आचरण रहित विचार कितने ही अच्छे क्यों न हों, उन्हें खोटे मोती की तरह समझना चाहिए।

– महात्मा गांधी

शुचिता की खातिर

लोकतंत्र में किसी भी चुनाव की शुचिता इस बात पर निर्भर करती है कि जनप्रतिनिधि के चयन की प्रक्रिया कितनी संवैधानिक, निष्पक्ष और पारदर्शी है। यह तभी सुनिश्चित हो पाता है, जब मतदाता चुनाव में मतदान की वास्तविक पात्रता रखते हों और तमाम चुनावी कार्य स्वतंत्र तरीके से संपन्न कराए जाएं। इसकी जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग पर होती है और वह समय-समय पर मतदाता सूची में संशोधन करता रहता है, ताकि जो व्यक्ति मतदान के लिए पात्र नहीं है या जिनका निधन हो चुका है, उनके नाम सूची से हटा दिए जाएं। विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआइआर भी इसी प्रकिया का हिस्सा है, मगर इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि कुछ राज्यों में पिछले दिनों इसे लेकर कई तरह के विवाद खड़े हो गए। यहां तक कि इसके औचित्य पर भी सवाल उठाए गए। इस पर सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को अपने फैसले में कहा कि निर्वाचन आयोग को एसआइआर कराने का पूरा अधिकार है और यह प्रक्रिया निष्पक्ष चुनावों के संवैधानिक दायित्व में जान फूंकती है। स्वतंत्र और पारदर्शी तरीके से चुनाव की अनिवार्यता को आगे बढ़ाने में यह महत्त्वपूर्ण कड़ी है।

गौरतलब है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पूर्व राज्य में शुरू किए गए विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर सबसे पहले सवाल उठे थे। विपक्षी दलों ने इस प्रक्रिया के समय को लेकर प्रश्न उठाया था। उनका कहना था कि चुनाव से ठीक पहले ही यह प्रक्रिया क्यों शुरू की गई, जबकि निर्वाचन आयोग इसे एक साल पूर्व भी करवा सकता था। इसके बाद आधार कार्ड को नागरिकता का प्रमाणपत्र स्वीकार नहीं करने को लेकर भी विवाद हुआ, जो सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचा और अंततः निर्वाचन आयोग को इस मामले में अपने कदम पीछे खींचने पड़े। इसके बाद सवालों का यह सिलसिला उत्तर प्रदेश से होते हुए पश्चिम बंगाल तक पहुंचा और शीर्ष अदालत को फिर इसमें दखल देना पड़ा। बिहार में एसआइआर को चुनौती देने वाली कई याचिकाएं दायर की गई थीं, जिनका निपटारा करते हुए न्यायालय ने कहा कि निर्वाचन आयोग को संविधान के अनुच्छेद 324 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम (आरपीए) की धारा 21(3) के तहत विशेष पुनरीक्षण करने का अधिकार प्राप्त है।

शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में यह भी कहा कि मतदाता सूची से नाम हटाना इस बात की कानूनी घोषणा नहीं है कि कोई व्यक्ति इस देश का नागरिक नहीं है। इससे उन लोगों को निश्चित तौर पर राहत मिली है, जिनके नाम तकनीकी कारणों से मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं और अब उन्हें इस बात की चिंता सताने लगी है कि कहीं आगे चलकर उनकी नागरिकता खतरे में न पड़ जाए। यह बात सच है कि चुनावों की शुचिता को बरकरार रखने के लिए मतदाता सूची में संशोधन जरूरी है, लेकिन कोई पात्र व्यक्ति तकनीकी कारणों से मताधिकार से वंचित न हो, इसकी जिम्मेदारी भी निर्वाचन आयोग की ही है। पिछले दिनों बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनावों में जिस तरह से लाखों लोग मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के बाद मतदान नहीं कर पाए, वह वास्तव में चिंताजनक है। हालांकि, मताधिकार से वंचित होने की स्थिति रोकने के लिए शीर्ष अदालत ने निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया है कि नागरिकता के आधार पर हटाए गए सभी नामों के मामलों को चार सप्ताह के भीतर सक्षम प्राधिकारी के पास भेजा जाए और उन्हें अगले विधानसभा या स्थानीय निकाय चुनावों से पहले अपना निर्णय देना होगा।

नशे का जाल

देश में नशीले पदार्थों का बढ़ता काला कारोबार एक गंभीर समस्या बन गया है। शहरों से लेकर गांवों तक इसका जाल तेजी से फैल रहा है। विदेश से भी बड़े पैमाने पर जमीन और समुद्र के रास्ते नशीले पदार्थों की तस्करी का सिलसिला बदस्तूर जारी है। हाल ही में तटरक्षक बल और गुजरात आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) ने संयुक्त अभियान में मुंद्रा तट पर एक जहाज से करीब 1,150 करोड़ रुपए का नशीला पदार्थ जब्त किया है। सवाल है कि गुजरात नशीले पदार्थ का पारगमन केंद्र क्यों बनता जा रहा है? राज्य में पिछले कुछ वर्षों से सुरक्षा बल इस तरह की गतिविधियों के खिलाफ लगातार अभियान चला रहे हैं। इसके बावजूद अगर समुद्री मार्ग से नशीले पदार्थों की तस्करी पर लगाम नहीं लग पा रही है, तो इसकी क्या वजह हो सकती है। सुरक्षा एजंसियां आखिर उन लोगों तक क्यों नहीं पहुंच पाती हैं, जो इतने बड़े पैमाने पर समुद्री मार्ग से नशीले पदार्थों की तस्करी करते हैं और उसे देश के विभिन्न हिस्सों में पहुंचाते हैं।

गौरतलब है कि गुजरात के मुंद्रा तट पर यह पहली बार नहीं है, जब समुद्र के रास्ते लाई गई नशीले पदार्थों की बड़ी खेप पकड़ी गई है। वर्ष 2021 में तो इक्कीस हजार करोड़ रुपए के तीन हजार किलो नशीले पदार्थ यहां जब्त किए गए थे। उस समय यह सबसे बड़ी बरामदगी बताई गई थी। उसके बाद ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि इतनी बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थों की खेप मंगाता कौन है? इसकी व्यापक रूप से जांच किए जाने की जरूरत है, ताकि दोषियों को न्याय के कठघरे में लाया जा सके। गुजरात के लिए सबसे बड़ी चुनौती उसकी लंबी तटरेखा है और बड़ी संख्या में पंजीकृत छोटे जहाजों और नावों की निगरानी करने के लिए माकूल व्यवस्था का होना बेहद जरूरी है। व्यापार और सुरक्षा के लिहाज से यह तटरेखा संवेदनशील है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि उन संगठित गिरोहों पर शिकंजा कसा जाए, जो विदेश से तस्करी के जरिए देश में नशे का जाल फैला रहे हैं।

दुर्लभ खनिज और साझा हित

भारत और अमेरिका ने दुर्लभ खनिजों की आपूर्ति सुरक्षित करने के लिए अहम समझौते किए हैं। मगर इसमें परस्पर हितों का ख्याल रखा जाना बेहद जरूरी है।

पुष्परंजन

भारत और अमेरिका ने जरूरी खनिजों एवं दुर्लभ धातुओं की आपूर्ति सुरक्षित करने के लिए अहम समझौते किए हैं, जिसमें उनका खनन और प्रसंस्करण भी शामिल है। इन समझौतों पर बीते मंगलवार को नई दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिका में उनके समकक्ष मार्को रूबियो ने हस्ताक्षर किए। रूबियो चार दिन की भारत यात्रा पर थे। उनकी इस यात्रा के आखिरी दिन 'क्वाड' (जिसमें अमेरिका, जापान, आस्ट्रेलिया और भारत शामिल हैं) के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। भारतीय विदेश मंत्रालय ने उसी दिन अलग से क्वाड देशों के बीच जरूरी खनिजों की आपूर्ति को लेकर एक रूपरेखा की घोषणा की। इसके साथ भारत के दुर्लभ एवं जरूरी खनिजों के भंडार के बारे में भी जानकारी साझा की गई। भारत-अमेरिका के बीच यह समझौता अहम हो सकता है, लेकिन इसमें परस्पर हितों का ख्याल रखा जाना बेहद जरूरी है।

एक कामयाब यात्रा का सेहरा बांध कर अमेरिका के विदेश मंत्री अपने वतन लौटे हैं। इस तरह अमेरिका ने क्वाड देशों के साथ चर्चा कर अपने लिए दुर्लभ खनिजों की आपूर्ति सुनिश्चित करने का प्रयास किया है। यह बेहद महत्त्वपूर्ण है, लेकिन कई दृष्टि से विचारणीय भी है। भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से जारी दस्तावेज में कहा गया कि क्वाड देशों की सरकारें और निजी कंपनियां इस पहल के लिए ऋण गारंटी, सबसिडी और दीर्घकालिक खरीद समझौतों का उपयोग करते हुए बीस अरब डालर जुटाने का इरादा रखती हैं। इन देशों का उद्देश्य इस धन को खनन, प्रसंस्करण और पुनर्चक्रण परियोजनाओं में लगाना है, ताकि महत्त्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति पर उनकी निर्भरता कम हो सके।

'दुर्लभ खनिज' क्या हैं और वे इतने महत्त्वपूर्ण क्यों हैं? इसका जवाब है कि ये ऐसे गैर-ईंधन खनिज हैं, जिनका उपयोग बैटरी, घड़ियां, वायरिंग, सैन्य हार्डवेयर, सेमीकंडक्टर और अन्य तकनीकी उत्पाद बनाने के लिए किया जाता है। जरूरी खनिजों में 17 दुर्लभ खनिज तत्त्व शामिल हैं, जिनमें लैंथेनाइड (धात्विक तत्व), स्कैंडियम और यट्रियम की मांग सबसे अधिक है। स्कैंडियम का उपयोग एअरोस्पेस और खेल उपकरण बनाने में किया जाता है। यट्रियम का उपयोग लेजर और सिरेमिक के निर्माण में होता है। लैंथेनाइड, उच्च तापमान वाले स्थायी चुंबक बनाने में इस्तेमाल होता है, जो इलेक्ट्रिक वाहनों और पवन चक्कियों के काम आता है।

गौरतलब है कि निकल, कोबाल्ट, लिथियम, एल्युमीनियम और जिंक सबसे जरूरी खनिजों में से हैं। अमेरिका बारह जरूरी खनिजों के लिए पूरी तरह से आयात पर निर्भर है। वह 29 अन्य जरूरी खनिजों के लिए अपनी जरूरत का कम से कम आधा हिस्सा आयात करता है। उसकी आर्थिक या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी दुर्लभ खनिजों के आयात में कोई अड़चन न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए अमेरिका हरसंभव प्रयास कर रहा है। दुर्लभ खनिजों का उपयोग हार्डवेयर के उन मुख्य घटकों में भी किया जाता है, जो सेमीकंडक्टर और कृत्रिम मेधा (एआइ) तकनीकों में काम आते हैं। चीन के पास इनमें से बारह खनिजों के भंडार हैं। दुर्लभ खनिजों के प्रसंस्करण की लागत बहुत ज्यादा होती है और इनके खनन में भी भारी मात्रा में रसायनों का इस्तेमाल होता है, जिससे जहरीला

कचरा पैदा होता है। फिलहाल, दुनिया में दुर्लभ खनिजों की ज्यादातर आपूर्ति पर चीन का नियंत्रण है। इन खनिजों का साठ फीसद हिस्सा चीन के पास है और वह दुनिया की कुल आपूर्ति का नब्बे फीसद हिस्से को उपयोग के लायक बनाता है। अमेरिका और दूसरे देश इन खनिजों के लिए चीन पर अधिक निर्भर हैं। अमेरिका ने खास तौर पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में चीन पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए इन खनिजों के अन्य आपूर्तिकर्ताओं की पहचान करने पर जोर दिया है। अब सवाल है कि भारत के पास कौन से दुर्लभ खनिज हैं? जुलाई, 2023 में भारत ने तीस खनिजों की एक सूची जारी की थी, जिसमें बेरिलियम, बिस्मथ, कोबाल्ट, तांबा, गैलियम, जर्मेनियम, ग्रेफाइट, हैफनियम, लिथियम, मोलिब्डेनम, नाइओबियम, निकल, प्लैटिनम समूह के तत्त्व, फास्फोरस, पोटाश के अलावा दुर्लभ मृदा तत्व- रेनियम, सिलिकान, स्ट्रोंटियम, टैंटलम, टेल्यूरियम, टिन, टाइटेनियम, टंगस्टन, वैनेडियम, जिरकोनियम, सेलेनियम और कैडमियम का ब्योरा दिया गया था। बताया गया है कि भारत के पास एक करोड़ तीस लाख टन से ज्यादा मोनाजाइट है। यह एक फास्फेट खनिज है, जिसमें दुर्लभ आक्साइड होते हैं और यह दुर्लभ खनिजों के मुख्य प्राकृतिक स्रोतों में से एक है।

> वर्ष 2026-2027 के बजट में सरकार ने ओड़ीशा, केरलम, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में 'दुर्लभ खनिज गलियारे' बनाने के लिए नए नीतिगत उपाय पेश किए हैं। मगर सवाल है कि यह सब हमें खुद करना था या इसे किसी दूसरे देश के सुपुर्द करना था? इसमें दोराय नहीं कि अमेरिका सबसे पहले अपने हित देखता है। अगर इस मामले में क्वाड देश शामिल हैं, तो बहुपक्षीय सहमति के बावजूद केवल भारत और अमेरिका के बीच ही द्विपक्षीय समझौते पर जोर क्यों दिया गया? वास्तव में अमेरिका दुर्लभ खनिजों की आपूर्ति में चीन के दबदबे को खत्म करना चाहता है, लेकिन इसमें भारत को अपने हित सुरक्षित रखने होंगे।

सरकार का अनुमान है कि देश के मोनाजाइट भंडार में सत्तर लाख टन से अधिक दुर्लभ मृदा आक्साइड (आरइओएस) मौजूद हैं। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट बताती है कि चीन के भंडार में लगभग चार करोड़ चालीस लाख टन आरइओएस मौजूद है और यह दुनिया के ज्ञात भंडारों का लगभग आधा हिस्सा है। वर्ष 2026-2027 के बजट में सरकार ने ओड़ीशा, केरलम, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में 'दुर्लभ खनिज गलियारे' बनाने के लिए नए नीतिगत उपाय पेश किए हैं। ये दुर्लभ खनिजों के खनन एवं प्रसंस्करण, अनुसंधान करने और इलेक्ट्रिक वाहनों, पवनचक्की तथा अन्य उन्नत तकनीकों में उपयोग होने वाले उच्च-प्रदर्शन वाले दुर्लभ चुंबकों के निर्माण के केंद्र होंगे। मगर सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह सब हमें खुद करना था या इसे किसी दूसरे देश के सुपुर्द करना था? इसमें दोराय नहीं कि अमेरिका सबसे पहले अपने हित देखता है। अगर क्वाड देश इसमें शामिल हैं, तो बहुपक्षीय सहमति के बावजूद केवल भारत और अमेरिका के बीच ही द्विपक्षीय समझौते पर जोर क्यों दिया गया?

हाल में अमेरिका ने दक्षिण अफ्रीका में 'फलाबोर्वा रेयरअर्थ्स प्रोजेक्ट' में निवेश का एलान किया था। इससे पहले दिसंबर, 2025 में अमेरिका ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में अहम खनिजों के खनन में 1.25 अरब डालर के निवेश की घोषणा की थी। फरवरी 2026 में उसने अहम खनिजों पर 'पैक्स सिलिका पहल' की थी, जिसमें उसने अर्जेंटीना, कुक आइलैंड्स, इक्वाडोर, गिनी, मोरक्को, पैराग्वे, पेरू, फिलीपींस, संयुक्त अरब अमीरात, ब्रिटेन और उज्बेकिस्तान के साथ अहम खनिजों से जुड़े ग्यारह समझौते किए थे। अब भारत के दुर्लभ खनिज गलियारे पर भी उसकी नजर है। हालांकि, भारत का कहना है कि अमेरिका के साथ समझौता के जरिए दुर्लभ खनिजों की आपूर्ति में सहयोग को और गहरा करना है। चीन के दबदबे को चुनौती देने के लिए अमेरिका ने जापान और भारत जैसे देशों के साथ अहम समझौते किए हैं।

बहरहाल, भारत के पास दुर्लभ खनिजों का विशाल भंडार है, जो उद्योगों के लिए एक मजबूत नींव प्रदान करता है। देश के पास एक करोड़ तीस लाख टन से अधिक मोनाजाइट है, जिसमें अनुमानित सत्तर लाख टन से ज्यादा दुर्लभ आक्साइड शामिल हैं। ये भंडार ओड़ीशा, केरलम, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और झारखंड में पाए जाते हैं। ये सभी भंडार मिल कर एक एकीकृत विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र की स्थापना का समर्थन करने के लिए भारत के कच्चे माल के आधार को मजबूत करते हैं। ऐसे में जरूरी है कि किसी भी देश से एकपक्षीय समझौते के बजाय परस्पर हितों को ध्यान में रखकर सहयोग की रणनीति तय की जाए।

भावना का एहसास

शोभा जैन

असंतोष और प्रतिरोध समाज में स्वतः साथ चलने वाला अयाचित भाव है। ऐसे में भावनाओं का आहत होना भी एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। भावनात्मक अनुपस्थिति हमेशा शारीरिक अनुपस्थिति नहीं होती, लेकिन वह शारीरिक से कहीं अधिक गहरी और निपुण होती है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कई बार ऐसे क्षण आते हैं, जब हम बिना किसी रिश्ते, परिचय या पहचान के भी कुछ दृश्य देखकर भावुक हो जाते हैं। वे दृश्य भले ही सड़क पर निकलती किसी की शव यात्रा का हो, किसी बच्चे का गुब्बारा न खरीद पाने का रुदन या चिलचिलाती धूप में सड़क किनारे नंगे पैर घूमते मासूम बच्चे, जो किसी चमचमाती कार का कांच अचानक साफ करने लगते हैं। भावुक व्यक्ति कभी सुविधा से चयन करने वाला नहीं होता, वह सूखी नदी या बंजर खेत देखकर भी उतना ही दुखी हो सकता है, जितना गर्मी के दिनों में दो-दिन घर में पानी न आने पर। भावनात्मक होना एक शुद्ध व्यक्ति की पहचान है, इसलिए भावना के हर शब्द नवजात होते हैं। नवजात का हृदय निश्छल पवित्र होता है।

हमारे सामूहिक मानस में स्वीकार्य यथार्थ होना तो भावनात्मक स्तर का होना चाहिए, लेकिन इसके उलट अब स्वीकार्य यथार्थ से भावनाओं का दूर-दूर तक कोई लेना-देना नहीं होता। कहने का आशय यह कि बात छोटी या बड़ी नहीं होती। छोटी या बड़ी होती है भावना। शब्द सामने आ जाते हैं, भावना पीछे रह जाती है। इसीलिए दुनिया में शब्दों की लड़ाई चलती है। याद रखना होगा कि भावना का हर तत्त्व नवजात है। वह कभी पुनरावृत्ति में जन्म नहीं लेती। भाव एक अचेतन तीव्रता का अनुभव है। हालांकि भावना और प्रभाव का प्रयोग अक्सर एक-दूसरे के स्थान पर किया जाता है, लेकिन प्रभाव को भावनाओं और संवेगों से भ्रमित न करना महत्त्वपूर्ण है।

आज लोगों की भावना सुविधा के मुताबिक हो गई है। वे सड़क पर घुमाते अपने कुत्ते के लिए तो संवेदनशील होते हैं, भावनात्मक भी, लेकिन दूसरों के बच्चों या सड़क के अन्य जीव के प्रति उनकी कोई प्रतिक्रिया भावनात्मक स्तर पर सतही नजर आती है। हम बात भावनाओं की कर रहे हैं, लेकिन अब जो शब्द खबरों और बातचीत में गूंजते हैं- बलात्कार, हत्या, जनसंहार, आत्महत्या, भीड़-हत्या, दहेज हत्या, बाल शोषण, मानव तस्करी, आतंकवाद, अपहरण आदि, वे हमारी भावनाओं को कितना आहत करते हैं? घटनाओं का अतिरेक हमारी भावनाओं को शोर में तब्दील कर रहा है, इसलिए हम दोनों के अंतर को समझना भी भूल रहे।

हम अपने मानस में बहुत कुछ ऐसा स्वीकारने के आदी हो चले हैं, जो मनुष्य होने पर भी संशय करता है। स्वीकार्यता में भावनात्मक अभिव्यक्ति कितनी होगी, यह विचारणीय है। भावना किसी अनुभूति का प्रकटीकरण या प्रदर्शन है। हम अपनी भावनाओं को दुनिया के सामने प्रकट करते हैं। कभी-कभी यह प्रकटीकरण हमारी आंतरिक स्थिति की अभिव्यक्ति होती है और कभी-कभी सामाजिक अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए बनावटी होती है। भाव की संप्रेषणीयता ही इसे एक शक्तिशाली सामाजिक शक्ति बनाती है। एक व्यक्ति की भावनाएं दूसरे की भावनाएं बन जाए, यह बहुत हद तक संभव नहीं, लेकिन एक की भावनाएं दूसरे तक पहुंचती जरूर हैं। समाज इसी समझ से संवेदन-तत्त्व को स्पर्श करता है।

जीवन में बढ़ते हुए दो शब्द और जुड़ते हैं। आशावाद कह लें या आदर्शीकरण- यही वह प्राणतत्त्व है, जो मनुष्य के स्थिर यथार्थ के भीतर रोम छिद्रों की तरह मौजूद गतिशील, परिवर्तनशील स्वरूप से जोड़ता है और इस प्रकार उसके उन्नत पक्ष को विस्तार देता है। मगर इसके केंद्र में उसकी भावनाएं निहित हैं। संवेदना, कल्पना, दृष्टि, बोध, तड़प, बेचैनी, निराशा-उम्मीद और व्यग्रता- ये सभी भावनाओं को आकार देने वाले संसाधन हैं। वयस्क लोगों के जीवन में भावनाएं कितने सार्थक रूप से काम करती रहती हैं! यहां तक कि उनके द्वारा अपनी भावनाओं पर कुछ हद तक सचेत नियंत्रण का प्रभाव भी रहता है। एक शिशु में संवेदनाओं को समझने के लिए भाषा कौशल नहीं होते, न ही उसके पास पिछले अनुभवों का कोई इतिहास होता है, फिर भी वह भावनाएं अभिव्यक्त करता है और उसकी भावनाएं पहुंचती हैं।

सच तो यह है कि शब्द जब मुड़कर अपनी तरफ देखता है, तो विचार बन जाता है। उस विचार की भावनाओं को हम उसकी नैसर्गिक क्रांति में देख पाते हैं। साहित्य सृजन की किसी भी विधा में उसकी नैसर्गिक क्रांति में देख पाते हैं। भावनाएं या तो नैतिक तनाव में आकार लेती हैं या बहुत संवेदनशील क्षण में, जहां व्यक्ति अपनी चुप्पी और बोलने की विवशता के बीच खड़ा दिखाई देता है। भावनाओं के निश्छल प्रवाह में आवेग हो, तो धाराओं का और संयम हो, तो तटों का। व्यक्ति की पीड़ा और आकांक्षा, किसी भी सर्जक की निजी न होकर एक बड़े सांस्कृतिक आख्यान का हिस्सा बन जाती है। व्यक्ति किसी भव्य अतीत को स्मृति में स्वयं को बसाए या अपने विराट वर्तमान की खोह में, बिना भावनाओं के वह मनुष्य नहीं है।

जीवन की विफलताएं, कमजोरियां संघर्ष हमारी साधना का रहस्य हैं। व्यक्ति इनसे आहत भी होता है, लेकिन उस आहत होने का केंद्रीय भाव भावनात्मक ही है। बस वे भावनाएं इनके घटित होने पर कौन-सी दिशा की लय पकड़ती है, यह समय पर निर्भर है। कुछ लोग आहत होने पर अपराध की दुनिया चुनते हैं, कुछ दूसरों के साथ ऐसा न हो, ऐसा कुछ करते हैं। दोनों के केंद्र में भावनाएं ही हैं। वक्त के साथ वक्त की अंगुली पकड़ कर वक्त की तरह चाल चलने की बाध्यता निरंतर इसकी गति-दिशा-लक्ष्य निर्धारित करती चलती है और इससे जुड़ी उसकी कोई भी नियति व्यक्तियों के सचेष्ट प्रयासों का परिणाम है।

दुनिया मेरे आगे

> भावुक व्यक्ति कभी सुविधा से चयन करने वाला नहीं होता, वह सूखी नदी या बंजर खेत देखकर भी उतना ही दुखी हो सकता है, जितना गर्मी के दिनों में दो-दिन घर में पानी न आने पर। भावनात्मक होना एक शुद्ध व्यक्ति की पहचान है, इसलिए भावना के हर शब्द नवजात होते हैं।

लोकतंत्र में असहमति

हाल ही में सोशल मीडिया पर चर्चा में आई 'काकरोच जनता पार्टी' (सीजेपी) को केवल एक हास्य-व्यंग्य मान कर सिरे से खारिज कर देना उचित नहीं होगा। इतिहास बताता है कि समाज में जब असंतोष, निराशा या व्यवस्था के प्रति अविश्वास बढ़ता है, तब उसकी अभिव्यक्ति अनेक रूपों में सामने आती है। कभी वह आंदोलन का रूप लेती है, कभी साहित्य और कला में दिखाई देती है, तो कभी व्यंग्य और डिजिटल अभियानों के रूप में उभरती है। सीजेपी के बढ़ते समर्थक इस बात का संकेत हो सकते हैं कि समाज का एक वर्ग अपनी बात पारंपरिक मंचों पर प्रभावी ढंग से नहीं रख पा रहा है और इसलिए वह प्रतीकात्मक तथा रचनात्मक माध्यमों का सहारा ले रहा है। यह लोकतंत्र की एक विशेषता भी है कि नागरिक शांतिपूर्ण तरीके से हास्य और व्यंग्य के माध्यम से अपनी असहमति व्यक्त कर सकते हैं। हालांकि, किसी भी आक्रोश की अभिव्यक्ति को सकारात्मक दिशा देना आवश्यक है। यदि असंतोष केवल उपहास या नकारात्मकता तक सीमित रह जाए, तो उसका रचनात्मक परिणाम नहीं निकलता।

– ओपी चौधरी, सनसिटी, रतलाम

आवाज का दमन

बिहार की राजनीति में बहाली अब एक उम्मीद नहीं, बल्कि एक चक्रव्यूह है। हाल ही में जिस तरह युवाओं पर लाठियां चलीं, वह इस बात का प्रमाण है कि सत्तारूढ़ दल के लिए नौजवान केवल वोट बैंक हैं। बिहार की धरती, जो कभी ज्ञान और क्रांति का केंद्र थी, आज वहां युवाओं के उत्पीड़न का कुचक्र चल रहा है। शिक्षक अभ्यर्थियों के मामले में अपने अधिकार की मांग करने पर जिस तरह बर्बरता से लाठियां बरसाई गई हैं, उससे रोजगार देने के वादे की कलई खुल गई है। यह केवल 'लाठीचार्ज' नहीं है, बल्कि बिहार के भविष्य और युवाओं के आत्मसम्मान पर प्रहार है। जो युवा कल समाज को शिक्षा देने का दायित्व संभालने वाले थे, आज वे शासन और प्रशासन की संवेदनहीनता का शिकार हो रहे हैं। सरकार को यह समझना होगा कि युवा शक्ति की आवाज को लाठी के सहारे दबाने के बजाय उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है।

– प्रसिद्ध यादव, फुलवारी, पटना

पर्यावरण की फिक्र

वैश्विक स्तर पर मौसम और हवा की गुणवत्ता जांचने वाली संस्था 'एक्यूआइ' ने हाल ही में तापमान बढ़ने संबंधी जो आंकड़ा पेश किया है, वह हम सभी के लिए चिंता का विषय है। इन आंकड़ों में बताया गया है कि भारत के लगभग पचास शहरों का तापमान सबसे ज्यादा है। ये आंकड़े बताते हैं कि हम वन संपदा के प्रति लापरवाह हो गए हैं। हम उनका संरक्षण करने के बजाय उन्हें लगातार बर्बाद कर रहे हैं। ग्रीष्म ऋतु में गर्मी से राहत पाने के लिए लोग शिमला जैसे ठंडे क्षेत्रों का रुख करते हैं, लेकिन गंभीर बात यह है कि पहाड़ भी अब तपने लगे हैं। अगर धरती पर इसी तरह तापमान बढ़ता गया, तो वह दिन दूर नहीं है जब ठंडे पहाड़ भी गर्म होते चले जाएंगे। इन परिस्थितियों के बावजूद अब भी हमने प्रकृति को संभालने और सहेजने के लिए गंभीरता नहीं दिखाई, तो भीषण गर्मी समूचे प्राणियों के अस्तित्व के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकती है।

– राजेश कुमार चौहान, जलंधर

घुसपैठ के विरुद्ध

देश की सुरक्षा, सामाजिक संतुलन और लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए घुसपैठ को रोकना होगा। सीमावर्ती राज्यों, विशेषकर पश्चिम बंगाल और असम में बांग्लादेश से घुसपैठ का मुद्दा राजनीतिक एवं सामाजिक बहस का विषय रहा है। अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने वाले लोगों की पहचान कर उन्हें वापस भेजने की प्रक्रिया आसान नहीं है। फिर भी राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक कदम माना जा रहा है। घुसपैठ केवल जनसंख्या दबाव का प्रश्न नहीं, बल्कि सुरक्षा, संसाधनों पर भार और चुनावी व्यवस्था को प्रभावित करने वाला विषय भी है। फर्जी दस्तावेजों से नागरिकता और मतदाता पहचान पत्र प्राप्त कर लेना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। इसीलिए इस मुद्दे पर सभी दलों को एक साथ आना चाहिए, ताकि घुसपैठियों पर कार्रवाई हो सके।

– हिमांशु शेखर, गयाजी

लोकमानस

loksatta@expressindia.com

आकड्यांपेक्षा उत्तरदायित्व महत्त्वाचे !

'चौथा 'फ'!' हा अग्रलेख (२७ मे) वाचला. अर्थव्यवस्थेपुढील आव्हाने म्हणून इंधन, खते आणि परकीय चलनाची चर्चा वारंवार होते, परंतु हे केवळ वरवरचे तांत्रिक आणि प्रशासकीय अडथळे आहेत, ज्यांवर आज ना उद्या योग्य धोरणांच्या माध्यमातून मार्ग काढता येऊ शकतो. मात्र या सर्वांवर कडी करणारा जो चौथा 'फ'- 'फसवणुकी'चा आहे, तोच आजच्या व्यवस्थेचा खरा आजार आहे. तोच आत्मवंचनेचा मूळ गाभा वाटतो.

इंधनावरील करातून होणारी नफेखोरी, अनुदानाच्या मृगजळात अडकवलेला बळीराजा आणि परकीय गुंतवणुकीतील धोरणात्मक धरसोड या गोष्टी केवळ आर्थिक अपयश दर्शवत नाहीत, तर हे व्यवस्थेची संवेदनशीलता हरवल्याचे लक्षण आहेत. याहूनही सर्वात भयंकर बाब म्हणजे आभास निर्मितीची वाढती प्रवृत्ती. आपणच जगात सर्वांत वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था आहोत, असा आभास निर्माण करणे आणि सत्तेत बसलेल्यांनी स्वतःच त्या भ्रमात जगणे, हा आत्मवंचनेचा कळस आहे.

जेव्हा वास्तवाचे भान हरपून केवळ स्वप्नांचा व्यापार सुरू होतो, तेव्हा लोकशाहीचा मूळ पायाच ढासळू लागतो. चौथा 'फ' फसवणूक ही केवळ सत्तेची देणगी नाही. तिचे मूळ समाजाच्या स्वतःच्याच प्रवृत्तीत आहे. लोकशाहीत 'सत्ता आणि सामान्य माणूस' यांच्यात एक अलिखित, पवित्र नैतिक करार असतो. सामान्य माणसाचे रोजचे जगणे हे कोणत्याही जागतिक स्तरावरील कागदी आकडेवारीवर नाही, तर बेरोजगारी आणि महागाईच्या दाहक वास्तवावर आधारलेले असते. त्यामुळे समाजातील आर्थिक प्रश्न हे केवळ आकड्यांचे खेळ कधीच असू शकत नाहीत, तर ते सत्तेच्या नैतिकतेचे आणि उत्तरदायित्वाचे निदर्शक असतात. विकासाच्या चकचकीत आवरणाखाली हाच नैतिक करार आज आतून पोखरला गेला आहे, हेच वास्तव आणि अंतिम सत्य म्हणून स्वीकारावे लागेल.

■ **संदीप देवरे,** मुंबई

रोडावलेली बचत, बोकाळलेला चंगळवाद

'चौथा 'फ'!' हा अग्रलेख (२७ मे) वाचला. २००६ मध्ये भारतावर आर्थिक अरिष्ट आले होते तेव्हा सर्वसामान्यांकडे असलेल्या बचतीने त्यांना तारले होते. पूर्वी प्राप्तिकर वाचतो म्हणून गुंतवणूक केली जात असे. पण आता केलेल्या गुंतवणुकीवर प्राप्तिकरात सूट मिळत नसल्याने देशातली बचतही रोडावत चालली आहे. सरकारच सांगत आहे कर भरा, बचत करू नका. त्यामुळे देशातील तरुणवर्ग चंगळवादी झाला आहे. उद्या मिळणारे पैसे आजच खर्चून मोकळा होतो आहे. सहज मिळणाऱ्या क्रेडिट कार्डमुळे चैनीच्या वस्तू खरेदी करणे सोपे झाले आहे. विश्वगुरू ज्या वेळी झोला उचलून निघून जातील, तोवर जनता देशोधडीला लागलेली असेल, असेच भारताची आजची अवस्था पाहता वाटते. देशाची अवस्था कधी नव्हे इतकी वाईट झाली आहे, देश अनागोंदीच्या काठावर उभा आहे, तरी चौथा 'फ' भक्तांकडून पूर्ण शक्तीनिशी रेटला जात आहे, याचे आश्चर्य वाटते.

■ **धनराज खरटमल,** मुलुंड (मुंबई)

फुगवलेल्या दाव्यांचे वास्तव

'चौथा 'फ'!' (दि.२७) हा अग्रलेख वाचला. गेल्या काही वर्षांत घोषणाबाजी, जाहिरातबाजी आणि प्रतिमानिर्मितीला महत्त्व दिले जात असून त्यामुळे वास्तवातील आर्थिक प्रश्नांकडे दुर्लक्ष होत आहे. आर्थिक प्रगतीचे दावे करताना बेरोजगारी, महागाई, शेतकऱ्यांची ओढाताण, वाढती आर्थिक विषमता यांसारख्या मूलभूत प्रश्नांची उत्तरे सरकारने देणेही तितकेच आवश्यक आहे. लोकशाही व्यवस्थेत सरकारवर प्रश्न उपस्थित करणे ही माध्यमांची आणि सजग नागरिकांची जबाबदारी आहे. केवळ आश्वासने आणि घोषणांवर अर्थव्यवस्था मजबूत होत नाही; त्यासाठी दीर्घकालीन नियोजन, पारदर्शकता आणि वास्तवाचे भान आवश्यक असते. 'मेक इन इंडिया'च्या गजरामुळे चीनमधून उद्योग भारतात येतील अशी स्वप्ने रंगवली गेली; परंतु प्रत्यक्षात अनेक उद्योगांनी व्हिएतनाम आणि मलेशियाची वाट धरली. मग घोषणांचे फुगे आकाशात तरंगत राहिले आणि वास्तव जमिनीवरच पडून राहिले.

■ **डॉ. राजेंद्र तांबिले,** सातारा

सरकारच्या धोरणांबद्दल भ्रमनिरास

'चौथा 'फ'!' हा अग्रलेख (२७ मे) वाचला. मोदी सरकारच्या धोरणांविषयी आजवर वाटणारा आशावाद आता फोल ठरू लागला आहे. या तीन 'फ' च्या बाबतीत सरकारची खरोखरच 'फ'सगत झाली आहे. हळूहळू विद्यमान केंद्र सरकारबद्दल आणि सरकारच्या धोरणांबद्दल भ्रमनिरास होऊ लागला आहे. विरोधी पक्षातही आनंदी आनंदच आहे. एकूणच 'आपुलाची वाद आपणाशी' अशी अवस्था आहे.

■ **सुबोध गद्रे,** कोल्हापूर

कंपन्यांना नफा मिळतो कसा?

'चौथा 'फ'!' हा अग्रलेख (२७ मे) वाचला. आंतरराष्ट्रीय बाजारात इंधनांचे दर वाढले की ग्राहकास वाढीव दर आकारले जातात, मग इंधन स्वस्त झाल्यावर ग्राहकास इंधन स्वस्त दरात मिळणे आवश्यक नाही का? एकीकडे तेल कंपन्या आपल्या वार्षिक ताळेबंदात प्रचंड प्रमाणात नफा दाखवतात, मग तोट्यात तेल विक्री कशी होते, हे कळाले पाहिजे.

■ **शशिकांत कुलकर्णी,** नांदेड

'नीट'पेक्षा विद्वेष महत्त्वाचा?

'शिक्षणातील विषमतेचा 'नीट' आरसा' हा लेख वाचला. नीट परीक्षेतील घोळ हा अनितीला सत्ताधाऱ्यांकडून मिळणाऱ्या अनिष्ट प्रोत्साहनाचाच परिपाक आहे. विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्या भ्रष्ट व्यवस्थेचे हे प्रतिबिंब आहे. भ्रष्ट मार्गाने आपल्याला हवे ते आणि हवे तेव्हा मिळविता येते, असाच संदेश या प्रकरणातून गेल्याचे दिसते. प्रामाणिकपणे अभ्यास करून, परीक्षा देऊन प्रगती करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याऐवजी तरुणांची डोकी जाती व धर्मावरून भडकावली जात आहेत. विद्वेषाचे भयंकर विष पद्धतशीरपणे पसरविण्याचे काम दुष्ट शक्ती अविरतपणे आणि अगदी बेमालूमपणे पार पाडत आहेत! विकार आणि विखाराचे धडे जनतेला जाणूनबुजून दिले जात आहेत!

नीटमधील पेपरफुटीला सर्वस्वी 'एनटीए'च जबाबदार आहे. सुमार बुद्धीचा डॉक्टरपुत्र डॉक्टर कसा होतो, याचे उत्तर या प्रकरणाने दिले आहे. प्रामाणिक, होतकरू विद्यार्थ्यांवर अन्याय करणारा हा शिक्षण क्षेत्रातील महाप्रचंड भ्रष्टाचार हे केवळ हिमनगाचे टोक आहे की काय असा दाट संशय येतो. सर्वसामान्य, प्रामाणिक, होतकरू विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळण्याच्या या अत्यंत निंदनीय आणि संतापजनक प्रकाराची पाळेमुळे किती खोलवर रुजली असतील याची केवळ कल्पनाच केलेली बरी. संकुचित, कोत्या मनाचे भ्रष्ट सरकार, त्याचे भ्रष्ट, संकुचित विचार यांमुळे भ्रष्ट आचारविचाराचे जणू पेवच फुटले आहे. अशा या अंधारात आशावाद जोपासणे हाच तगून राहण्याचा मार्ग आहे. उद्याच्या परिवर्तनाची आस धरून चालावे लागणार आहे.

■ **श्रीकांत जाधव,** अतीत (सातारा)

इंधन आहे, तर रांगा कशामुळे?

'इंधन साठेबाजीवर कारवाईसाठी संयुक्त पथक, अन्न व नागरीपुरवठा, गृह विभागाकडून कारवाई', हे वृत्त (लोकसत्ता- २७ मे) वाचले. आखाती देशांतील युद्धाचा परिणाम म्हणून, वस्तूंची आयात निर्यात थांबली आहे. बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्याचा परिणाम म्हणून, पेट्रोल, डिझेलचे दर तीन वेळा वाढवण्यात आले. याचा त्रास वाहनचालकांना होत आहे. सरकार आपल्याकडे पेट्रोल, डिझेलचा पुरेसा साठा आहे, असे कंठशोष करून सांगत आहे, मात्र प्रत्यक्षात परिस्थिती वेगळीच आहे. साठा पुरेसा आहे तर, पेट्रोल पंपावर वाहनांच्या रांगा का आहेत. काही ठिकाणी तर, पेट्रोल, डिझेल संपले आहे, असे फलक लागले आहेत, ते कशामुळे? काही ठिकाणी पेट्रोल, डिझेल नाही असे सांगितल्यामुळे, वाहनचालकांकडून पेट्रोल, डिझेल भरणाऱ्या व्यक्तीला मारहाण होण्याचे प्रकार घडत आहेत. तीच गत स्वयंपाकाच्या गॅसची. सिलेंडरचा पुरेसा साठा आहे तर, जनतेला रांगा लावून का उभे राहावे लागत आहे? तसेच सिलेंडर मिळण्यासाठी १५ ते ४५ दिवसांचा कालावधी का लागत आहे? या प्रश्नांची उत्तरे सरकारने द्यायला हवीत. इंधन साठेबाजीमुळे जर हे प्रकार घडत असतील तर, ते रोखण्यासाठी संयुक्त पथक नेमावे आणि ते कामगिरी चोखपणे बजावेल, याची खबरदारी घ्यावी.

■ **गुरुनाथ मराठे,** बोरिवली (मुंबई)

दलितांचे पहिले छात्रालय आर्थिक विवंचनेत!

'हरिजन सेवक संघा'तर्फे संचालित 'राजेंद्र छात्रालया'ने अनेक विद्यार्थी घडवले. मुंबईचे पहिले दलित महापौर डॉ. पी. टी. बोराडे, सनदी अधिकारी भाई नगराळे, धुळ्याचे आजवरचे सात खासदार याच छात्रालयाचे माजी विद्यार्थी, मात्र आज हे छात्रालय भाड्याच्या इमारतीत सुरू ठेवावे लागत आहे. यात संस्थेची आर्थिक ओढाताण होत आहे...

देवेंद्र गावंडे
devendra.gawande@expressindia.com

गांधीमार्गाचे वर्तमान

हा प्रसंग ३१ जुलै १९३७ चा. एका न्यायालयीन खटल्याच्या निमित्ताने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर धुळ्याला आले होते. ही संधी साधून तिथल्या गांधीवाद्यांनी ठरवले, आंबेडकरांना 'हरिजन सेवक संघा'तर्फे संचालित 'राजेंद्र छात्रालय' दाखवायचेच. यासाठी पुढाकार घेतला ॲड. काकासाहेब बर्वेंनी. हे त्या काळचे निष्णात वकील. कामकाज संपल्यावर त्यांनी गळ घातली. आंबेडकर तयार झाले. सारे आनंदित होऊन बाहेर निघाले. त्यांच्यासाठी राखून ठेवलेला टांगा तिथेच होता, पण चालक बेपत्ता झालेला. चौकशी केल्यावर कळले की अस्पृश्य म्हणजे महार व्यक्तीला टांग्यात बसवले तर पाप लागेल म्हणून तो पसार झालेला. शेवटी नरसोपंत सौंदणकरांनी टांग्याचे सारथ्य केले. आंबेडकर छात्रालयात आले. त्यांनी सेवक संघाच्या कार्याची भरभरून स्तुती केली. तसा अभिप्राय लिहिला. आजही मागास समाजातील गरीब मुलांना शिक्षणाचे दार उघडून देणाऱ्या या छात्रालयाच्या निर्मितीची कथाही मोठी विलक्षण. सवर्णांचा जाच सहन करणाऱ्या दलितांना राजकारण तर सोडाच पण शिक्षण व नोकरी मिळवण्यासाठी किती कष्ट पडतात याची जाणीव महात्मा गांधींना पहिल्यांदा करून दिली ती आंबेडकरांनी. राखीव मतदारसंघाची मागणी हे त्यामागचे निमित्त. आधी वाद, मग चर्चा व शेवटी करार हे सारे घडले १९२२ ला. पुणे कराराच्या जन्माची कथा अशी. यामुळे व्यथित झालेल्या गांधींनी पुरे झाले राजकारण म्हणत हरिजन सेवा संघाची स्थापना केली.

छात्रालये, शाळा सुरू करा अशी हाक समर्थकांना दिली. त्याची साद पोहोचली थेट ॲड. बर्वेंच्या कानी. धुळे परिसरात १८९९ पासून अस्पृश्यता निवारण संघाच्या माध्यमातून दलितोद्धाराचे काम करणारे बर्वे एक छात्रालय चालवत होतेच. बर्वे, सौंदणकर व त्यांचे सर्व सहकारी ब्राह्मण. त्यांना प्रारंभी या कामासाठी ब्राह्मण वस्तीत कुणी जागा देईना. मग त्यांनी मुस्लीम वस्तीत ती शोधली. गावखेड्यातली दलित मुले गोळा करून धुळ्याला आणायची. चरख्यावर खादीचे सूत कातून त्याचे कपडे शिवून या मुलांना द्यायचे. त्यांचे अंघोळपाणी, जेवणाची व्यवस्था करायची व शिकवायचे. यामुळे हिंदूंच्या रोषाला पात्र ठरलेल्या बर्वेंनी त्याची फिकीर कधी केली नाही. गांधींचा आदेश येताच त्यांनी हे छात्रालय हरिजन सेवक संघाला सुपूर्द केले. हे राज्यातले पहिले छात्रालय. ३१ जुलै १९३५ ला राजेंद्र प्रसादांनी उद्घाटन केले तेव्हापासून याचे नाव झाले राजेंद्र छात्रालय. १९३९ ला कन्या छात्रालयाची सुरुवात झाली. आजवर या दोन्ही ठिकाणांहून पाच हजार मुले व साडेतीन हजार मुलींनी शिक्षण घेतले. दरवर्षी साडेतीनशे गरीब मुलेमुली येथे शिक्षणाच्या निमित्ताने दाखल होतात. १९३९ ला गांधींनी या छात्रालयाला भेट दिली. १९४० ला स्वातंत्र्यवीर सावरकरांनी.

भेटीनंतरचा सावरकर व आंबेडकरांचा अभिप्राय आजही वाचण्यासारखा. या दोघांनीही सेवक संघाचे व त्याला प्रेरणा देणाऱ्या गांधींचे कौतुक केलेले. खान्देशावर आजही साने गुरुजींचा प्रभाव. स्वातंत्र्याच्या लढ्यात विनोबा व गुरुजी बराच काळ धुळ्याच्या कारागृहात होते. तिथून सुटका झाल्यावर या दोघांनी याच छात्रालयात मुक्काम ठोकला. समाजाचे प्रबोधन हा दोघांच्याही कार्याचा भाग. मग काय, याच छात्रालयात विनोबा प्रवचन द्यायचे व साने गुरुजी ते लिहून घ्यायचे. गीताई जन्माला आली ती अशी. इतकी समृद्ध परंपरा लाभलेल्या या छात्रालयाने आजवर विद्यार्थीही तसेच घडवले. मुंबईचे पहिले दलित महापौर डॉ. पी. टी. बोराडे, सनदी अधिकारी भाई नगराळे. इतकेच काय तर धुळ्याचे आजवरचे सात खासदार याच छात्रालयाचे विद्यार्थी. स्वावलंबन हे या ठिकाणाचे मुख्य सूत्र. त्यामुळे एखादा विद्यार्थी जास्त शिकला नाही तरी रिकामा राहात नाही. शहरातले अनेक ऑटोचालक इथले विद्यार्थी. त्यातले काही आजही कमाईतला काही वाटा छात्रालयाला देतात. आता या दोन्ही छात्रालयांचा कारभार बघतात मधुकर शिरसाठ हे माजी विद्यार्थी. ते सरकारी नोकरीत होते. तुरुंग अधिकारी. सात वर्षांत त्यांनी ती सोडली व हे काम हाती घेतले. जे बिघडलेले त्यांना दुरुस्त करण्यापेक्षा पिढी बिघडूच नये यासाठी झटणे चांगले अशी त्यांची भूमिका. त्यांचे वडील समता सैनिक दलात होते. आंबेडकरांच्या जवळचे. शिरसाठांनी वाहून घेतले गांधीकार्याला. आजच्या प्रतिकूल परिस्थितीत गांधी-आंबेडकर या छात्रालयात एकत्र वास करतात हे तसे दुर्लभ चित्र!

डॉ. आंबेडकरांचा अभिप्राय

सेवक संघाच्या राज्य शाखेचे सचिव असलेले शिरसाठ वर्गणी गोळा करून विद्यार्थ्यांची सोय करतात. सरकार या संस्थेला नऊशे रुपये प्रतिविद्यार्थी अनुदान देते. सरकारी छात्रालयात हाच आकडा अडीच हजार. शिरसाठांच्या मदतीला येथील अनेक गांधीवादी असतात. रमेश दाणे हे ज्येष्ठ पत्रकार त्यातले एक. मध्यंतरी सरकारने अनुदान बंद केले तेव्हा धुळेकरांनी इथले विद्यार्थी जगवले. हे शहर धार्मिक दंगलीसाठी कुप्रसिद्ध. ती झाली की मुस्लीम या छात्रालयाचा आश्रय घेतात. काँग्रेस राजवटीच्या काळात ही संस्था दुर्लक्षित राहिली. युतीचे सरकार आल्यावर राजकुमार बडोले सामाजिक न्यायमंत्री असताना त्यांनी चार कोटींचा निधी दिला. यातून छात्रालयाची इमारत उभी राहिली पण अजून उद्घाटन झालेले नाही. कन्या छात्रालयासाठी जास्तीच्या निधीची मागणी केली पण टक्केवारी देण्याची ऐपत नाही म्हणून घोडे अडलेले. आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी पुढाकार घ्यावा व हा ऐतिहासिक वारसा पुढे न्यावा असे शिरसाठ म्हणतात. मध्यंतरी संस्थेचा अमृतमहोत्सव झाला. तत्कालीन राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील पाहुण्या होत्या. तेव्हा काही दलित संघटनांनी मोर्चा काढून फलकातील हरिजन शब्द हटवण्याची मागणी केली. यावरून तणाव निर्माण होऊ नये म्हणून शहरातील सर्व पक्षांचे लोक एकत्र आले व त्यांनी या संघटनांची समजूत काढली.

गेल्या ९० वर्षांत एकही वाद नाही, विद्यार्थ्यांची तक्रार नाही, कुठलीही वाईट घटना नाही हे या छात्रालयाचे वैशिष्ट्य. ते जपायला हवे यासाठी शहरातील सारे गांधीवादी दक्ष असतात. अनेकदा विद्यार्थ्यांच्या गरजा भागवता भागवता संस्थेच्या नाकीनऊ येतात, पण गांधींच्या प्रेरणेतून उभे राहिलेल्या या छात्रालयाला मदत करण्यासाठी काँग्रेसचा एकही नेता समोर येत नाही. हा पक्ष सध्या पराभूतावस्था अनुभवत असला तरी नेत्यांची श्रीमंती कायम. ते ऊठसूट गांधींचे नाव घेतात पण मदत मागितली की पाठ फिरवतात. हरिजन सेवक संघाची केवळ पाच छात्रालये सध्या राज्यात कशीबशी तग धरून आहेत. स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा ही संख्या पन्नासपेक्षा जास्त होती. नंतर बाळासाहेब भारदे या संघाचे राज्य अध्यक्ष झाले. अस्सल गांधीवादी व मनाने उमदे असलेल्या या नेत्याचा काँग्रेसच्याच लोकांनी गैरफायदा घेतला. अनेक ठिकाणची छात्रालये स्वतःच्या शिक्षण संस्थांना जोडून घेतली. अशा मागणीपत्रांवर भारदेंनी समोरच्यांवर विश्वास टाकून स्वाक्षऱ्या केल्या. नंतर या नेत्यांनी छात्रालये बंद केली व जागा हडपली.

आता पुण्याचे माजी आमदार मोहन जोशी अध्यक्ष आहेत. ही छात्रालये, कल्याणजवळच्या शेईला असलेली एक शाळा व अंबरनाथला १९३७ मध्ये स्थापन झालेली व अजूनही सुरू असलेली शाळा ते कशीबशी संचालित करतात- अनेकदा पदरचे पैसे खर्च करून. धुळ्याच्या छात्रालयाकडे आधी खूप जागा होती. बर्वेंनी विकत घेऊन दान दिलेली. तिथे बाजूलाच वैद्यकीय महाविद्यालय चालवणाऱ्या एका संस्थानिक तसेच काँग्रेसनेत्याने त्यातली बरीचशी हडपली. शिरसाठांनी खूप लढा दिला. आमिष झुगारले पण फायदा झाला नाही. अस्पृश्यता निवारणाचा नारा देणाऱ्या काँग्रेसच्या लेखी हे छात्रालयच अस्पृश्य ठरले आहे. उन्हाळ्याच्या सुट्टीत या संस्थेत वेगवेगळी शिबिरे भरतात. एप्रिलच्या शेवटी एका टळटळीत दुपारी भेट दिली तेव्हा बर्वेंचे नाव असलेल्या कन्या छात्रालयात भिक्खू महासंघाचे शिबीर सुरू होते. आताच्या दूषित वातावरणातला हा तसा दुर्मीळ प्रसंग. मनात कोरला गेलेला. नवीन इमारत पण उद्घाटन नाही. त्यामुळे एक छात्रालय भाड्याच्या इमारतीत सुरू ठेवावे लागल्याने संस्थेची आर्थिक ओढाताण खूप होते. ती बघून लोक देणगी देतात पण सरकार लक्ष देत नाही. गांधी, आंबेडकर, सावरकर अशी तिघांची पायधूळ लागलेली ही संस्था टिकायला हवी.

कुतूहल

धूमकेतूला शेपटी का असते?

सूर्यमालेतील इतर सभासदांपेक्षा आपल्या शेपटीमुळे वेगळे दिसणारे सभासद म्हणजे धूमकेतू! धूमकेतूंनी पृथ्वीच्या आणि पर्यायाने जीवसृष्टीच्या उत्क्रांतीत मोलाची भूमिका बजावली आहे. सूर्यमाला तयार होण्याच्या सुरुवातीच्या प्रचंड उलथापालथीच्या काळात, तयार होत असलेल्या पृथ्वीवर अनेक धूमकेतू आदळले. या प्रक्रियेत पाणी, अनेक सेंद्रिय मूलद्रव्ये आणि जीवनावश्यक घटक तयार होण्यासाठीची ऊर्जा, या धूमकेतूंनी पृथ्वीला बहाल केली.

सूर्यमालेतील ग्रह जसे सूर्यप्रदक्षिणा करतात तसेच धूमकेतूही सूर्याभोवती प्रचंड लांब पण लंबवर्तुळाकार प्रदक्षिणा करत असतात. जेव्हा आपल्याला एखादा धूमकेतू दिसू लागतो तेव्हा त्याची शेपटी आपलं लक्ष वेधून घेते. धूमकेतूला प्रत्यक्षात दोन शेपट्या असतात, थोडी वक्र दिसणारी धुळीची पांढरी शेपटी आणि सरळ दिसणारी वायूंची निळसर शेपटी!

सूर्यापासून दूरवर असताना धूमकेतूला एकही शेपटी नसते. मात्र तो जसजसा सूर्याजवळ येत जातो, तसतसे सूर्याच्या उष्णतेमुळे त्याच्या गाभ्यातील काही पदार्थ वितळू लागतात. वितळलेल्या या पदार्थांचा सौरवाताशी म्हणजे सूर्याकडून येणाऱ्या विद्युत प्रभारित कणांच्या प्रवाहाशी संपर्क आला, की ते गाभ्यातून बाहेर फेकले जातात. हे बाहेर फेकलेले पदार्थ म्हणजेच धूमकेतूच्या शेपट्या!

गाभ्यातून वितळून बाहेर पडलेल्या अनेक पदार्थांपैकी बाष्प, अमोनिया, नायट्रोजन, कार्बन डायऑक्साइड, कार्बन मोनोक्साइड यांसारख्या वायूंवर सूर्याकडून येणाऱ्या अतिनील किरणांमुळे धन विद्युतभार येतो. धन विद्युतभार असणाऱ्या या वायूंवर सौरवात आणि सूर्यकिरणांच्या दबावासह, सूर्याच्या चुंबकीय क्षेत्राचाही प्रभाव पडतो. त्यामुळे ते सूर्य आणि धूमकेतू यांना जोडणाऱ्या रेषेत मात्र सूर्यापासून उलट्या दिशेने, दूर फेकले जातात. या शेपटीत कार्बन मोनोक्साइडच्या कणांचं प्रमाण जास्त असतं. हा वायू सूर्याकडून येणारी अल्ट्राव्हायोलेट म्हणजेच अतिनील किरणं शोषतो. आणि नंतर निळ्या दृश्य प्रकाशाचं उत्सर्जन करतो. त्यामुळे ही शेपटी निळी दिसते.

बाहेर पडणाऱ्या पदार्थांत सिलिकेट्स, लोह, ग्रॅफाइट आणि काही अमिनो आम्लं यांचा समावेश असतो. या पदार्थांवर कोणताही विद्युतप्रभार नसल्यामुळे सूर्याचं चुंबकीय क्षेत्र या पदार्थांवर प्रभाव टाकू शकत नाही. या कणांचा आकारही तुलनेने मोठा असल्याने सूर्याकडून येणाऱ्या किरणांचा, या कणांवर तुलनेने जास्त दाब पडतो. या दाबामुळेच या शेपटीचा आकार धुमकेतूच्या फिरण्याच्या कक्षेच्या दिशेने थोडा वक्र होतो. हे कण सूर्याकडून येणारा प्रकाश परावर्तित करतात, म्हणून ही शेपटी फिकट पिवळसर किंवा पांढरी दिसते. गाभ्यातून बाहेर पडणारे हे पदार्थ धूमकेतूच्या कक्षेलगत साठत जातात. असे साठत गेलेले हे पदार्थ, दर वर्षी होणाऱ्या उल्कावर्षावाचं कारण ठरतात.

– सुमेध सावंत
मराठी विज्ञान परिषद
ईमेल : office@mavipa.org
संकेतस्थळ : www.mavipa.org

उलटा चष्मा

बंगाली मत्स्यपुराण...

***पश्चिम बंगालमधील** सरकारने केलेली पाच रुपयांत मासळीभाताची घोषणा ऐकून उद्विग्न झालेल्या एका ज्येष्ठ कार्यकर्त्याने वळकटी व लोखंडी पेटी उचलली. आता थेट दिल्ली गाठायची. पक्षाच्या मुख्यालयात जाऊन जाब विचारायचा असे ठरवत ते रेल्वेत बसले. कोलकाता ते दिल्ली प्रवासात त्यांना गेले सहा महिने बंगालमध्ये तळ ठोकून विजयासाठी घेतलेले कष्ट आठवले- केवळ धर्मभावना जागृत केल्यामुळे हा विजय मिळाला. आता मांसाहाराच्या माध्यमातून पुन्हा अधर्माकडे वाटचाल? छे छे! हे शक्यच नाही. सहन होत नाही- असे ते संपूर्ण प्रवासादरम्यान पुटपुटत राहिले.*

दिल्लीत पोहोचल्यावर त्यांनी थेट धोरण समितीतील ज्येष्ठांना गाठून मनातली खदखद बोलून दाखवली. ती शांतपणे ऐकून घेतल्यावर एक ज्येष्ठ म्हणाले. 'अरे, इतके नाराज व्हायचे काही कारण नाही. परिवाराचा एक घटक म्हणून पक्षाला विजय मिळवून देण्याची जबाबदारी आपली. राज्य चालवण्याची त्यांची. मांसाहाराला प्रोत्साहन देणे हे आपल्या धोरणात बसत नाही हे मान्यच, पण कधी कधी सत्तेसाठी धोरण बाजूला ठेवावे लागते. सामान्यांच्या भावनांचा विचार करावा लागतो. तिथल्या जनतेला आता कुठे आपण धर्माचरणाच्या पातळीवर आणले. आता त्यांच्या खाण्यापिण्याच्या सवयी मोडायच्या असतील तर थोडा वेळ लागेल ना! निवडणुकीच्या प्रचारात त्या दीदीने 'हे सत्तेत आले तर 'मांसमच्छी' बंद करतील' अशी भीती दाखवली होती. ती खोटी हे दर्शवण्यासाठी मूळ धोरणाला बगल द्यावी लागली. याचा अर्थ ते बासनात गुंडाळले असा होत नाही.

मंदिर, समान नागरी कायदा हे दीर्घकाळ बाजूला ठेवलेले मुद्दे नंतर मार्गी लागलेच ना! अजूनही अखंड भारताचे स्वप्न अधुरे आहे. एकदा संपूर्ण देश ताब्यात आला, विरोधक नष्ट झाले, प्रश्न विचारणारे संपले की हळूच धर्मवादींना धर्मवेडे करण्याच्या कामाला लागू. काही वर्षांपूर्वी ईशान्येकडील राज्ये जिंकतानासुद्धा मांसाहाराचा मुद्दा बाजूला ठेवावा लागला होता. तिथे तर बीफचा प्रश्न होता. तरीही राज्ये ताब्यात घेण्यासाठी त्यावर 'चुप्पी साधावी' लागली. बीफसमोर मासोळी तर क्षुल्लकच ना! यावर तुला कुणी डिवचलेच तर सरळ पुराणकथांचा आधार घे. पृथ्वीला वाचवण्यासाठी विष्णूनेसुद्धा मत्स्यावतार धारण केला होता. त्यातून 'मत्स्यपुराण' घडले. त्यामुळे आता धर्माला आणखी पुढे नेण्यासाठी काहीकाळ मासोळीचा आधार घेतला तर त्यात वावगे काय, असा प्रतिप्रश्न डिवचणाऱ्यांना विचार व निरुत्तर कर.

आणखी एक गोष्ट. अशा उदरभरणाच्या योजना दीर्घकाळ टिकत नाहीत. जयललितांनी 'अम्मा कँटीन' सुरू केलं. नंतर 'अण्णा इडली' आली. काँग्रेसने कर्नाटकात 'इंदिरा थाली' सुरू केली. महाराष्ट्रात 'शिवभोजन थाळी' सुरू झाली. पुढे काय झाले या योजनांचे? एकेक करत बंदच पडल्या ना! त्यामुळे किमान तू तरी मासोळीवरून उगाच 'शिवाशिव' करू नको. काही दिवसांत लोक ही योजनाच विसरून जातील. सामान्यांना धर्माच्या एका सूत्रात बांधून राजकीय विजय मिळवणे तसे सोपे. त्यांच्या खाण्यापिण्याच्या सवयी बदलणे कठीण. त्यासाठी चहूकडे धार्मिक वातावरण तयार करावे लागते. देवदेवतांची भीती दाखवावी लागते. हे दीर्घकाळ चालणारे काम आहे. सर्वंकष सत्ता मिळाल्यावरच ते शक्य आहे. त्यासाठी तू आतापासून कामाला लाग' हे ऐकल्यावर कार्यकर्ता थोडा शांत झाला व म्हणाला. 'म्हणजे मी जिवंत असेपर्यंत तरी हे धोरण देशात लागू होणे शक्य नाही.' यावर ज्येष्ठ हसत म्हणाले. 'अरे तेव्हा तू जिवंत नसलास तरी तुझ्या कार्याची नोंद इतिहासात घेतली जाईलच की, जशी विष्णूची घेतली गेली तशी!'

राजवाडे विचारविश्व

इतिहासाचे वास्तव रूप समजण्यासाठी...

'जी राष्ट्रे आज स्वतंत्र आहेत, त्यांतील इतिहासकारांनी (आणि पर्यायाने राज्यकर्त्यांनीही) हे पक्के ध्यानात ठेवले पाहिजे की, आजमितीस जी राष्ट्रे परतंत्र दिसतात, त्यांच्या चरित्रांत स्वतंत्र राष्ट्रांच्याही चरित्रांत दिसून येणार नाहीत, अशी प्रगतीची प्रौढ रूपे विद्यमान असण्याचा बळकट संभव आहे', असे सांगून राजवाड्यांनी युरोपीय लोकांच्याच समजुतीतील एका फेरबदलाचे चांगले उदाहरण पुढे केले.

त्यांनी लिहिले, 'शंभर दीडशे वर्षांपूर्वी सर्व भाषांचा उगम हिब्रू भाषेत असावा व पश्चिम युरोपातील इंग्रजी व फ्रेंच भाषा फारच प्रौढ दशेप्रत पोचलेल्या आहेत, असा समज युरोपामध्ये प्रचलित होता. परंतु संस्कृत भाषेशी जसजसा युरोपीय इतिहासकारांचा जास्त परिचय होत गेला, तसतसा हिब्रू भाषेशी आंग्ल, फ्रेंच वगैरे भाषांचा काहीएक संबंध नाही, आपले मूळ आर्यभाषेच्या जवळपास कोठेतरी आहे व आपल्या भाषांपेक्षाही प्रौढतर भाषा आहेत, असा त्यांचा ग्रह झाला. हा समज कितपत खराखोटा आहे, हा प्रश्न अलाहिदा; परंतु मानवसमाजाच्या भाषाविषयक इतिहासात युरोपीय लोकांची समजूत ही अशी फिरली, हे निर्विवाद आहे. असाच फेरबदल राजकीय, धार्मिक व सामाजिक बाबतींतही होण्याचा फार संभव आहे'.

युरोपीय इतिहासकारांमधली आणखी एक विलक्षण खोड राजवाड्यांनी या निमित्ताने उघडकीस आणली. त्यांनी लिहिले 'ती खोड ही की, पुरातन किंवा उत्तम असे जे काही आढळेल, त्याच्याशी आपल्या समाजाचा काहीतरी बादरायण संबंध लावण्याची ते हाव धरतात. ग्रीस देशाच्या इतिहासापलीकडे जोपर्यंत त्यांची माहिती गेली नव्हती, तोपर्यंत ट्रॉट शहराशी आपला संबंध लावून, हेलन नामक स्त्रीचे आपण वंशज आहोत, असे प्रतिपादन करण्यात त्यांना फुशारकी वाटे. काही काळपर्यंत यहुदी लोकांना ते आपले पूर्वज मानीत आणि अलीकडे संस्कृत भाषेशी परिचय झाल्यापासून ते आपली गणना आर्यकुळात करू लागले आहेत... या बादरायण पद्धतीचा परिणाम असा होतो की, दर दहा वर्षांनी त्यांचे ऐतिहासिक सिद्धान्त बदलत असतात... सारांश, सत्यापेक्षा, स्वजातिगौरवाकडे या लोकांचे लक्ष विशेष असते. हा दोष कोणत्याही देशातील निर्लेप इतिहासकारांनी टाळला पाहिजे'.

याबरोबरच इतिहासाच्या वास्तव रूपाबद्दलचे विवेचन सुरू करता करता राजवाड्यांनी अगदी थोडक्यात मांडलेले इतर काही मुद्देसुद्धा दखलपात्र होते. 'वर्तमानक्षणाच्या पाठीमागील गतकाळी पृथ्वीवरील नव्या व जुन्या सर्व समाजांच्या सर्व तऱ्हांच्या उलाढालींची जी साद्यन्त आणि विश्वसनीय हकिकत, ती इतिहास होय. असला साद्यन्त व विश्वसनीय इतिहास पृथ्वीवरील कोणत्याही भाषेत अद्यापपर्यंत लिहिला गेलेला नाही. समाजाच्या साद्यन्त चरित्राचा हर्डर, हेल्मोल्ट, क्लेअर, रिडपाथ वगैरे लोकांनी असला इतिहास लिहिण्याचा यत्न केला आहे; परंतु यांच्यापैकी प्रत्येकाचा इतिहास त्याच्या त्याच्या स्वदेशाभिमानाच्या रंगाने चितारला गेल्यामुळे, इतर देशांतल्या इतिहासज्ञांच्या पसंतीस सहजच उतरत नाही. जो तो आपापला देश त्रिभुवनाचे केंद्र समजून सकल जगाचा इतिहास रंगवण्याचा प्रयत्न करीत असतो. शिवाय प्रत्येकाचे स्वदेशाभिमानाखेरीज काहीतरी वैयक्तिक खूळ असतेच. कोणी केवळ भूगोलदृष्ट्या, कोणी केवळ काळदृष्ट्या, कोणी शास्त्रदृष्ट्या, कोणी निव्वळ व्यापारदृष्ट्या तर कोणी स्वदेशसंस्कृतिदृष्ट्या जगाच्या इतिहासाची अजमावणी करीत असतात. अशी नाना प्रकारची व्यंगे या इतिहासकारांच्या ग्रंथांत दृष्टीस पडतात; त्यामुळे विविध प्रश्नांचा समाधानकारक निकाल लागत नाही... तेव्हा वैयक्तिक मते एकीकडे सारून आणि स्वदेशाभिमानाचा दर्प बाजूला ठेवून... हेल्मोल्ट म्हणतो त्याप्रमाणे निर्लेप आणि निरहंकारी होऊन इतिहासाचा विचार करावयाला लागणे ही इतिहासाचे खरे स्वरूप जाणण्याच्या मार्गाला लागण्याची पहिली पायरी आहे.'

ही पहिली पायरी गाठणे किंवा गाठता येणे खूप कठीण आहे, भल्याभल्यांना ते जमलेले नाही, हेसुद्धा राजवाड्यांनी आपल्या विवेचनात पुरेसे स्पष्ट केले आणि पुढील पायरी म्हणजे सर्व प्रकारचे अर्धवट ग्रह सोडून देण्याची पायरी किती महत्त्वाची आहे, याबद्दलचे सोदाहरण स्पष्टीकरण देण्यास प्रारंभ केला.

– आनंद हर्डीकर
anand47.hardikar@gmail.com

अब्राहम आग्रहाचे अराजक!

ट्रम्प यांच्याशी शत्रुत्वाइतकीच, किंबहुना अधिक त्यांच्याशी मैत्रीच महागात कशी पडते याची प्रचीती त्यांच्या सर्व मित्रांना एव्हाना आलीच असेल.

अमेरिका आणि इस्रायलने फुटकळ कारणांसाठी इराणवर भीषण हल्ले करून सुरू केलेल्या युद्धास आज, २८ मे रोजी तीन महिने पूर्ण होतील. त्या संघर्षास तूर्त स्थगिती मिळाली आहे, पण तो पूर्णविराम नव्हे. तसे पाहिल्यास, रात्र-रात्र जागून युद्धासारख्या जागतिक समस्यांवर विचारमंथन करणे आणि रात्रीच शक्यतो त्या समस्यांवर तोडगा काढणे हा अमेरिकेचे विद्यमान अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा आवडीचा छंद. रोजच्या रोज समस्या बदलेल वा न बदलेल, पण तोडगा मात्र नवाच हवा! एखाद्या समस्येवर आज एक तोडगा असेल, तर उद्या त्याच समस्येवर निराळा तोडगा. पुन्हा 'काल तुम्ही या विषयावर वेगळे बोलला होतात' असे म्हणण्याची हिंमत असलेले महानुभाव ट्रम्प यांच्या टोळक्यात नाहीत. कदाचित काल आपण एखाद्या विषयावर काय बोललो हे ट्रम्प यांनाही दुसऱ्या दिवशी स्मरत नसेल. इराण युद्ध थांबवण्यासाठी त्यांनी जो ताजा तोडगा सुचवला, तोही त्यांना येत्या काही दिवसांत आठवणार नाही. पण त्यांच्या नवीन सूचनावजा आदेशाने इराण युद्धसमाप्तीची बोलणी फिस्कटू शकतात आणि इंधनटंचाईच्या झळा जगाला आणखी अनंत काळ सोसाव्या लागू शकतात, त्यामुळे तोडग्याचा श्लेष आवश्यक.

इराणशी जो काही सौदा (ट्रम्प यापेक्षा वेगळे काय करू शकतात?) करायचा, त्यात भागीदारी हवी असेल तर संबंधित देशांनी अमेरिकेच्या पुढाकाराने आणि इस्रायलला गोंजारण्यासाठी घडवून आणलेल्या 'अब्राहम करारा'तही सहभागी झाले पाहिजे असा आग्रह ट्रम्प यांनी काही अरब आणि मुस्लीम देशांपाशी धरला आहे. हे देश आहेत सौदी अरेबिया, कतार, तुर्कीये, इजिप्त आणि पाकिस्तान. अब्राहम करारात जे सहभागी होत नाहीत, त्यांना इराण सौद्याचा मार्गही बंद. ही विचित्र अट संबंधित देशांसाठी धक्कादायक खरीच. कारण यांतील बहुतेक देश, विशेषतः कतार आणि पाकिस्तान इराण युद्धसमाप्तीसाठी अमेरिका आणि इराण यांच्यात वाटाघाटी घडवून आणत आहेत. इराणवर 'लष्करी कारवाई'ला २८ फेब्रुवारी रोजी सुरुवात झाली. एप्रिलच्या सुरुवातीस या कारवाईस दोन्ही देशांच्या संमतीने स्थगिती देण्यात आली. या युद्धविरामाचा उद्देश युद्धसमाप्तीसाठी काही तरी शाश्वत स्वरूपाचा तोडगा शोधून काढणे, असा सांगितला जातो. ती बोलणी जेथे सुरू झाली, तेथेच थिजलेल्या अवस्थेत आहेत. कारण होर्मुझ सामुद्रधुनीची नाकेबंदी आणि इराणच्या ताब्यातील युरेनियम समृद्धीकरणाची मर्यादा या दोन कळीच्या विषयांवर मतैक्य अजिबात संभवत नाही. हे दोन विषय सोडून इतर बाबींची चर्चा म्हणजे वेळेचा आणि पैशाचा अपव्यय. त्यात पुन्हा आता या अब्राहम कराराची नवी पाचर.

अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी आपण विराजमान झाल्यानंतर 'प्रचंड यशस्वी' अशा असंख्य निर्णयांपैकी एक म्हणजे हा अब्राहम करार, असे ट्रम्प मानून चालतात. डोनाल्ड ट्रम्प २०१६ ते २०२० या काळात पहिल्यांदा अमेरिकेचे अध्यक्ष होते, त्या वेळी पश्चिम आशियात पॅलेस्टाइन प्रश्न मार्गी लावण्यात त्यांचे हितसंबंध गुंतलेले होते. वरकरणी हा उद्देश असला, तरी त्यात इस्रायलचे आणि अमेरिकेतील इस्रायलवादी रिपब्लिकन धनाढ्यांचे हितच अभिप्रेत होते. म्हणूनच याकामी कोण्या मुत्सद्द्यावर भरवसा न ठेवता त्यांनी आपले जामात जॅरेड कुश्नेर यांना आखातात वारंवार धाडले. त्या काळात आणि विशेषतः इस्रायलचे नरसंहारी पंतप्रधान बिन्यामिन नेतान्याहू यांच्या अमदानीत इस्रायलने पश्चिम किनारपट्टी आणि गाझा पट्टी या पॅलेस्टिनी मुलुखांत पद्धतशीर विस्तार सुरू केला होता. त्यास पॅलेस्टिनींचा कडाडून विरोध होत होता. त्याची दखल अरब देशांकडून घेतली जात होती. इस्रायलच्या विस्तारवादाकडून लक्ष दुसरीकडे वळवायचे, तर त्यासाठी प्रथम अरब देशांकडून इस्रायलला मान्यता मिळवणे हे पहिले पाऊल. ते मिळवण्यासाठी ट्रम्प यांनी अब्राहम कराराची संकल्पना

> **कारण अब्राहम कराराच्या निमित्ताने प्रथम इस्रायलला मान्यता द्यावी हा ट्रम्प यांचा त्यांच्या मित्रदेशांकडेच अजब आग्रह. पॅलेस्टिनी मरोत, आम्हांस आणि इस्रायलला हवे ते मान्य आहे की नाही ते कळवा. सोबत आलात तर ठीक, नाही तर गेलात उडत अशी त्यांची अरेरावी.**

मांडली. ख्रिस्ती, इस्लाम आणि यहुदी या तीन 'अब्राहमिक' (या तीनही धर्मांचा उगम अब्राहम या आद्य प्रेषितापासून होतो. म्हणून या धर्मांस अब्राहमिक असे संबोधले जाते) धर्मांशी संबंधित राष्ट्रांना केंद्रस्थानी ठरवून हा करार करण्यात आला. करारात अरब देशांनी सहभागी व्हावे यासाठी आणखी एक गाजर दाखवण्यात आले, ते होते इराणभयाचे. कारण या टापूतील अरब देश आणि इस्रायल, तसेच अमेरिका या सर्वांसाठी इराण हा शत्रू क्रमांक एक होता. अब्राहम करार हा पश्चिम आशियात शांतता, समृद्धी, स्थैर्य घडवून आणण्यासाठी कसा नि किती आवश्यक याचे दाखले दिले गेले. या भूलथापांना पहिले गळाला लागले संयुक्त अरब अमिराती (यूएई) नि बहारिन. अब्राहम करार हा शांतता तोडगा म्हणूनही संबोधला जातो. पण ज्या अरब राष्ट्रांशी इस्रायलने युद्धे लढली, ते देश म्हणजे जॉर्डन आणि इजिप्त यांनी पूर्वीच त्या देशाशी शांतता करार केलेला आहे. बहारिन आणि यूएई कधी इस्रायलशी लढलेच नाहीत! पण त्यांच्याकडून इस्रायलला मान्यता मिळवण्याचे काम कराराच्या माध्यमातून झाले. आणखी दोन देश या करारात सहभागी झाले. ते होते मोरोक्को आणि सुदान. या चारही देशांशी इस्रायलने व्यापार, पर्यटन, तंत्रज्ञान देवाणघेवाण या क्षेत्रांमध्ये संबंध प्रस्थापित केले.

मात्र सौदी अरेबिया आणि कतार या प्रमुख धनाढ्य देशांनी इस्रायलला मान्यता देण्याची घाई केली नाही. आता तर गेल्या तीन वर्षांत गाझा पट्टीत इस्रायलने घडवून आणलेल्या नरसंहारानंतर ती शक्यताही उरलेली नाही. अब्राहम करारात सहभाग म्हणजे इस्रायलच्या अस्तित्वाला मान्यता आणि पॅलेस्टाइन राष्ट्रनिर्मितीचा मुद्दा अनादि-अनंत काळ लटकता, हा कावा ओळखण्याची कुवत या दोन्ही देशांच्या नेतृत्वाकडे शाबूत आहे. ट्रम्प यांनी पाकिस्तान, तुर्कीये यांनाही अब्राहम करारात सहभागी होण्याविषयी फर्मावले. तुर्कीयेने १९४९ मध्ये इस्रायलला मान्यता दिली. पाकिस्तान या करारात सहभागी होणार नाही, कारण इस्रायलला मान्यता देण्याचे त्यांचे धोरण नाही. मूळ अब्राहम कराराला शांतता करार असे संबोधले गेले, त्यातून पश्चिम आशियात शांतता निर्माण होऊ शकली नाहीच. आता त्या कराराचा विस्तार इराण शांतता कराराशी जोडला जातो, तेथेही शांतता वा स्थैर्य निर्माण होणार नाही.

कारण मूळ अब्राहम करार झालाच मुळी इस्रायली हट्टातून. इराणबरोबर वाटाघाटींमध्ये इस्रायल सहभागी नाही. तरीदेखील आताच्या घडामोडींवर इस्रायलची काळी सावली आहेच. कारण अब्राहम कराराच्या निमित्ताने प्रथम इस्रायलला मान्यता द्यावी हा ट्रम्प यांचा त्यांच्या मित्रदेशांकडेच अजब आग्रह. पॅलेस्टिनी मरोत, आम्हांस आणि इस्रायलला हे हवे आहे, ते मान्य आहे की नाही ते कळवा. तुम्ही सोबत आलात तर ठीक, नाही तर गेलात उडत अशी ही अरेरावी. ट्रम्प यांच्याशी शत्रुत्वाइतकीच, किंबहुना अधिक त्यांच्याशी मैत्रीच महागात कशी पडते याची प्रचीती त्यांच्या सर्व मित्रांना एव्हाना आलीच असेल. एकदा आणखी अरब देश गळाला लागले, इस्रायल नि त्यांच्यात संबंध प्रस्थापित झाले की पॅलेस्टाइनला पुसतो कोण? नि द्विराष्ट्र सिद्धान्ताची पत्रास ठेवतो कोण? हे नेपथ्य कोणत्या देशास सर्वाधिक फायदेशीर ठरणार, हे वेगळे सांगण्याची गरज ती काय? इराणी नेतृत्वाचा आडमुठेपणा गृहीत धरला, तरी ट्रम्प यांचा लहरीपणा असा सातत्याने घातक ठरू लागला आहे. त्यातून युद्धसमाप्तीची शक्यताही लुप्त होताना दिसते. पॅलेस्टाइनच्या जिवावर अरबी नैतिकतेला ट्रम्प यांनी ललकारले आहे. आधीच त्यांतले काही गळाला लागले. आता उरलेसुरलेही फशी पडले, तर या विस्तारित कराराचा आग्रह पश्चिम आशियात अब्राहम अराजक ठरण्याची शक्यताच अधिक.

शिक्षण व्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेचा पराभव

लेख

डॉ. विवेक बी. कोरडे
शिक्षणक्षेत्रातील जाणकार
vivekkorde0605@gmail.com

या वर्षीचा सीबीएससी बारावीचा निकाल सुरुवातीपासूनच वादाच्या भोवऱ्यात अडकला आहे. त्याचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे विद्यार्थ्यांना अपेक्षेपेक्षा खूपच कमी गुण मिळणे. यंदा विशेषतः ७५ टक्क्यांपेक्षा जास्त गुण मिळवणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या लक्षणीयरीत्या कमी झाल्याने पालक आणि विद्यार्थ्यांमध्ये नैराश्य, संभ्रम आणि अस्वस्थतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

सीबीएससीच्या यंदाच्या निकालात एकूण उत्तीर्णतेचा टक्का तब्बल ३.१९ टक्क्यांनी घसरला आहे आणि अनेक विद्यार्थ्यांच्या गुणांमध्ये अनपेक्षित घट दिसून आली आहे. यामागे कौशल्याधारित (कॉम्पिटन्सी बेस्ड्) प्रश्नांची वाढ, डिजिटल ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) प्रणालीची अंमलबजावणी आणि भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र यांसारख्या विषयांतील अधिक कठोर मूल्यमापन कारणीभूत असल्याचे सांगितले जात आहे. शिक्षण व्यवस्था आता पाठांतरावर आधारित प्रणालीपासून संकल्पनात्मक आणि विश्लेषणात्मक शिक्षणाकडे वळत असल्याचा दावा केला जात आहे. कागदावर हे आकर्षक वाटू शकते, परंतु प्रत्यक्षात विद्यार्थ्यांना या बदलासाठी कितपत तयार करण्यात आले होते, हा मूलभूत प्रश्न आहे. कारण शिक्षणातील कोणताही बदल हा विद्यार्थ्यांवर अचानक लादला जाणारा प्रयोग असू शकत नाही. एका बाजूला वर्षानुवर्षे चालत आलेली अभ्यासपद्धती, कोचिंग क्लासेसची रचना आणि परीक्षा तयारीची सवय; आणि दुसऱ्या बाजूला अचानक बदललेली प्रश्नपत्रिका, नवीन मूल्यमापन पद्धती आणि कठोर तपासणी - या दोघांमधील दरी भरून काढण्यासाठी पुरेशी यंत्रणा उभी करण्यात आली होती का? की 'राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण' आणि 'शैक्षणिक सुधारणा' या आकर्षक घोषणांच्या नावाखाली विद्यार्थ्यांच्या भविष्यावरच प्रयोग करण्याचा उद्योग सुरू आहे?

या सर्व प्रक्रियेचा सर्वाधिक फटका विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्याला बसत आहे. निकालानंतर अनेक विद्यार्थ्यांमध्ये आत्मविश्वास कमी होणे, नैराश्य निर्माण होणे आणि स्वतःच्या क्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहणे यांसारख्या घटना समोर येत आहेत. शैक्षणिक सुधारणांच्या नावाखाली जर विद्यार्थ्यांचे मानसिक खच्चीकरण होत असेल, तर त्या नेमक्या कोणासाठी आणि कशासाठी आहेत, हा प्रश्न शिक्षण व्यवस्थेला विचारलाच पाहिजे.

अशातच दिल्लीतील एक धक्कादायक प्रकरण संपूर्ण शिक्षण व्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उभे करणारे ठरले. बारावीत भौतिकशास्त्र विषयात अपेक्षेपेक्षा खूपच कमी गुण मिळाल्याने वेदांत श्रीवास्तवने

> **येथे प्रश्न फक्त एका विद्यार्थ्याचा नाही; तर आपल्या समाजाच्या मानसिकतेचा आहे. न्यायासाठी आवाज उठवणाऱ्या विद्यार्थ्याला पुराव्याआधीच दोषी ठरवण्याची घाई आपण का करतो? शिक्षण व्यवस्थेतील चुका दाखवणाऱ्याला उत्तर देण्याऐवजी त्यालाच लक्ष्य करण्याची प्रवृत्ती का वाढत आहे?**

पुनर्पडताळणीसाठी अर्ज केला. कदाचित त्यालाही सुरुवातीला वाटले असेल की मूल्यांकनात काही किरकोळ चूक झाली असेल; पण उत्तरपत्रिकेची प्रत मिळाल्यानंतर त्याने सांगितले - 'हे माझे हस्ताक्षरच नाही.' म्हणजे प्रश्न फक्त कमी गुणांचा नव्हता; प्रश्न असा होता की, विद्यार्थ्याच्या नावाशी दुसऱ्याच व्यक्तीची उत्तरपत्रिका जोडली गेली होती. ही केवळ तांत्रिक चूक नव्हती, तर विद्यार्थ्याच्या आयुष्याशी आणि भविष्याशी खेळलेला गंभीर प्रकार होता. दुर्दैवाने या विद्यार्थ्याचा आवाज ऐकून घेण्याऐवजी सुरुवातीला त्याच्यावरच संशय घेतला गेला. सोशल मीडियावर त्याची खिल्ली उडवली गेली, त्याला ट्रोल करण्यात आले, त्याच्या प्रामाणिकपणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले. त्याच्यावर हा विद्यार्थी पाकिस्तानी आहे अशी वैयक्तिक आणि असंबंधित टीकाही झाली. येथे सर्वात मोठा प्रश्न फक्त एका विद्यार्थ्याचा नाही; प्रश्न आपल्या समाजाच्या मानसिकतेचा आहे. न्यायासाठी आवाज उठवणाऱ्या विद्यार्थ्याला पुराव्याआधीच दोषी ठरवण्याची घाई आपण का करतो? शिक्षण व्यवस्थेतील चुका दाखवणाऱ्याला उत्तर देण्याऐवजी त्यालाच लक्ष्य करण्याची प्रवृत्ती का वाढत आहे? स्वतःच्या हक्कासाठी बोलल्यामुळे एका विद्यार्थ्याला समाजाच्या न्यायालयात आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले जात असेल, तर हे केवळ शैक्षणिक व्यवस्थेचे नाही तर सामाजिक नैतिकतेचेही अपयश आहे.

या संपूर्ण प्रकरणातील अधिक चिंताजनक बाब म्हणजे या वर्षी उत्तरपत्रिकांचे डिजिटल स्कॅनिंग आणि तथाकथित 'स्मार्ट मूल्यांकन' प्रणाली म्हणजेच ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) पद्धतीचा वापर मोठ्या प्रमाणात करण्यात आला. कागदावर ही प्रणाली आधुनिक आणि आकर्षक वाटत असली तरी प्रत्यक्षात अनेक शिक्षकांनीच स्कॅनिंगमधील त्रुटींमुळे उत्तरपत्रिका स्पष्ट दिसत नसल्याची, पाने अपूर्ण दिसण्याची किंवा मूल्यांकनात अडचणी येत असल्याची नाराजी व्यक्त केली होती. विद्यार्थ्यांनी मूल्यांकन झालेल्या प्रती मागवल्या, तेव्हा अनेकांना धक्कादायक विसंगती दिसून आल्या. म्हणजेच तंत्रज्ञानाच्या नावाखाली निर्माण केलेली व्यवस्था प्रत्यक्षात विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी धोकादायक खेळ करत असल्याचे चित्र दिसू लागले. आणि शेवटी जेव्हा हा विषय समाज माध्यमांवर गाजला, चर्चा वाढली आणि सर्वत्र प्रश्न विचारले जाऊ लागले, तेव्हाच सीबीएससीला मान्य करावे लागले की तांत्रिक चूक झाली होती आणि चुकीची उत्तरपत्रिका त्या विद्यार्थ्याशी जोडली गेली होती. पण इथे खरा प्रश्न उभा राहतो विद्यार्थ्याने इतका संघर्ष केल्यानंतर, मानसिक तणाव सहन केल्यानंतर आणि सार्वजनिक अपमान सहन केल्यानंतरच ही चूक मान्य व्हावी का? त्याने आवाजच उठवला नसता तर? त्याचे भविष्य, त्याचे गुण, त्याची मेहनत आणि त्याची स्वप्ने कायमची कोणाच्या तरी 'सिस्टम एरर'च्या नावाखाली गाडली गेली असती का? शिक्षण व्यवस्था ही विद्यार्थ्यांच्या आयुष्याचा पाया असते; ती विद्यार्थ्यांच्या सहनशक्तीची परीक्षा घेणारी प्रयोगशाळा नसते.

आता सर्वात मोठा आणि अस्वस्थ करणारा प्रश्न असा आहे की, त्या एका विद्यार्थ्याने धाडस करून आवाज उठवला नसता, जर समाजमाध्यमांवर हे प्रकरण गाजले नसते, तर ही चूक कधीच समोर आली असती का?

त्या विद्यार्थ्याचे गुण, त्याचे करिअर, त्याची वर्षानुवर्षांची मेहनत, त्याची स्वप्ने आणि त्याचे संपूर्ण भविष्य एखाद्या संगणकीय 'तांत्रिक त्रुटी'च्या नावाखाली गाडले गेले असते का? आणि उद्या हा प्रश्न फक्त वेदांतपुरता मर्यादित राहणार आहे याची खात्री कोण देणार? कारण आज तो वेदांत होता; उद्या तो कोणताही विद्यार्थी असू शकतो. एखाद्या गरीब शेतकऱ्याचा मुलगा, मजुराची मुलगी किंवा कर्ज काढून मुलांच्या शिक्षणासाठी संघर्ष करणाऱ्या पालकांची आशा असू शकते. आज शिक्षण व्यवस्थेत तंत्रज्ञानाचा प्रचंड गाजावाजा केला जात आहे. डिजिटल इंडिया, स्मार्ट मूल्यांकन, ऑन-स्क्रीन मार्किंग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आधुनिक शिक्षण प्रणाली - या आकर्षक आणि चमकदार शब्दांनी वातावरण भरून गेले आहे. पण या तथाकथित स्मार्ट व्यवस्थेतच विद्यार्थ्यांच्या उत्तरपत्रिका चुकीच्या नावांशी जोडल्या जात असतील, स्कॅनिंगमध्ये चुका होत असतील आणि जर विद्यार्थ्यांनाच स्वतःच्या न्यायासाठी रस्त्यावर उतरावे लागत असेल, तर ही प्रगती नसून विद्यार्थ्यांच्या आयुष्याशी चाललेला खेळ आहे. कारण शिक्षणातील तंत्रज्ञान हे विद्यार्थ्यांना मदत करण्यासाठी असते, त्यांचे भविष्य धोक्यात घालण्यासाठी नव्हे.

विद्यार्थी वर्षानुवर्षे संघर्ष करतात. अनेक विद्यार्थी घरची परिस्थिती हलाखीची असतानाही दिवस-रात्र अभ्यास करतात, पालक स्वतःच्या गरजा बाजूला ठेवून मुलांच्या शिक्षणासाठी कर्ज काढतात, स्वतःची स्वप्ने मोडून मुलांच्या स्वप्नांना पंख देण्याचा प्रयत्न करतात. आणि शेवटी त्यांच्या आयुष्याचा निर्णय एखाद्या तांत्रिक चुकीवर, एखाद्या चुकीच्या स्कॅनिंगवर किंवा एखाद्या यंत्रणात्मक गोंधळावर अवलंबून असेल, तर ही व्यवस्था विद्यार्थ्यांसाठी नसून व्यवस्थेच्या सोयीसाठी चालत असल्याचे स्पष्ट होते. सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे या घटनेनंतर इतर विद्यार्थ्यांकडूनही अशाच प्रकारच्या तक्रारी समोर येऊ लागल्या. याचा अर्थ हा केवळ 'एक अपवाद' नाही; तर व्यवस्थेच्या भिंतींना पडलेल्या मोठ्या तड्याचा इशारा असू शकतो. सीबीएसईने चूक मान्य केली, हे स्वागतार्ह आहे; पण केवळ चूक मान्य केल्याने जबाबदारी संपत नाही. या चुकीसाठी जबाबदार कोण? विद्यार्थ्यांच्या मानसिक तणावाची भरपाई कोण करणार? चुकीच्या मूल्यमापनामुळे एखाद्या विद्यार्थ्याने प्रवेश, संधी किंवा आयुष्याची दिशा गमावली असेल, तर त्याची किंमत कोण मोजणार?

देशाला आज केवळ नवीन शैक्षणिक धोरणांची नाही, तर उत्तरदायी आणि संवेदनशील शिक्षण व्यवस्थेची गरज आहे. विद्यार्थ्यांना आकर्षक घोषणा नकोत; त्यांना न्याय हवा आहे. कारण विद्यार्थी हे प्रयोगशाळेतील उंदीर नाहीत. त्यांच्या उत्तरपत्रिका फक्त कागदाचे गठ्ठे नाहीत; त्या त्यांच्या आयुष्याची स्वप्ने, त्यांच्या पालकांचा संघर्ष आणि त्यांच्या भविष्याचा पाया आहेत. आणि त्या पायाशी निष्काळजीपणा, तांत्रिक चुका आणि व्यवस्थेची बेफिकिरी ठेवली जात असेल, तर ती केवळ एका विद्यार्थ्याची हार नसून संपूर्ण शिक्षण व्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेचा पराभव आहे.

अन्वयार्थ

हिंदीवरून भाजपला उपरती

केंद्र सरकारच्या नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणातील त्रिभाषा सूत्रावरूनच आरोप-प्रत्यारोप झाले. या सूत्राच्या आडून हिंदी लादण्याचा भाजपचा प्रयत्न असल्याची टीका विरोधकांनी केली. त्रिभाषा सूत्राचे भाजप व केंद्र सरकारकडून नेहमीच समर्थन केले जाते. तीन भाषांमुळे विद्यार्थ्यांना नवीन भाषा शिकण्याची संधी उपलब्ध होते तसेच भारतीय सांस्कृतिक वैविध्यतेची ओळख होते, असा युक्तिवाद भाजपकडून केला जातो. तिसरी भाषा म्हणजे फक्त हिंदी नाही, तर विद्यार्थ्यांनी कोणतीही भारतीय भाषा शिकावी, अशी भूमिका केंद्राच्या वतीने मांडण्यात आली होती. तमिळनाडू, कर्नाटक या दक्षिणेकडील राज्यांनी त्रिभाषा सूत्राला ठाम विरोध दर्शविला. तमिळनाडूत तर हिंदीला सख्त विरोध केला जातो. तत्कालीन द्रमुक सरकारने त्रिभाषा सूत्र स्वीकारण्यास ठाम नकार दिला होता. यातूनच केंद्राने तमिळनाडूचे दोन हजार कोटींपेक्षा अधिक समग्र शिक्षा अभियानातील अनुदान रोखून धरले होते. तमिळनाडूत द्रमुक, टीव्हीके, अण्णा द्रमुक अशा सर्वच प्रादेशिक पक्षांनी हिंदीला विरोध केला असताना राज्यातील भाजप नेत्यांकडून त्रिभाषा सूत्राचे समर्थन केले जात होते.

त्याच तमिळनाडूतील भाजप नेत्यांकडून त्रिभाषा सूत्राला झालेला विरोध हा लक्षणीय बदल मानला जातो. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या म्हणजेच सीबीएसईच्या वतीने नवीन शैक्षणिक वर्षात इयत्ता नववीपासून त्रिभाषा सूत्राची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. तसा आदेश सीबीएसईच्या वतीने गेल्या आठवड्यात लागू करण्यात आला. त्याची प्रतिक्रिया तमिळनाडूमध्ये उमटणे स्वाभाविक होते. द्रमुक, मुख्यमंत्री विजय यांच्या टीव्हीकेकडून विरोध झाला असता तर आश्चर्य वाटले नसते. पण या धोरणाला भाजप नेत्यांनीच विरोध दर्शविला आहे. अण्णामलाई हे भाजपचे तमिळनाडूतील आक्रमक नेते अशी त्यांची ख्याती. भारतीय पोलीस सेवेतील (आय.पी.एस.) राजीनामा देऊन राजकारणात उतरलेल्या अण्णामलाई यांनी केंद्राच्या धोरणाला सक्त विरोध दर्शवीत त्रिभाषा सूत्र २०२९-३० या आधीच्या नियोजित वेळापत्रकानुसार राबवावे, असे पत्रच केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांना दिले आहे. सीबीएसईच्या आदेशानंतर तमिळनाडूतील मुख्यमंत्री जोसेफ विजय यांच्या सरकारने तमिळ व इंग्रजी या दोन भाषांचे सूत्र राज्यात कायम राहील व तिसरी भाषा शिकवली जाणार नाही, असे स्पष्ट केले. त्रिभाषा सूत्राच्या आडून हिंदी लादण्याचा हा केंद्राचा प्रयत्न असल्याचा आरोप तमिळनाडूत सुरू झाला होता. त्यातूनच भाजपमध्ये तीव्र प्रतिक्रिया उमटली असणार हे निश्चित.

दक्षिणेत भाजपला अजूनही तेवढा जनाधार मिळालेला नाही. तमिळनाडूत विविध प्रयोग करूनही भाजपची ताकद वाढू शकलेली नाही. नुकत्याच पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपचा फक्त एक आमदार निवडून आला. गेल्या वेळी चार आमदार निवडून आले होते. तमिळनाडूत भाजपच्या वाढीसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व गृहमंत्री अमित शहा यांनी जोर लावला होता. पण सारे प्रयत्न फोल ठरले. भाजपने अण्णा द्रमुकबरोबर युतीत निवडणूक लढवली. पण त्याचा पक्षाला काहीही फायदा झाला नाही. 'अण्णा द्रमुक - भाजपला मत म्हणजे दिल्लीची सत्ता', असा प्रचार द्रमुकने केला होता. भाजपला यश मिळाल्यास राज्यात हिंदीची सक्ती केली जाईल, हा प्रचाराचा मुद्दा होता. भाजपच्या अपयशात हिंदी सक्तीचा मुद्दा महत्त्वाचा ठरला असावा. दोन वर्षांपूर्वी तमिळनाडूत झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत भाजपला ५.४१ टक्के मते मिळाली होती. विधानसभा निवडणुकीत मतांची टक्केवारी तीन टक्क्यांपर्यंत घसरली व केवळ एकच उमेदवार निवडून आला. त्रिभाषा सूत्र म्हणजे हिंदी लादण्याचा प्रयत्न हा प्रचार भाजपच्या विरोधात गेला असणार. यामुळेच अण्णामलाई यांनी त्रिभाषा सूत्राची अंमलबजावणी आता नको, अशी ठाम भूमिका घेतली आहे. हिंदीवरून भाजपला झालेली उपरती, असाच त्याचा अर्थ काढला जातो. जयललिता यांच्या पश्चात अण्णा द्रमुकची पीछेहाट होईल व ती राजकीय जागा व्यापण्याची भाजपची योजना होती. पण लागोपाठ दोन विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजपला काहीच प्रगती करता आलेली नाही. चित्रपट अभिनेता जोसेफ विजय यांनी दोन वर्षांपूर्वी स्थापन केलेल्या टीव्हीके पक्षाने सत्ता काबीज करीत प्रस्थापित सर्व पक्षांना मोठा धक्का दिला. अण्णा द्रमुकच्या अस्तित्वाचाच प्रश्न आता निर्माण झाला आहे. अशा वेळी भाजपला स्वबळावर पक्षवाढीसाठी प्रयत्न करावे लागणार आहेत. हिंदी सक्ती हा त्यात अडसर येऊ शकतो हे भाजप नेत्यांच्या लक्षात आले असावे. त्यातूनच त्रिभाषा सूत्रावरून भाजपच्या नेत्यांनी माघार घेतलेली असू शकते.

त्रिभाषा सूत्रामुळे परदेशी भाषा शिकवणाऱ्या शिक्षकांच्या नोकरीवर गदा?

विश्लेषण

चिन्मय पाटणकर
chinmay.patankar@expressindia.com

> **राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० नुसार केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाने (सीबीएसई) इयत्ता सहावीपासून त्रिभाषा सूत्राची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे फ्रेंच, जपानी, जर्मन अशा परदेशी भाषा मुख्य विषय रचनेतून हद्दपार झाल्या आहेत. त्यामुळे या भाषा शिक्षकांना नोकरी गमवावी लागणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.**

सीबीएसईचे त्रिभाषा सूत्र काय आहे?

सीबीएसईने शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ पासून देशभरातील शाळांमध्ये त्रिभाषा सूत्र लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार नव्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणावर आधारित शिक्षण आराखड्यानुसार, इयत्ता सहावीपासून तीन भाषा शिकवल्या जाणार आहेत. त्यापैकी दोन भाषा भारतीय असणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील सीबीएसई संलग्न शाळांचा विचार करता मुळात विद्यार्थी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत असल्यास इंग्रजी ही माध्यम भाषा, राज्यात मराठी सक्तीची असल्याने मराठी भाषा, तसेच आणखी एक भारतीय भाषा म्हणून हिंदी, संस्कृतसह अन्य भारतीय भाषांचा पर्याय उपलब्ध असेल. इयत्ता सहावीशिवाय सीबीएसईने अलीकडेच इयत्ता नववीलाही २०२६-२७ पासूनच तिसरी भाषा शिकवण्याचा निर्णय घेतला. मात्र या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे.

त्रिभाषा सूत्रापूर्वीची रचना कशी होती?

त्रिभाषा सूत्र लागू करण्याआधी पाचवीपर्यंत दोनच भाषा शिकवल्या जायच्या. त्यात पहिली भाषा म्हणून माध्यम भाषा (प्रामुख्याने इंग्रजी), दुसरी भाषा म्हणून प्रादेशिक भाषा शिकवली जायची. सहावी ते आठवीच्या स्तरावर तीन भाषा शिकवल्या जात होत्या. मात्र, तिसरी भाषा निवडण्याबाबत लवचीकता होती. त्यात विद्यार्थी भारतीय भाषांशिवाय परदेशी भाषाही निवडू शकत होते. तिसऱ्या भाषेचे मूल्यमापन शाळा स्तरावरच केले जायचे. तर बोर्डाच्या परीक्षेसाठी दोनच भाषा शिकणे अनिवार्य होते. त्यात पहिली भाषा म्हणून इंग्रजी, दुसरी भाषा म्हणून कोणतीही भारतीय भाषा किंवा कोणतीही परदेशी भाषा निवडण्याची विद्यार्थ्यांना मुभा होती.

आता राष्ट्रीय शिक्षण धोरणानुसार त्रिभाषा सूत्राची अंमलबजावणी करताना काय होणार?

राष्ट्रीय शिक्षण धोरणामध्ये इंग्रजी ही भाषा परदेशी भाषांच्या गटात ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे जर्मन, फ्रेंच, जपानी अशा परदेशी भाषांचा मुख्य विषय रचनेमध्ये समावेश करता येणार नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना इंग्रजी भाषेमुळे अन्य परदेशी भाषा शिकता येणार नाहीत. विद्यार्थ्यांना चौथी भाषा शिकायचीच असल्यास ते जर्मन, फ्रेंच, जपानी अशा परदेशी भाषांची निवड करू शकतात. सीबीएसईशी संलग्न असलेल्या महाराष्ट्रातील बहुसंख्य शाळा इंग्रजी माध्यमाच्या आहेत. त्यामुळे इंग्रजी ही माध्यम भाषा असेल. महाराष्ट्रात मराठी सक्तीची असल्याने मराठी दुसरी भाषा, तर भारतीय भाषांच्या गटातून प्रामुख्याने हिंदी, संस्कृतचा पर्याय विद्यार्थी निवडू शकतात. तसेच हिंदी, संस्कृतव्यतिरिक्त अन्य भारतीय भाषा शिकायची असली तरी पुरेसे विद्यार्थी नसल्यास शाळेकडून स्वतंत्र शिक्षक मिळू शकणार नाही. त्यामुळे तांत्रिकदृष्ट्या जर्मन, जपानी, फ्रेंच अशा परदेशी भाषा आता अधिकृत शिक्षणातून हद्दपार झाल्याचे चित्र आहे.

परदेशी भाषा शिक्षकांना नोकरी गमवावी लागणार?

आतापर्यंत अनेक शाळांनी केवळ जर्मन, जपानी, फ्रेंच अशा परदेशी भाषा शिकवण्यासाठी स्वतंत्र शिक्षकांची नियुक्ती केली होती. मात्र, आता परदेशी भाषा मुख्य विषय रचनेतून हद्दपार झाल्याने या शिक्षकांची गरज उरणार नाही. चौथी भाषा शिकण्याची तयारी असलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या लक्षणीय असल्यास स्वतंत्र शिक्षक नेमला जाऊ शकतो. मात्र, मुख्य विषय रचनेत इंग्रजीव्यतिरिक्त अन्य परदेशी भाषा नसल्याने जर्मन, जपानी, फ्रेंच अशा परदेशी भाषा शिक्षकांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळण्याची शक्यता प्रथमदर्शनी दिसून येते.

मुख्याध्यापक काय म्हणतात?

पुण्यातील एसपीएम पब्लिक स्कूलच्या प्राचार्य अपर्णा मॉरिस म्हणाल्या, जर्मन, जपानीसारख्या परदेशी भाषा मुख्य विषय म्हणून शिकता येणार नसल्याने केवळ तेच विषय शिकवणाऱ्या शिक्षकांचे नुकसान होऊ शकते. मात्र, त्या शिक्षकांना अन्य विषय सोपवण्याचा निर्णय संस्था स्तरावर घेणे शक्य आहे. उदाहरणार्थ, आमच्या शाळेत जर्मन भाषा शिकवणाऱ्या दोन शिक्षकांना मराठी भाषा शिकवण्यासाठी समायोजित केले आहे. अलीकडे विद्यार्थ्यांचे परदेशी भाषा शिकण्याचे प्रमाण वाढत आहे. परदेशी विद्यापीठे भारतीय विद्यार्थ्यांसाठी विशेष सवलती देतात हे त्यामागील कारण आहे. मात्र, भारतीय भाषांना महत्त्व देण्याचा निर्णय नक्कीच स्वागतार्ह आहे. हा निर्णय पूर्वीच व्हायला हवा होता. मात्र, परदेशी भाषा शिकू नयेत असे नाही. परदेशी भाषा पूर्णपणे बाजूला न टाकण्याचा विचार केला पाहिजे. आता नव्या धोरणानुसार आमच्या शाळेत जर्मन भाषा नियमित विषयाप्रमाणे न शिकवता विद्यार्थ्यांच्या निवडीनुसार अतिरिक्त विषय म्हणून शिकवला जाणार आहे. मिलेनियम स्कूलच्या शैक्षणिक प्रमुख राधिका वैद्य म्हणाल्या, जर्मन, जपानी, फ्रेंच अशा परदेशी भाषा शिकवणाऱ्या शिक्षकांना सामावून घेण्यासाठी शाळा आणि संबंधित शिक्षक यांनाच काही तरी वेगळा विचार करावा लागेल. हा वेगळा विचार प्रत्येक शाळेसाठी वेगळा असू शकतो. काही शिक्षकांचा बहुभाषिकतेच्या दृष्टीने विचार करता येऊ शकतो, तसे पर्याय विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करून द्यावे लागू शकतात. तसेच काही शिक्षकांना परदेशी भाषेऐवजी वेगळी कौशल्ये आत्मसात करावी लागू शकतात. जेणेकरून त्यांची नोकरी टिकून राहू शकते. मात्र, शिक्षक आणि संबंधित शाळा यांनाच त्याबाबत विचार करावा लागेल.

संपादकीय

देवच भूमिहीन होण्याची भीती

महाराष्ट्रातील मंदिरांच्या कळसांवर अस्वस्थतेचे मळभ दाटले आहे. सभामंडपात काळजीचे वातावरण तर गाभाऱ्यात थोडा कोलाहल आहे. कारण आहे, महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन प्रारूप अधिनियम नावाने येणारा नवा कायदा. सध्या या कायद्याचे प्रारूप सर्वसामान्यांच्या आक्षेप, हरकतींसाठी खुले करण्यात आले आहे. येत्या ५ जूनपर्यंत त्यावर आक्षेप नोंदविता येतील, पण त्यापूर्वीच हा कायदा हिंदू धर्मविरोधी असल्याचा आरोप होत आहे. प्रस्तावित कायद्याच्या विरोधात बैठका व मेळाव्यांमध्ये विचारविनिमय, तसेच आंदोलने सुरू झाली आहेत. त्यातही हा कायदा हैदराबाद इनाम कायदे, तसेच वक्फ मालमत्तांना लागू होणार नसल्याचे आधीच जाहीर झाल्याने हिंदुत्ववादी संघटना अधिक आक्रमक आहेत. सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाशी संबंधित विश्व हिंदू परिषदेने या कायद्याविरुद्ध भूमिका घेतली आहे. महाराष्ट्र मंदिर महासंघाने सरकारविरुद्ध दंड थोपटले आहेत. आमच्या विचारांचे सरकार केंद्रात व राज्यात सत्तेवर असताना असा अत्याचार करणारा कायदा कसा काय येऊ शकतो, हा या मंडळींचा करडा सवाल आहे. वरवर पाहता हा कायदा अतिशय उदात्त हेतूने आणत असल्याचे दाखविण्याचा प्रयत्न राज्य सरकारने चालविला आहे. मुख्यतः देवस्थान इनाम जमिनींची जुनी पद्धत रद्द करून पुजारी, वहिवाटदार, मिरासदार किंवा भाडेकरू व जमीन कसणाऱ्यांना त्यांची मालकी व कायमस्वरूपी हक्क देणे, हे हक्क वर्ग - १ असावेत, यासाठी काही प्रमाणात नजराणा भरून घेणे, जेणेकरून जुने हक्क व सवलती संपुष्टात येतील, भविष्यात या जमिनी महसूलदेय होतील, असे काही हेतू हा कायदा आणण्यामागे आहेत. मूळ देवस्थानाची मालकी असलेल्या गावठाणातील जमिनींवर २०११ पूर्वीचा कब्जा असेल, तर बाजारभावानुसार त्यांची किंमत देवस्थानाकडे भरून काही शर्तींनुसार तो कब्जा नियमित करता येईल. अशी अतिक्रमणे नियमित झाल्यानंतर उरलेली जमीन नव्या व्यवस्थेनुसार देवस्थानांच्या ताब्यात देणे, असे आणखी काही हेतू आहेत. सरकारला वाटते की, हे सारे केल्याने दशकानुदशके चालणारे मालमत्तांचे जुने वाद संपतील, जमीन कसणाऱ्यांना तिची मालकी मिळेल, अशा जमिनींचा व्यावसायिक वापर सुलभ होईल आणि विविध प्रकारच्या विकासासाठी राज्यभरातील जवळपास चार लाख हेक्टरहून अधिक जमीन उपलब्ध होईल. तथापि, एकूणच देवस्थानांच्या जमिनींच्या आतापर्यंतच्या भानगडी पाहता, सरकारच्या हेतूंवर संशय घेतला जाऊ शकतो. श्रीमंत देव आणि कमालीचे गरीब भक्त अशा सामाजिक विसंगतीच्या देशात मंदिरातील सोने व मालमत्ता हा नेहमीच असूयेचा विषय असतो. त्यामुळे अनेकांना या प्रस्तावित कायद्याचे आकर्षण वाटू शकेल. तथापि, या कायद्याने ज्या प्रकारे अतिक्रमणे व अवैध कब्जा नियमित होणार आहे आणि सार्वजनिक वापरासाठी जमिनी उपलब्ध करण्याच्या नावाखाली त्या मालमत्तांचा बाजार भरविला जाणार आहे, ते सारे संशयास्पद आहे. मुळात देवस्थान जमिनी हे भूमाफियांचे पहिले लक्ष्य असते. त्या जमिनींची अफरातफर, अवैध कब्जा, कागदोपत्री घोटाळे अत्यंत गंभीर असूनही राजकीय हस्तक्षेप आणि इतर कारणांनी त्यांची चौकशी होत नाही. कधीतरी चौकशीचा फार्स झाला, तरी प्रत्यक्षात कारवाई होत नाही. तीन हजारांपेक्षा अधिक मंदिराचा कारभार पाहणाऱ्या पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीच्या कार्यक्षेत्रात हजारो एकर जमीन कागदोपत्री गायब झाल्याचा आरोप आहे. जोतिबा देवस्थान, त्र्यंबकेश्वर देवस्थान यासाठी अनेकदा चर्चेत असते. अनेक प्रकरणांची सीआयडी व एसआयटी चौकशी झाली, परंतु कालांतराने सारे काही थंडावले. या घोटाळ्यांमध्ये बरेचदा राजकीय नेते गुंतलेले असतात, हे लपून राहिलेले नाही. अलीकडे संघटित गुन्हेगारीविरुद्ध आवेशाने बोलणाऱ्या मराठवाड्यातील एका नेत्यांच्या ते राज्यमंत्री असतानाच्या कारभाराच्या सुरस कथा मंत्रालयात अजूनही चर्चिल्या जातात. या पार्श्वभूमीवर, आधी झालेल्या जमीन घोटाळ्याची कोणतीही चौकशी न करता, दोषींना शिक्षा न देता, अतिक्रमणे नियमित करण्याचा, मंदिराच्या दिवाबत्तीसाठी राजेरजवाडे, वतनदारांकडून मिळालेल्या जमिनींची मालकी काढून घेण्याचा, जमिनींची मालकी थेट खुली करण्याचा प्रयत्न नव्या कायद्याने होत असेल, तर त्याला विरोध होणारच. जमिनी किंवा इतर मालमत्ता भाडेपट्ट्याने देण्याची नवी व्यवस्था आली, तर भविष्यात मंदिरांच्या उत्पन्नाचे काय होणार, देवच भूमिहीन झाले, तर या जमिनींच्या उत्पन्नातून चालणारे देवांचे उत्सव, भाविकांना अन्नदान, देखभालीची बेगमी देवस्थानांनी कशी करायची, असे अनेक प्रश्न उपस्थित होतात. भाविक भक्त आणि मंदिरांच्या व्यवस्थापनांना या प्रश्नांची उत्तरे सरकारकडून हवी आहेत.

तरुणांनी 'राजकारण' करावे आणि ते 'शिकावे'ही!

विद्यापीठांत राजकीय चळवळींना पूर्णतः मज्जाव असावा असे सुचवणे म्हणजे तरुणांसाठी 'नागरिकत्वाची प्रयोगशाळा'च नाकारणे होय.

शशी थरूर
ज्येष्ठ काँग्रेस नेते, खासदार

शैक्षणिक संस्थांच्या आवारात, राजकीय प्रभावापासून मुक्त आणि सुसंवादी वातावरण असावे अशी भूमिका केरळ उच्च न्यायालयाने व्यक्त केली. त्यावरून भारतीय शिक्षणव्यवस्थेच्या दुखऱ्या नसेवर बोट ठेवणारी चर्चा झडू लागली आहे. त्यातून एक भ्रामक द्वंद्व उभे राहते. एकतर 'शुद्ध शैक्षणिक' संस्थेतील सोवळा अराजकीय सन्नाटा किंवा मग राज्यपातळीवरील अटीतटीच्या पक्षीय संग्रामाचे अराजकता आणि हिंसा माजवणारे प्रतिबिंब! यावाचून तिसरा मार्ग जणू उपलब्धच नाही!

विद्यापीठांत राजकीय चळवळींना पूर्णतः मज्जाव असावा असे सुचवणे म्हणजे 'नागरिकत्वाची प्रयोगशाळा' ही त्यांची मूलभूत भूमिकाच नाकारणे होय; परंतु कॅम्पसमधील राजकारणाचे टीकाकार पूर्णतः चुकीचे नाहीत. मुख्य प्रवाहातील राजकीय पक्षांच्या विद्यार्थी-जीवनातील चंचुप्रवेशामुळे बौद्धिक वादविवादाची जागा बऱ्याचदा बाहुबळाने बळकावलेली दिसते; परंतु राजकारणाला बंदी घालणे हा त्यावरचा उपाय नव्हे. त्यासाठी विद्यार्थी चळवळ बाह्य पक्षीय यंत्रणांपासून मुक्त करायला हवी.

विद्यापीठ म्हणजे केवळ पदव्या निर्माण करणारा कारखाना नसतो. एक स्वतंत्र प्रौढ व्यक्ती म्हणून एखाद्या युवकाचा राज्य आणि समाज यांच्याशी परस्परसंबंध घडवणारा तो पहिला अवकाश असतो. राजकीय चर्चा, सक्रिय सहभाग आणि आंदोलन ही अत्यावश्यक शैक्षणिक साधने आहेत. मतभेदांमधून सामंजस्य कसे साधावे, संघटन कसे उभे करावे आणि सत्ताधीशांना जबाबदार कसे धरावे हे त्यातून शिकता येते. विद्यार्थ्यांचा एखादा गट फीवाढीविरुद्ध आंदोलन उभारतो, राष्ट्रीय धोरणावर चर्चा करतो तेव्हा ते सारे सुदृढ लोकशाही कार्यपद्धतीची तालीमच करत असतात. आपण या चळवळींना बंदी घालतो तेव्हा 'राजकारण हे आपणा सर्वांचे सामायिक नागरी कर्तव्य न मानता, तो घाणेरडा खेळ व्यावसायिक राजकारण्यांच्या हाती सोपवणेच श्रेयस्कर' असाच संदेश आपण पुढच्या पिढीला देत असतो.

वस्तुतः भारतीय विद्यापीठातील वातावरण विद्यापीठीय राजकारणामुळे नव्हे, तर त्या नावाखाली होणाऱ्या पक्षीय राजकारणामुळे दूषित झाले आहे. अभाविप, एनएसयूआय आणि एसएफआय या खऱ्याखुऱ्या विद्यापीठीय चळवळी नसून वेगवेगळ्या राष्ट्रीय किंवा प्रादेशिक पक्षांच्या युवा शाखा आहेत. राजकीय पक्षांकडून विद्यार्थी निवडणुकांना पैसा पुरवला जातो, तेव्हा वाचनालय, वसतिगृहातील सुविधा इत्यादी मूळ मुद्दे बाजूला पडून या निवडणुका म्हणजे राष्ट्रीय पातळीवरील ध्रुवीकरणाच्या छोट्या आवृत्त्या बनतात. राजकीय सहभाग आवश्यक; परंतु पक्षीय हस्तक्षेप मात्र घातक हे मान्य केले तर आपल्याला मध्यममार्ग शोधावा लागेल. विद्यार्थ्यांच्या स्वायत्त प्रशासनाला प्रोत्साहन देणे हे आपले उद्दिष्ट असावे. नोंदणीकृत राजकीय पक्षांपासून पूर्णतः स्वतंत्र असलेल्या विद्यार्थी संघटनांच्या दिशेने आपली वाटचाल असावी. जगातील अनेक श्रेष्ठ विद्यापीठांत 'स्वतंत्र विद्यार्थी संघटना' आहेत. तेथे उमेदवार व्यक्तिगत पातळीवर किंवा कॅम्पस अंतर्गत आघाडी करून लढतात.

विद्यापीठात पाऊल ठेवणाऱ्या पहिल्या पिढीतील किंवा ग्रामीण विद्यार्थ्यांना एनएसयूआय, अभाविप, किंवा एसएफआयसारख्या संघटना आर्थिक रसद, मार्गदर्शन आणि राजकीय सहभागासाठी आवश्यक संपर्क-जाळे पुरवू शकतात. राष्ट्रीय पातळीवरील जमवाजमव आणि पक्षशिस्त यांच्या अनुभवातून खरे राजकारण कसे चालते याचे काही धडेही मिळतात; परंतु यातील कोणत्याही बाबीसाठी बाहेरील पक्षसंघटना विद्यापीठाच्या आवारात येण्याची मुळीच आवश्यकता नसते. विद्यापीठांना राष्ट्रव्यापी राजकीय रणांगणाच्या शाखा न बनवता, राष्ट्रीय पक्षांकडून सध्या मिळणारे फायदे त्यांच्याहून अधिक योग्य आणि पारदर्शक यंत्रणांकडूनही प्राप्त करता येतील.

शैक्षणिक शिस्त आणि लोकशाहीतील चैतन्य यांच्यातील दरी मिटवण्यासाठी त्रिसूत्री सुधारणांची आवश्यकता आहे.

१) आर्थिक आणि संघटनात्मक सांगड मोडली पाहिजे. निवडणुकीतील खर्चावर कठोर बंधने घातली पाहिजेत. सर्व निधी अंतर्गत देणग्यांतून उभा केला पाहिजे किंवा तो विद्यापीठानेच पुरवला पाहिजे. नोंदणीकृत राजकीय पक्षाकडून निधी मिळाल्याचा कोणताही पुरावा मिळाल्यास उमेदवार तत्काळ अपात्र ठरवला जावा.

२) विद्यार्थी संघटनांच्या घटना शैक्षणिक गुणवत्ता, विद्यार्थी कल्याण आणि स्थानिक सामाजिक न्याय अशा प्रशासकीय मुद्द्यांवरच केंद्रित राहाव्यात यासाठी विद्यापीठाचे प्रशासन आणि विद्यार्थी प्रतिनिधींनी एकत्रितपणे प्रयत्न करायला हवेत. सर्व लक्ष स्थानिक घटकांवरच केंद्रित झाल्यास बाहेरच्या पक्षांना हस्तक्षेप करण्यात स्वारस्य उरणार नाही.

३) राजकीय वादविवादावर बंदी घालण्याऐवजी विद्यापीठांनी त्याला संस्थात्मक स्वरूप द्यावे. अंदाधुंद मेळावे टाळून कॅम्पसनी नियोजनबद्ध वादविवाद, टाऊन हॉल्स किंवा नागरिक मंच आयोजित करावेत. येथे विद्यार्थ्यांनी पक्षीय शिक्के बसण्याचे किंवा शारीरिक हल्ल्यांचे भय न बाळगता राष्ट्रीय प्रश्नांवर-अगदी वादग्रस्त प्रश्नांवरही मुक्त वादविवाद करावेत. शैक्षणिक संस्थेने स्वतः तटस्थच राहावे; परंतु विद्यार्थ्यांना भूमिका घेता यावी, झपाटून जाता यावे, 'राजकीय' होता यावे, यासाठी त्यांना संरक्षित, सुरक्षित अवकाश मात्र जरूर द्यावा.

नागरिकत्वाचे शिक्षण हे अभियांत्रिकी किंवा इतिहासाच्या शिक्षणाइतकेच महत्त्वाचे आहे. राजकीय क्रियाशीलतेवर बंदी घातली तर आपण केवळ संवेदनशून्य तंत्रज्ञांची पिढी तयार करू. याउलट पक्षीय राजकारणाला रान मोकळे सोडले तर कट्टर, झापडबंद समर्थकांची पिढी घडवू; परंतु स्वतंत्र विद्यार्थी चळवळीचा मार्ग निवडला तर विचार करणाऱ्यांची पिढी आकाराला येईल.

अन्वयार्थ

'ट्रॅप'मध्ये अडकलेले ८५ टक्के आरोपी निर्दोष कसे सुटतात?

लाच प्रकरणात केवळ १४ ते १६ टक्के गुन्ह्यांमध्ये शिक्षा होते. दोषसिद्धी आणि शिक्षेचे प्रमाण वाढविण्यामधले अडथळे नेमके कोणते आहेत?

राजेश निस्ताने
वृत्तसंपादक, लोकमत, नांदेड

भ्रष्टाचाराच्या उघडकीस येणाऱ्या प्रकरणांमध्ये देशात महाराष्ट्र 'टॉप'वर आहे. त्यातही महसूल, पोलिस, जिल्हा परिषद या विभागांचा क्रमांक वर आहे. जेवढ्या संख्येने ट्रॅप होतात, त्या तुलनेत शिक्षा मात्र होत नाही. आजघडीला एसीबीच्या खटल्यांमध्ये शिक्षा होण्याचे प्रमाण अवघे १४ ते १६ टक्के एवढे आहे. त्यातही वर्ग-३ च्या कर्मचाऱ्यांचीच संख्या अधिक आहे. अर्थात ८५ टक्के प्रकरणांतील आरोपी ट्रॅप होऊनही निर्दोष सुटतात. त्यामुळे एसीबीच्या ट्रॅपबाबत सरकारी यंत्रणेमध्ये भीती दिसत नाही.

वर्षानुवर्षे खटला चालणे, तो चालविण्याबाबत न्यायालयीन घटकांमध्ये असलेली अनास्था, खटल्यादरम्यान महत्त्वाचे साक्षीदार सेवानिवृत्त होणे, मरण पावणे, पैरवी अधिकारी, सरकारी वकिलांकडून पंच-साक्षीदारांना कोर्टात गुन्हा सिद्ध होण्याच्या दृष्टीने मार्गदर्शन न मिळणे, तपास अधिकारी, ट्रॅप अधिकारी यांना खटल्यापूर्वी संबंधित कागदपत्रे न मिळणे, फिर्यादी उलटणे, सरकारी पंचांनी कोर्टात साक्ष देताना (कारवाई होईल म्हणून थेट फितूर न होता) जाणीवपूर्वक संशय निर्माण करणे, तांत्रिक पुराव्यातील विसंगती.. आदी कारणे निकाल आरोपींच्या बाजूने लागण्यासाठी कारणीभूत ठरतात.

आजही अनेक जिल्ह्यात २०१५-१६ मध्ये ट्रॅप झालेली प्रकरणे अद्याप बोर्डावर आलेली नाहीत. दहा-दहा वर्षे खटले प्रलंबित राहणार असतील, तर लाचखोरांना शिक्षा होईल कशी? या दीर्घ काळात पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेलेले असते. घटनाक्रमाचा विसर पडतो. मग, कोर्टात प्रकरण सैल पडते. ते आरोपीच्या फायद्याचेच ठरते. अनेकदा ट्रॅप होतात, पण त्याच्या दोषारोपपत्राला मंत्रालयातून मंजुरीच दिली जात नाही. पर्यायाने एसीबीला मग अशा प्रकरणात 'फायनल' पाठवावे लागते. एसीबीचे परिश्रम, शासनाचा खर्च पाण्यात जातो. दुसरीकडे एसीबीबाबतही तक्रारदारांमध्ये तेवढा विश्वास राहिलेला नाही. स्थानिक स्तरावर तक्रार 'लीक' होईल, या भीतीने अनेकदा दुसऱ्या जिल्ह्यातील एसीबीकडे जावून तक्रार नोंदविली जाते. एसीबीत पोस्टिंग मिळविण्यासाठी 'वजनदार' राजकीय वशिलेबाजी केली जाते. वन स्टेपची भुरळ किंवा पदोन्नतीचा पुढील मार्ग सुकर करण्यासाठी नाईलाजाने एसीबीत आलेले काही अधिकारी मात्र टाइमपास करतात अन् सोयीची पोस्टींग मिळाली की निघून जातात. इतरांवर ट्रॅप करणाऱ्या एसीबीतच अनेक ठिकाणी भ्रष्टाचार फोफावला आहे. शासकीय अधिकारी, कर्मचारी किंवा लोकसेवकाच्या व्याख्येत मोडणाऱ्या व्यक्तीने लाच स्वीकारली किंवा अपसंपदा बाळगली, तर त्याच्यावर एसीबी गुन्हा दाखल करते. परंतु, एसीबीतील अधिकारीच आरोपीला 'रिलीफ' देण्याच्या नावाखाली 'उलाढाल' करत असतील तर?

गेल्या पाच-दहा वर्षांत एसीबीला 'क्राइम ब्रँच'पेक्षाही अधिक महत्त्व आल्याने एसीबीच मेन ब्रँच बनली आहे. काही वर्षांपूर्वी नागपुरात एका महिला कर्मचाऱ्याने वरिष्ठांशी झालेल्या वादानंतर एसीबीला शासनाच्या कोणत्या विभागाकडून किती हप्ता येतो याची यादीच उघड केली होती. या चढत्या आलेखाची भुरळ पडल्यामुळेच आता एसीबीमध्ये पोस्टिंगसाठी रस्सीखेच पहायला मिळते. त्यात रिजन-महानगरे 'टॉप'वर आहेत. एसीबीत जिल्ह्याचा बॉस बनावे यासाठी पोलिस अधिकाऱ्यांची धडपड असते. त्यामागे ना बंदोबस्त, ना युनिफार्म हेही एक कारण. ट्रॅप किंवा अपसंपदेचा गुन्हा दाखल झाल्यानंतर आरोपी घाबरलेला असतो, त्याचाच फायदा उचलला जातो.

निनावी आणि मिसमॅच तक्रारींची दखल घेऊ नये, असे शासनाचे स्पष्ट आदेश आहेत. मात्र, त्यानंतरही एसीबी अशा निनावी तक्रारींच्या आडून 'प्रतिष्ठित पंटर' मार्फत संबंधिताला धडकी भरविणारा मेसेज पोहोचवितात. त्यातूनच पुढे यशस्वी 'तडजोड' केली जाते. राजकीय नेतेही त्यात मागे नाहीत. काही राजकीय नेतेही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मालमत्तेची एसीबीमार्फत खुली चौकशी करण्याचे पत्र देतात. लगेच त्यांचे कार्यकर्ते अधिकाऱ्याची 'भेट' घेतात, नंतर चौकशीची मागणी थंड बस्त्यात टाकली जाते. एसीबीच्या धाडीत शक्यतोवर कर्मचारी आणि कनिष्ठ दर्जाचे अधिकारीच अडकतात. बडे मासे मात्र सुटतात. वरिष्ठांची तर बहुतांश सेटिंग असतेच. इतरांना लाचखोर म्हणून अटक करणाऱ्या 'एसीबी'वरच संशयाची सुई स्थिरावत असेल तर कोण कोणावर ट्रॅप करणार, हा खरा प्रश्न आहे.

rajesh.nistane@lokmat.com

जगभर

दोन्ही पाय नसताना केवळ हातांनी एव्हरेस्ट सर!

रुस्तम नाबिएव. रशियन हवाई दलाचे माजी पॅराट्रूपर. सैबेरियात असताना १२ जुलै २०१५ रोजी रात्री त्यांची लष्करी प्रशिक्षण छावणी कोसळली. सारे सैनिक त्यावेळी गाढ झोपेत होते. त्यातलाच एक रुस्तम नाबिएव. रुस्तम अतिशय गंभीर जखमी झाला. तो जगेल की नाही याचीही शाश्वती नव्हती. त्याच्यावर १६ शस्त्रक्रिया कराव्या लागल्या आणि दोन्ही पाय कापावे लागले. तो जिवंत राहिला, तरी सगळ्यांच्या दृष्टीनं त्याचं आयुष्य आता संपलं होतं. पण रुस्तमच्या दृष्टीनं काहीच संपलेलं नव्हतं. त्याच्यासाठी त्या दिवसापासून नवं आयुष्य सुरू झालं.

रुस्तमनं आपल्या अपंगत्वासमोर हार मानली नाही. त्याच्याकडे पाहिल्यानंतर लोक जेवढे हळहळायचे, तेवढी त्याची जिद्द बुलंद होत गेली. एकामागून एक शस्त्रक्रिया आणि दुखणी, वेदनांतून सावरल्यावर त्यानं मनाशी खुणगाठ बांधली, आपले दोन्ही पाय गेलेले असले तरी आपली हिंमत अजूनही बुलंद आहे. या हिमतीच्या बळावर आपण काहीही करू शकतो. त्यानं सुरुवातीला स्लेज हॉकी खेळायला सुरुवात केली. त्यात प्रावीण्य मिळवलं आणि नंतर व्यावसायिक स्लेज हॉकीही तो खेळायला लागला. मॉस्कोस्थित फिनिक्स क्लबकडून तो खेळला.

ते करत असतानाच प्रभावशाली ब्लॉगर आणि फिटनेस प्रशिक्षक बनला. स्वतःच्या अपंगत्वाचा कुठलाही बाऊ न करता, या परिस्थितीतही काय काय करता येऊ शकतं, हे त्यानं दाखवून दिलं. स्वतःच्या उदाहरणातून इतरांना प्रेरणा आणि प्रोत्साहन देत गेला. त्यामुळेच त्याचा मूळ प्रदेश बश्कोर्तोस्तानमध्ये मानवाधिकार परिषदेचे सदस्य म्हणून त्याची नियुक्ती करण्यात आली. पण एवढ्यावरही त्याला स्वस्थ बसवलं नाही. त्यानं विचार केला, पाय नसले म्हणून काय झालं, आपण गिर्यारोहणही करू शकतो. केवळ

हातांच्या बळावर तो गिर्यारोहण करू लागला. सुरुवातीला छोटे-छोटे डोंगर, शिखरं तो चढून गेला. विश्वास आणि हिंमत आणखी बुलंद झाल्यावर मग त्यानं मागे वळून पाहिलं नाही.

२०२० मध्ये युरोपमधील सर्वात उंच शिखर माउंट एलब्रस, २०२१ मध्ये माउंट मानस्लू, २०२१ मध्ये माउंट किलिमांजारो आणि माउंट काझबेक, २०२२ मध्ये दक्षिण अमेरिकेतील अकोंकागुआ शिखर त्यानं 'पादाक्रांत' केलं!

कोणत्याही पट्टीच्या गिर्यारोहकाचं जे स्वप्न असतं, ते त्याला आता खुणावू लागलं, ते म्हणजे एव्हरेस्ट सर करण्याचं. त्यादृष्टीनंही त्यानं प्रयत्न सुरू केले आणि २० मे २०२६ रोजी त्यानं नवा इतिहास रचला. दोन्ही पाय नसताना, कृत्रिम अवयवांचा वापर न करता केवळ हातांच्या बळावर ८,८४८.८६ मीटर उंच जगातील सर्वोच्च शिखर एव्हरेस्ट त्यानं सर केलं!

एव्हरेस्ट सर करणारा जगातला तो चौथा अवयवविच्छेदित गिर्यारोहक असला तरी केवळ हातांनी एव्हरेस्ट चढून जाणारा जगातला तो पहिलाच व्यक्ती आहे! मार्क इंग्लिस हे गुडघ्याखाली दोन्ही पाय गमावलेले पहिले व्यक्ती होते, ज्यांनी २००६ मध्ये कृत्रिम अवयवांच्या मदतीनं एव्हरेस्ट सर केलं होतं. आपल्या ३४ व्या वाढदिवसानिमित्त त्यानं आपल्या सर्वांत मोठ्या स्वप्नाच्या दिशेनं पाऊल टाकलं आणि दुर्दम्य इच्छाशक्तीच्या बळावर आपलं हे स्वप्न केवळ पूर्णच केलं नाही, तर गिर्यारोहणाच्या क्षेत्रात आपलं नाव सुवर्णाक्षरांनी नोंदवलं. 'जोपर्यंत तुमचा श्वास सुरू आहे, तोपर्यंत संघर्ष सुरू ठेवा..', हे आपलं म्हणणं त्यानं खरं करून दाखवलं!

जनमन

वनविभागाने संरक्षणाची जबाबदारी घ्यावी

चंद्रपूर जिल्ह्यातील जंगलांत तेंदूपत्ता संकलनासाठी अनेक ग्रामीण लोक जात असतात. हंगामात ग्रामस्थांच्या रोजगाराचं हे एक प्रमुख साधन आहे. सध्या चंद्रपूर जिल्ह्यात वाघांची संख्या भरपूर प्रमाणात वाढलेली आहे. त्यामुळे तेंदूपत्ता संकलनासाठी जाणाऱ्या लोकांवर वाघांचे हल्ले होण्याचे प्रमाणदेखील अनेक पटींनी वाढलेले आहेत. ही अतिशय चिंताजनक बाब आहे. वाघांचे हल्ले कसे रोखावे हे वनविभागासमोर एक मोठे आव्हान आहे. याविषयी चंद्रपूर जिल्ह्यातील काही वनसंवर्धकांचं असं मत आहे की, शासनाने तेंदूपत्ता संकलनावर सरसकट बंदी आणावी; परंतु दुसरीकडे अनेक संवर्धकांचं असं म्हणणं आहे की, तेंदूपत्ता संकलन हे ग्रामीण लोकांचं महत्त्वाचं रोजगाराचं साधन आहे. त्यामुळे या कामावर सरसकट बंदी आणता येणार नाही. जर बंदी आणायचीच असेल तर आधी गावकऱ्यांना रोजगाराचे साधन उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे.

जोपर्यंत लोकांना रोजगाराचे इतर साधन उपलब्ध होत नाही, तोपर्यंत तेंदूपत्ता हंगामात लोक धोका पत्करूनसुद्धा तेंदूपत्ता संकलनासाठी जातीलच. म्हणून लोकांच्या संरक्षणासाठी वनविभागाला काही पावले उचलणे अत्यंत आवश्यक आहे. वनविभागाच्या निगराणीत हे कार्य सुरू ठेवावे. त्याकरिता वनविभागाने लोकांना तेंदूपत्ता संकलनासाठी एक वेळ ठरवून द्यावी. त्या वेळेत वनविभागाचे कर्मचारी लोकांच्या संरक्षणासाठी तैनात ठेवावे. वाघांपासून लोकांच्या सुरक्षिततेसाठी आवश्यक त्या उपाययोजना तयार ठेवाव्यात. वेळ संपल्यावर सर्वांना जंगलातून निघून जाण्यास सांगावे. यामुळे लोकंही सुरक्षित राहतील आणि वनवणव्यांवरसुद्धा नियंत्रण ठेवता येईल.

- **संजीव हरिदास हेडाऊ,** नागपूर

समकालीन महत्त्वाचे मुद्दे मांडणारी, नवी चर्चा सुरू करणारी वाचक-पत्रे या स्तंभामध्ये प्रसिद्ध केली जातील. आपली पत्रे येथे पाठवा : **janman@lokmat.com**

सेतू

ऑस्ट्रेलियातल्या लडिवाळ पक्ष्यांची मंजूळ गोष्ट सांगायची, तर..

ऑस्ट्रेलियातले पक्षी शतपावलीला निघावं तसे रस्त्यावरून फिरत असतात. गाड्या आल्या तरी उडत नाहीत. शेवटी चारचाकी गाड्या वेग कमी करतात...

हिमानी नीलेश
सीनिअर लायब्ररी ऑफिसर, ॲडलेड, ऑस्ट्रेलिया

ऑस्ट्रेलियातल्या माझ्या घरी एक आकाशी रंगाचा आणि त्याच्या जोडीला पिवळ्या रंगाचा असे दोन बजेरिअर पक्षी आहेत. आपल्याकडे भारतात लव्हबर्ड्स असतात तसे. त्यातला आकाशी (स्किपी), तर फार लाघवी आहे. तो पोपटाप्रमाणे, 'मी पुणेकर आहे, हॅलो एव्हरीबडी हॅव अ सीट' अशी अख्खी दोन वाक्ये नीटच बोलत असे. मग दुसरा पिवळा पक्षी आल्यावर ते आपापसात त्यांच्यातच इतके बोलू लागले की स्किपी आम्ही आधी शिकवलेलं सगळं पार विसरून गेला. पिवळा पक्षी लहान आहे, पण आक्रमक आहे. त्याला आमची म्हणावी तशी ओढ नाही. स्किपी मात्र आमच्या अंगाखांद्यावर असतो. यांच्या पिंजऱ्याचं दार कायम उघडं असतं आणि त्यांना वाटेल तेव्हा ते आमच्या घरात फिरतात. हातावर बसून कोथिंबीर, पालक खातात. रोजच्या बिया तर असतातच. स्किपीला आम्ही माझी सहकारी तान्याकडून आणलं. तान्याचा नवरा खरं तर पक्षीच जन्माला यायचा असं ती नेहमी म्हणे. एके दिवशी तिनं मला तिच्या परसातले सात मोठेच्या मोठे पिंजरे दाखवले त्यात पक्ष्यांच्या रंगांची उधळण होती. काही अंडी घरट्यातून पडताना वाचवलेले कॉकटिएल्स तर बरेचसे बजीज. त्यांची देखभाल अँथनी निगुतीनं करीत असे.

माझ्या लहानपणी माझ्या घरी पोपट होते. मग त्या मुद्द्यावरून माझी आणि तान्याची चांगलीच गट्टी जमली. गुलाबी आणि राखाडी गालाज, पिवळा मोठा तुरा असणारे कोकटोज, समुद्रावरचे सीगल्स, इथले स्थानिक असे ककूबारा आणि सगळ्यात देखणे असे

सप्तरंगी पोपट म्हणजे लोर्किट्स अशा हरतऱ्हेच्या पक्ष्यांवर आम्ही बोलू लागलो. इथले पक्षी रस्त्यावरून शतपावलीला निघावं तसे फिरत असतात. गाड्या आल्या तरी मुळीसुद्धा उडत नाहीत. चारचाकी गाड्या नाकी दम येऊन वेग कमी करतात मग हे मनात असेल तर उडतात, नाहीतर खुशाल संथपणे चालत जिकडे जायचं असेल तिकडे जातात.

ऑस्ट्रेलियातल्या मैना इतर पक्ष्यांचं जिणंच मुश्कील करतात. इतर पक्ष्यांना हुसकावून लावणं हा त्यांचा प्रमुख उद्योग! असाच एक कोकटीएल मैनांपासून जीव वाचवत आमच्या लायब्ररीच्या बागेत आला. मी हात पुढे केल्यावर अल्लद हातावर आला. त्याचा तुरा माझ्या गालावर प्रेमानं घासू लागला तेव्हाच मी ओळखलं हा पाळीव असणार. त्याचा फोटो मग इथल्या हरवलेल्या पक्ष्यांच्या वेबसाइटवर मी त्वरित टाकला.

एक कॅन्सरग्रस्त आजोबा त्याचे पालक होते. ते जेव्हा पुन्हा भेटले तेव्हा आजोबा हरवलेला नातू भेटावा तसे हमसून रडू लागले. आजोबांना मग मी ठरवून मुलांच्या गोष्टी सांगायच्या तासाला लायब्ररीत बोलावलं .'पक्ष्यांना त्यांचे रंग कसे लाभले?' ही बारडी भाषेतील मेरी अल्बर्टची बोधकथा मी सांगू लागले. एका कबुतराला जखम होते. मदत करणाऱ्या पक्ष्यांना त्यांच्या मदतीच्या प्रमाणात बहुरंग मिळतात तर मदत न करणारा कावळा मात्र काळाच राहतो. आजोबा इवलं मूल होऊन ऐकत होते. त्यांचा चेहरा पाहून मी त्याहून लहान मूल झाले होते.

आज वळून पाहताना वाटतं, असे सप्तरंगी क्षण घट्ट घट्ट मुठीत पकडण्यासाठी आसुसलेली मी त्यांच्या ऐंशी वर्षांच्या अनुभवी डोळ्यांनी टिपली असेल का?

himaninilesh123@gmail.com

सेतू : जगभरातील मराठी माणसांच्या जगण्यातले रूपरंग शोधणारा हा स्तंभ. तुम्ही स्वतः, तुमचे आप्त परदेशात राहात असाल, तर तुमचे अनुभव जरूर पाठवा. निवडक लेखनाला प्रसिद्धी. **ईमेल करा :** setu@lokmat.com

तिरकस आणि चौकस

गजानन घोंगडे

हे पत्र लोकमत मीडिया प्रा. लिमिटेडच्या वतीने मुद्रक व प्रकाशक **बालाजी मुळे** यांनी प्लॉट नं. ए - ८१८ इंडस्ट्रियल एरिया, एम.आय.डी.सी., महापे, नवी मुंबई येथे मुद्रित करून 'लोकमत', पृथ्वी पार्क, सेक्टर ३०, सानपाडा, नवी मुंबई कार्यालय - ४००७०५ येथून प्रसिद्ध केले. ● दूरध्वनी क्र : ०२२ ४६०४१७८४
● **मुंबई कार्यालय :** लोकमत मीडिया प्रा. लिमिटेड, तिसरा मजला, पारिजात हाउस, प्लॉट नं. १०७६, आपटे इंडस्ट्रियल इस्टेट, लक्ष्मीनरसिंग पपन मार्ग, डॉ. ई मोझेस रोडसमोर, गांधीनगर, वरळी, मुंबई, ४०००१८. ● दूरध्वनी क्र : ०२२- ४६०३५९३०, ०२२- ४७५०७९४६ ● **ठाणे कार्यालय :** वेस्टर्न व्ह्यू, श्री गजानन महाराज चौक, वारकरी भवनाजवळ, ठाणे, फोन : २५४४१९०५, २५३८१७७४ ● **नवी मुंबई कार्यालय :** पृथ्वी पार्क, सेक्टर ३०, सानपाडा, नवी मुंबई ४००७०५. फोन : ०२२ ४६०४१७८४ ● संस्थापक संपादक : **स्व. जवाहरलाल दर्डा** ● मानद संपादिका : **श्रीमती उषाताई दर्डा** ● चेअरमन, एडिटोरियल बोर्ड : **डॉ. विजय दर्डा** ● एडिटर इन चिफ : **राजेंद्र दर्डा** ● समूह संपादक : **विजय बाविस्कर**
● संपादक : **अतुल कुलकर्णी*** (*पी. आर. बी. कायद्यानुसार संपादकीय जबाबदारी यांची आहे.)
'लोकमत'मधील लेखांचे हक्क राखून ठेवले आहेत. लोकमत ® हे चिन्ह लोकमत मीडिया प्रायव्हेट लि. चे. व्यापारचिन्ह आहे.

चिंतन

एसआईआर आयोग का हक व निष्पक्षता के लिए जरूरी

सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में कुछ गलत नहीं किया और उसे यह कराने का पूरा अधिकार है। बिहार की मतदाता सूची के एसआईआर का आदेश देकर आयोग ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम का भी कोई उल्लंघन नहीं किया। अदालत ने तीन सवालों की जांच की थी। क्या निर्वाचन आयोग के पास एसआईआर कराने की शक्ति है, क्या एसआईआर के तहत की गई जांच किसी वैध उद्देश्य पर आधारित है, और क्या अपनाई गई प्रक्रिया जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत या उनका उल्लंघन करने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर के पक्ष में निर्वाचन आयोग के तर्कों से सहमति जताई। कोर्ट ने दो टूक कहा कि इससे मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित हुई है और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों में सहायता मिली है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने वे सभी नैरेटिव ध्वस्त कर दिए हैं, जो एसआईआर के खिलाफ फैलाए जा रहे थे। सर्वोच्च अदालत ने यह भी कहा कि एसआईआर मतदाता सूचियों में नाम हटाने की चरणबद्ध प्रक्रिया, दावे और आपत्तियां दर्ज कराने का अवसर शामिल था। असल में एसआईआर का विरोध पूरी तरह से राजनीतिक था। विरोध कर रहे पक्ष ने कभी यह सवाल नहीं उठाया कि आयोग के किस कदम से एसआईआर की प्रक्रिया में गलत हो रहा है। वह आयोग के हर आंकड़े को अपने हिसाब से मनमाना बताने की कोशिश करता रहा। विपक्ष ने कई बार ऐसे तथ्य कोर्ट में पेश किए, जो पूरी तरह गलत थे। इस पर कोर्ट ने नाराजगी भी जताई। विपक्ष की शंकाओं का समाधान करने के लिए कोर्ट ने केवल पहचान पत्रों की संख्या बढ़ाई, बल्कि आयोग को वे सुरक्षा उपाय भी शामिल करने को कहा जिनकी मांग विपक्ष की ओर से की गई। असलियत तो यह थी कि विपक्ष ने कभी एसआईआर की शुद्धता पर जोर नहीं दिया। उसकी कोशिश पहले दिन से ही एसआईआर को रद्द कराने की रही। एसआईआर बहुत बड़ी प्रक्रिया है और करोड़ों लोगों का डाटा शुद्धता से मैच करना आसान नहीं है। हो सकता है उसमें कोई कमी रह जाए, लेकिन उसे ठीक कराने का विकल्प हर मतदाता के पास मौजूद था। विरोधाभासी तथ्य यह रहा कि खुद विपक्षी नेता वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का मुद्दा उठाते रहे और जब उसे ठीक करने की कोशिश हुई तो उसे रोकने में लग गए। सर्वोच्च अदालत ने साफ कर दिया कि एसआईआर संविधान की ऐसी प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य संविधान द्वारा संरक्षित उद्देश्यों को आगे बढ़ाना है। इस फैसले ने अन्य राज्यों में शुरू होने जा रही एसआईआर प्रक्रिया पर भी मुहर लगा दी है। यह फैसला बिहार में एसआईआर को लेकर है, लेकिन इसका असर अन्य राज्यों संबंधित विवादों पर भी नजर आएगा। पश्चिम बंगाल में अनेक लोगों का नाम अंतिम मतदाता सूची ने नहीं आ सका था, इस मामले पर भी सुनवाई चल रही है। विपक्ष ने जोर-शोर से अपने समर्थकों के नाम काटने का आरोप लगाया था, लेकिन अब बंगाल में सरकार बदलने के बाद जिस तरह से बांग्लादेश सीमा पर घुसपैठियों का जमावड़ा वापस जाने के लिए लगा हुआ है, वह चुनाव आयोग द्वारा बड़ी संख्या में घुसपैठियों नाम काटने के कदम की पुष्टि ही करता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए आयोग से कहा कि जिन लोगों के नाम नागरिकता की पुष्टि न होने की वजह से कटें है, वह उनका ब्योरा संबंधित विभाग को दे ताकि ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो सके।

विश्लेषण

डॉ. जयंतीलाल भंडारी

एफटीए, सरल कानून से बढ़ेंगे रोजगार

इन दिनों भारत की अर्थव्यवस्था से संबंधित वैश्विक आर्थिक संगठनों की रिपोर्टों में दो बातें रेखांकित हो रही हैं। एक, पश्चिम एशिया संकट के कारण देश की विकास दर में तेजी से गिरावट आ रही है। दो, भारत के तेजी से बढ़ते द्विपक्षीय व्यापार समझौतों और मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) को भारत के हित में अधिक लाभप्रद बनाने के मद्देनजर पूरे देश में जमीनी स्तर पर लागू की गई चार नई श्रम संहिताएं (लेबर कोड) जान फूंकते हुए दिखाई दे सकेंगी। उम्मीद करें कि पश्चिम एशिया संकट की चुनौतियों के बीच हाल ही में देशभर में जमीनी स्तर पर चार नई श्रम संहिताओं के तहत लागू किए गए नए सरल श्रम कानून देश के बढ़ते व्यापार समझौतों के लाभप्रद क्रियान्वयन में अहम भूमिका निभाएंगे।

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए कहा कि भारत द्वारा किए जा रहे वैश्विक व्यापार समझौते युवाओं के रोजगार व विकास को ध्यान में रखते हुए किए जा रहे हैं और इससे नए अवसरों के दरवाजे खुल रहे हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में इन दिनों भारत की अर्थव्यवस्था से संबंधित वैश्विक आर्थिक संगठनों की रिपोर्टों में दो बातें रेखांकित हो रही हैं। एक, पश्चिम एशिया संकट के कारण देश की विकास दर में तेजी से गिरावट आ रही है। दो, भारत के तेजी से बढ़ते द्विपक्षीय व्यापार समझौतों और मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) को भारत के हित में अधिक लाभप्रद बनाने के मद्देनजर पूरे देश में जमीनी स्तर पर लागू की गई चार नई श्रम संहिताएं (लेबर कोड) जान फूंकते हुए दिखाई दे सकेंगी।

इन चार श्रम संहिताओं-मजदूरी संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता और व्यावसायिक सुरक्षा संहिता के तहत नए सरल श्रम कानून उद्योग-कारोबार को मजबूती और विकास की नई संभावनाओं को आकार देते हुए दिखाई दे सकेंगे। उल्लेखनीय है कि इस समय वैश्विक अनिश्चितता और पश्चिम एशिया संकट के कारण घटती हुई विकास दर को थामने तथा विकास दर को बढ़ाने के मद्देनजर भारत द्विपक्षीय व्यापार समझौतों और एफटीए की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडौलाइड्स के बीच द्विपक्षीय वार्ता के दौरान वर्ष 2029 तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करने की प्रतिबद्धता जताई गई है। पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग दोगुना हुआ है। इसी तरह पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी ने पांच देशों-संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की आधिकारिक यात्रा के दौरान इन देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार के महत्वपूर्ण समझौते किए हैं। इनमें सेमीकंडक्टर, ऊर्जा, रक्षा और क्रिटिकल मिनरल्स पर समझौते प्रमुख हैं। इन देशों की 50 बड़ी वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों (सीईओ) के द्वारा भारत में अपनी व्यापार विस्तार योजनाओं के लिए लगभग 40 अरब डॉलर की राशि का निवेश संकल्प जताया गया है। यह भी महत्वपूर्ण है कि इस यात्रा के दौरान ओस्लो में संपन्न भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन यूरोप के नॉर्डिक क्षेत्र के साथ भारत के रिश्तों को व्यापक बनाने के मामले में अहम रहा है। नॉर्डिक देशों में उत्तरी यूरोप के डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और स्वीडन जैसे देश शामिल हैं। अब भारत इनके साथ पारंपरिक कूटनीतिक रिश्तों के बजाय गहन रणनीतिक साझेदारी की दिशा में बढ़ रहा है। नार्डिक देशों की कई बड़ी कंपनियों में से कई कंपनियां पहले से ही भारत में काफी अधिक निवेश कर चुकी हैं और उनका भारत में कुल निवेश लगभग 180 अरब डॉलर के आसपास है। नार्डिक देशों ने अगले 15 वर्षों में भारत में 100 अरब डॉलर का निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई है और इसके बदले में भारत ने इन देशों की रक्षा कंपनियों को रक्षा उद्योग गलियारे में 100 फीसदी विदेशी निवेश पहुंच प्रदान करना सुनिश्चित किया है। उल्लेखनीय है कि भारत एफटीए की डगर पर भी तेजी से बढ़ रहा है। पिछले माह 27 अप्रैल को भारत और न्यूजीलैंड के बीच एक ऐतिहासिक एफटीए पर हस्ताक्षर हुए हैं। न्यूजीलैंड के

साथ किए गए इस एफटीए का अत्यधिक मजबूत पक्ष भारत से सेवा निर्यात बढ़ाना और भारत से पेशेवरों को न्यूजीलैंड में अच्छे अवसरों के लिए आगे बढ़ाना भी है। यह एफटीए भारत की प्रतिभाओं, स्टार्टअप्स और नवाचार के लिए एक मजबूत बुनियाद प्रदान करता है। यह भी महत्वपूर्ण है कि पिछले वर्ष 2025 में भारत के द्वारा ब्रिटेन और ओमान के साथ किए गए एफटीए का भी इसी वर्ष 2026 में आगामी महीनों में कार्यान्वयन शुरू होगा। साथ ही, भारत-यूरोपीय संघ एफटीए का क्रियान्वयन भी इसी वर्ष संभावित है। इस समझौते को सभी समझौतों की जननी कहा गया है।

अब मॉरीशस, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), ऑस्ट्रेलिया और चार यूरोपीय देशों आइसलैंड, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और लिकटेंस्टाइन के समूह यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन (एफ्टा) के साथ सफलतापूर्वक कार्यान्वित हो रहे एफटीए के और अधिक लाभ मिलते हुए दिखाई देंगे। कनाडा, इस्राइल, रूस, पेरू, चिली, दक्षिण अफ्रीका और मेक्सिको के साथ मुक्त व्यापार समझौतों पर काम में तेजी आएगी। निश्चित रूप से भारत के बढ़ते हुए व्यापार समझौतों के अत्यधिक सकारात्मक परिदृश्य के बीच भारत में लागू नए सरल श्रम कानूनों की नई लाभप्रद अहमियत दिखाई दे रही है। नए श्रम कानूनों से व्यापार समझौतों का प्रभावी रूप से लाभप्रद क्रियान्वयन होगा। नए श्रम कानूनों से श्रमिकों की सुरक्षा में वृद्धि और बेहतर रोजगार ढांचे के लिए नियमों का आधुनिकरण उभर कर दिखाई दे रहा है। वहीं, इनसे उद्योग-कारोबार को रफ्तार मिलेगी। ये श्रम कानून देश में स्वतंत्रता के बाद से सबसे व्यापक और प्रगतिशील श्रम-उन्मुख सुधार हैं। ये नई श्रम संहिताएं सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा, न्यूनतम और समय पर मजदूरी का भुगतान, सुरक्षित कार्यस्थल और नारी शक्ति व युवा शक्ति के लिए लाभकारी अवसरों के लिए एक मजबूत नींव के रूप में काम करेंगी। साथ ही भविष्य के लिए एक ऐसे इकोसिस्टम का निर्माण करेंगी, जो श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करेगा। निसंदेह, नई श्रम संहिताओं ने श्रम नियमों को सरल, निष्पक्ष और नए दौर के कामकाजी वातावरण के अधिक अनुकूल बना दिया है। ये नई संहिताएं श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करने, सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा में सुधार करने, व्यवसायों के लिए नियमों का अनुपालन करना आसान बनाने और बढ़ती अर्थव्यवस्था में अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने के मद्देनजर अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं।

नई श्रम संहिताओं के तहत श्रमिकों, उद्योगों और सरकार के हितों से संबंधित बहुआयामी लाभ उभरकर दिखाई दे रहे हैं। अब नियोक्ताओं को सभी श्रमिकों को नियुक्ति पत्र जारी करना होगा तथा गिग और प्लेटफॉर्म कामगारों सहित पूरे श्रमबल को सामाजिक सुरक्षा कवरेज प्रदान करना होगा। न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने और 40 वर्ष से अधिक आयु के श्रमिकों के लिए मुफ्त वार्षिक स्वास्थ्य जांच प्रदान की जाना भी सुनिश्चित की गई है। अब तय अवधि के लिए ठेके पर काम करने वाले कामगारों को स्थायी श्रमिकों के बराबर सभी लाभ मिलेंगे और वे 5 साल के बजाय सिर्फ एक साल बाद ग्रेच्युटी पाने के हकदार होंगे। हाल के दशकों में भारत से सेवाओं का निर्यात वस्तुओं की तुलना में कहीं तेजी से बढ़ा है। उम्मीद करें कि पश्चिम एशिया संकट की चुनौतियों के बीच हाल ही में देशभर में जमीनी स्तर पर चार नई श्रम संहिताओं के तहत लागू किए गए नए सरल श्रम कानून देश के बढ़ते व्यापार समझौतों के लाभप्रद क्रियान्वयन में अहम भूमिका निभाएंगे। इससे देश श्रमिकों के कल्याण के साथ उत्पादन वृद्धि, निर्यात वृद्धि, रोजगार वृद्धि और विकास दर वृद्धि की राह पर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे सकेगा।

(लेखक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

लेख पर अपनी प्रतिक्रिया haribhoomi@gmail.com पर दे सकते हैं।

सारा संसार

सबरीमाला मंदिर दक्षिण भारत के प्रसिद्ध और चमत्कारिक हिंदू मंदिरों में से एक है जहाँ प्रतिवर्ष करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। भगवान अयप्पा को समर्पित इस मंदिर की एक खास बात यह है की इस मंदिर में जाने से पहले पंपा नदी में स्नान करना पड़ता है और फिर एक दीपक जलाकर नदी में प्रवाहित करने के बाद ही मंदिर में प्रवेश दिया जाता है।

जीवन बना और बिगाड़ सकती है ये चीजें

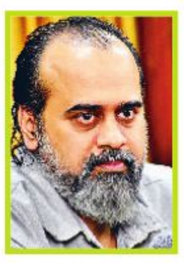

संकलित

दर्शन

आम आदमी अपने दिन का पूरा समय इन दो जगहों पर बिताता है वो है घर या फिर दफ्तर में। जैसी व्यक्ति की संगति होती है वैसी ही उसकी मति हो जाती है। इसलिए जरूरी होता है कि व्यक्ति हमेशा अपने लिए सही वातावरण चुनना चाहिए, जिससे वह सही पथ पर चले। आचार्य प्रशांत के अनुसार, एक व्यक्ति किस आधार पर विवाह करता है या फिर कैसी संगति चुनता है। यह महत्व की बात है कि वह व्यक्ति किसके साथ रह रहा है। आप चाहे विवाह करके रह रहे हो या फिर बिना विवाह करके अपना जीवन व्यय कर रहा हो। ऐसे में व्यक्ति को जरूर हमेशा याद रखना चाहिए कि वह अपने जीवनसाथी का चयन किस आधार पर कर रहा है। हर एक छोटी बात जैसे कि वह व्यक्ति अब से लगातार मेरे कमरे में रहेगा? किसके शब्द लगातार पड़ने लग गए हैं तुम्हारे कानों में? इन चीजों को याद करके ही निर्णय लेना चाहिए। क्योंकि इसी बात पर तुम्हारी जिंदगी या तो बन जाएगी या बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी। आचार्य प्रशांत आगे कहते हैं कि यहीं बात दफ्तर के लिए है कि दिन के आठ से दस घंटे आप किन लोगों की शक्लें देखते हैं या आर अपना बॉस बोलते हो, वो यूं ही है कोई सड़क का आदमी जो तुम्हारी जिंदगी पर अब अधिकार रखने लग गया है तो तुम बर्बाद हो जाओगे। यही बात दफ्तर के माहौल पर और धंधे की प्रकृति पर लागू होती है। तुम्हारी संस्था किस तरह का व्यवसाय करती है और तुम्हारे काम में किस तरह के लोग लगे हुए हैं?

मंत्र का असर

संकलित

प्रेरणा

एक निर्धन औरत एक साधु के पास गई, 'स्वामी जी! कोई ऐसा पवित्र मन्त्र लिख दीजिये जिससे मेरे बच्चों का रात को भूख से रोना बन्द हो जाये...।' साधु ने कुछ पल एकटक आकाश की ओर देखा फिर अपनी कुटिया में अन्दर गया और एक पीले कपड़े पर एक मन्त्र लिखकर उसे ताबीज की तरह लपेट-बाँधकर उस महिला को दे दिया। साधु ने कहा, 'इस मन्त्र को घर में उस जगह रखना, जहाँ अपनी मेहनत की कमाई का धन रखती हो।' महिला खुश होकर चली गई। ईश्वर कृपा से उस दिन उसके पति की आमदनी ठीक हुई और बच्चों को भोजन मिल गया। रात शान्ति से कट गई। अगले दिन भोर में ही उन्हें पैसों से भरी एक थैली घर के आंगन में मिली। थैली में धन के अलावा एक पर्चा भी निकला, जिस पर लिखा था, कोई कारोबार कर लें...। इस बात पर अमल करते हुवे उस औरत के पति ने एक छोटी सी दुकान किराए पर ले ली और काम शुरू किया। धीरे धीरे कारोबार बढ़ा, तो दुकानें भी बढ़ती गईं...। जैसे पैसों की बारिश सी होने लगी...। पति की कमाई तिजोरी में रखते समय एक दिन उस महिला की नज़र उस मन्त्र लिखे कपड़े पर पड़ी...। 'न जाने, साधु महाराज ने ऐसा कौन सा मन्त्र लिखा था कि हमारी सारी तंगी दूर हो गई?' सोचते सोचते उसने वह मन्त्र वाला कपड़ा खोल डाला...। जिस लिखा था कि.. जब पैसों की तंगी समाप्त हो जाये, तो सारा पैसा तिजोरी में छिपाने की बजाय कुछ पैसे ऐसे घर में डाल देना जहाँ से रात को बच्चों के रोने की आवाज़ें आती हों..!!

विचार

प्रभात मिश्र

सावरकर स्वप्न

प्रखर विचारक, दार्शनिक, पत्रकार, कवि, भविष्यवक्ता, नाट्यकार, भाषा सुधारक, समाज सुधारक, राष्ट्र प्रेमी, क्रांतिकारी और मां भारती के अनन्य उपासक स्वातंत्र्य वीर विनायक दामोदर सावरकर के व्यक्तित्व एवं कृतित्व को सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता है विराट और विशाल है आपकी चिंतन धारा जिसमें त्वरा है तो असीम गहराई भी धीर गंभीर हैं तो इतना कि 1926 - 30 के आसपास जब देवनागरी लिपि में व व्याकरण में सुधार एवं अनुसंधान की आवश्यकता समझी गई तो सावरकर सहर्ष अपना योगदान देते दृष्टि गोचर होते हैं और स्वरों के अ की बारहखड़ी तैयार की जिसे भाषागत सुधार के क्षेत्र में मील का पत्थर माना गया एवं इसे महात्मा गांधी ने भी समझा व स्वीकार कर इसे दैनिक लेखन में प्रयोग कर ग्राहता को आगे बढ़ाया ये वो दुर्लभ पहलू हैं सावरकर के जिसके लिए हिन्दी व अन्य सह भाषाई जगत सदैव ऋणी रहेगा वहीं नूतन शब्दों के अनुसंधान कर्ता की भूमिका में आप शब्दों के आविष्कारक के रूप में दिखाई देते हैं।

ये सावरकर के लेखनी का सौंदर्य ही है कि आज में कल देख लेना वर्तमान में भविष्य को देखना और उसके अनुरूप समाधान प्रस्तुत कर देना कुछ पंक्तियों से उनका स्मरण आवश्यक प्रतीत होता है - 'कांटों से छिद जाए चरण यदि चलूं उन्हीं कांटों पर पुनि पुनि - कट कट अंग गीरे धरणी पर चलने का वर दे दो' सावरकर जन्म जात कवि थे उनके साहित्यिक अवदानों का मूल्यांकन अभी भी शेष है उनकी लेखनी जो लोहे के कील से बनी थी सतत् चलती रही रुकी नहीं अविराम दीवारों पर लिख दिया वो अमर राग जिन्हें हम कमला, गोमांतक, महासागर, के नाम से जानते हैं अंडमान द्वीप स्थित सेलुलर जेल इसका साक्षी है जहां की दिवारें कुछ कहना चाहती हैं कि कैसे थे अंग्रेज और उनकी निष्ठुर सत्ता जो सावरकर को यातना दे रही थी पर उनका मनोबल नहीं तोड़ पाई इसी मनोबल का परिणाम हुआ कि अप्रतिम रचनाएं उद्घाटित हुईं जिससे राष्ट्रीय स्वाभिमान का सांस्कृतिक पुनर्जागरण का वातावरण बना।

सावरकर स्वप्न क्या है ? तो वो कहते हैं जिसकी जनता सारी मानव जाति हो ऐसा विश्व राष्ट्र हमारा ध्येय है और उस पर हमारा पूरा विश्वास है (1920 अंडमान) ये मंतव्य सावरकर के उन आलोचकों को सीधे ललकारता है जो सावरकर के प्रति संकुचित सोच रखते हुए अनर्गल प्रलाप करते रहते हैं भारत माता के इस वीर सपूत में जहां एक ओर क्रांति की ज्वाला है तो वहीं दूसरी ओर स्नेह का सागर भी समाया हुआ है इस साम्य में वीर सावरकर और श्री अरविन्द एक दूसरे के पूरक हैं। सावरकर स्वप्न के विविध रंग हैं जिसमें भाषाई शुद्धता का आग्रह गहरा है हम सभी जैसा कि जानते ही हैं कि शुद्ध भाषा के लिए शुद्ध दर्शन और शुद्ध श्रवण होगा तो ही शुद्ध उच्चारण और शुद्ध लेखन स्वयं आने लगेगा और इसी विषय का आग्रह सदैव सावरकर करते रहे जो हमारी समृद्ध भाषाई गौरव का परिचायक है यही है सावरकर स्वप्न कि अनावश्यक विदेशी शब्दों का हस्तक्षेप कम से कम हो। सावरकर स्वप्न मातृभाषा के प्रति वही संकल्प देखना चाहता है जो आयरलैंड के पुनर्जागरण में गेलिक भाषा का, बिस्मार्क के जर्मनी में जर्मन भाषा का, इसराइल में हिब्रू भाषा का, रूस में रुसी भाषा का।

-अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राज भाषा आयोग

अंतर्मन

आज की पाती

संस्कारों के अभाव में बच्चे बन जाते हैं हिंसक

कोई भी मां-बाप नहीं चाहते हैं कि उनके बच्चे जिंदगी में कभी भी पथभ्रष्ट हों, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के बच्चे पथभ्रष्ट हो जाते हैं। इसके मुख्य कारण बच्चों की परवरिश में कमी और इन्हें अच्छे संस्कार न मिलना भी है। अपने बच्चे सभी को प्यारे होते हैं, लेकिन बच्चों की गलतियों को अनदेखा करना बहुत गलत होता है। कुछ दिन पहले एक खबर पढ़ने को मिली कि दिल्ली में एक शादी समारोह में कम उम्र के लड़कों के बीच विवाद डीजे पर गाने को लेकर इस कदर हो गया कि इनमें एक लड़के की हत्या ही कर दी गई। ऐसी ही खबरें अक्सर पढ़ने और सुनने को मिलती हैं। सवाल तो यह है कि बच्चे, किशोर, नाबालिग आखिर क्यों पथभ्रष्ट होकर अनैतिक और अपराधी मामलों को अंजाम दे रहे हैं? *- प्रतीक सक्सेना, धमतरी*

ट्रेंड

प्रौद्योगिकी का समावेश

मोदी सरकार गरीबी उन्मूलन योजनाओं को अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के लिए उनमें प्रौद्योगिकी का समावेश कर रही है। इसी दिशा में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्थक-पीडीएस चरण-2 के लिए 25,530 करोड़ की राशि स्वीकृत की है।

- अमित शाह, केंद्रीय गृहमंत्री

सीबीएसई परीक्षा परिणाम

सीबीएसई परीक्षा परिणामों में बड़े पैमाने पर हेराफेरी हुई है, जिससे देशभर के लाखों बच्चे और उनके माता-पिता सदमे में हैं। मोदी जी हमेशा की तरह- कोई जवाब नहीं, कोई जवाबदेही नहीं, कोई शर्म नहीं।

-राहुल गांधी, सांसद, कांग्रेस

भाजपा-कांग्रेस संबंध

केंद्रीय एजेंसियों का भाजपा द्वारा क्षेत्रीय विपक्षी दलों को निशाना बनाने और लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए किया गया एक और घोर दुरुपयोग है। कांग्रेस द्वारा 'निष्क्रियता' की शिकायत शुरू होते ही ईडी की तत्काल छापेमारी से भाजपा-कांग्रेस संबंधों पर सवाल उठते हैं।

-अरविंद केजरीवाल, पूर्व सीएम, नई दिल्ली

जनता से लूटपाट

तेल की कीमतें बढ़ाकर भाजपा हाल के चुनावों में खर्च किए गए पैसे की भरपाई कर रही है। उसका बस एक ही सिद्धांत है कि उसका और उनके लोगों का खजाना कभी खाली न हो, भले ही इसके लिए जनता की जेबों से लूटपाट क्यों न करनी पड़े।

-अखिलेश यादव, सांसद, सपा

करंट अफेयर

संरा सुरक्षा परिषद को 'जीवंत संस्था' बनाने की जरूरत

भारत ने चीन की अध्यक्षता में हुई संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में वीटो का अधिकार रखने वाले स्थायी सदस्यों के बीच मतभेदों को उजागर किया।

भारत ने इस बात पर जोर दिया कि परिषद एक जीवंत संस्था होनी चाहिए, न कि कोई जीवाश्म जिसकी स्थिर संरचना 1945 के कंप्यूटर संस्करण पर उन्नत कृत्रिम बद्धिमत्ता (एआई) संबंधी प्रौद्योगिकियों को चलाने के समान हो। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि, राजदूत हरीश पर्वतनेनी ने कहा, संयुक्त राष्ट्र परिषद की सक्रियता का दौर अब समाप्त हो चुका है, और दुनिया अब विभाजन और टकराव से ग्रस्त है। वीटो अधिकार वाले स्थायी सदस्यों के स्तर पर परिषद विभाजित नजर आ रही है। संयुक्त राष्ट्र में कार्यकुशलता और उत्पादकता बढ़ाने की मांग पहले से कहीं अधिक प्रबल है पर्वतनेनी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की संयुक्त राष्ट्र चार्टर के उद्देश्यों और सिद्धांतों को बनाए रखना और संयुक्त राष्ट्र-केंद्रित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को मजबूत करना विषय पर हो रही चर्चा को संबोधित कर रहे थे। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने मंगलवार सुबह उक्त विषय पर चर्चा के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता की। अमेरिका, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, और चीन 'संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद' के वीटो का अधिकार रखने वाले पांच स्थायी सदस्य हैं।

ऑफ बीट

कार्डियो वजन उठाने से पहले करना चाहिए या बाद में?

फिटनेस के प्रति जुनूनी लोग दशकों से इस प्रश्न पर बहस करते रहे हैं कि 'कार्डियो' करना वजन उठाने से पहले बेहतर होता है या बाद में? हाल तक,

इसका उत्तर काफी हद तक पसंद पर निर्भर करता था - कुछ लोग वजन उठाने से पहले जॉगिंग करते थे, जबकि अन्य लोगों का मानना था कि पहले वजन उठाना वसा को खत्म करने के लिए बेहतर है। लेकिन एक नए शोध ने अंततः इस लंबे समय से विवादित प्रश्न का उत्तर दे दिया है। शोध के अनुसार, आपके व्यायाम का क्रम इस बात को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है कि आप कितनी चर्बी कम करते हैं। जिन प्रतिभागियों ने वजन उठाने के बाद कार्डियो किया, उनमें कार्डियो करने के बाद वजन उठाने वालों की तुलना में काफी अधिक चर्बी कम हुई और वे पूरे दिन शारीरिक रूप से अधिक सक्रिय रहे। शोधकर्ताओं ने प्रतिभागियों को 12 सप्ताह के लिए तीन समूहों में विभाजित किया। दोनों व्यायाम समूहों ने एक जैसे प्रशिक्षण कार्यक्रम अपनाए, केवल व्यायाम क्रम में अंतर था। प्रतिभागियों ने बेंच प्रेस, डेडलिफ्ट, बाइसेप कर्ल और स्क्वाट जैसे व्यायाम किए। कार्डियो सत्र में 30 मिनट तक 'साइकिलिंग' शामिल थी। दोनों समूहों के प्रतिभागियों ने अपनी हृदय संबंधी फिटनेस, मांसपेशियों की ताकत और शारीरिक बनावट में सुधार का अनुभव किया।

अपने विचार

हरिभूमि कार्यालय

टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-4242222, 23 पर या सीधे मेल से **hbcgpati@gmail.com** पर भेज सकते हैं।

दैनिक जागरण

अपेक्षित परिणाम नहीं मिला तो समझिए प्रयास में कमी रही

एसआइआर पर मुहर

अंततः सुप्रीम कोर्ट ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआइआर की चुनाव आयोग की प्रक्रिया को न केवल वैध करार दिया, बल्कि यह भी स्पष्ट किया कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों के लिए ऐसा किया जाना आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश उन विपक्षी नेताओं के लिए एक बड़ा झटका है, जो यह दुष्प्रचार करने में लगे हुए थे कि चुनाव आयोग भाजपा के इशारे पर एसआइआर के नाम पर मनमानी करने में लगा हुआ है। इस आदेश ने यह स्पष्ट किया कि झूठ के पैर नहीं होते और दुष्प्रचार के जरिये किसी वैध प्रक्रिया को रोका नहीं जा सकता। इस पर हैरानी नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से असहमत लोग निराशा व्यक्त कर रहे हैं। यह उनकी कुंठा के अतिरिक्त और कुछ नहीं, क्योंकि निष्पक्ष चुनावों की पहली शर्त ही यह है कि वैध मतदाता ही वोट डालें। कोई व्यक्ति वैध मतदाता है या नहीं, इसके निर्धारण के लिए आवश्यक छानबीन करना चुनाव आयोग का अधिकार है। यह विचित्र है कि कुछ विपक्षी दल चुनाव आयोग के इसी अधिकार को चुनौती देने के लिए ऐसे मनगढ़ंत आरोप लगा रहे थे कि आयोग एसआइआर के बहाने उनके समर्थकों के वोट काटने का काम कर रहा है। ऐसे आरोप लगाने वालों ने यह स्पष्ट करने की जहमत कभी नहीं उठाई कि आखिर उन्हें कैसे पता चला कि जिन लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए जा रहे हैं, वे उनके वोटर हैं?

बिहार में एसआइआर के दौरान जब करीब 65 लाख ऐसे नाम मतदाता सूची से हटाए गए, जो अन्यत्र बस गए थे या फिर जिनकी मृत्यु हो गई थी अथवा जिनके नाम दो जगह दर्ज थे तो यह शोर मचाया गया कि वैध मतदाताओं को मताधिकार से वंचित किया जा रहा है, पर यह शोर मचाने वाले ऐसे 65 लोगों को भी नहीं जुटा सके। बिहार विधानसभा चुनावों में एसआइआर के कोई मुद्दा न बन पाने के बाद विपक्षी दलों और खासकर वोट चोरी का जुमला उछाल रही कांग्रेस को यह समझ आ जाना चाहिए था कि वह हारी हुई लड़ाई लड़ रही है, लेकिन न उसने दीवार पर लिखी इबारत पढ़ी और न ही अन्य विपक्षी दलों ने। विपक्षी दलों को इस पर खासी आपत्ति थी कि एसआइआर के तहत लोगों की नागरिकता की परख की जा रही है, जबकि चुनाव आयोग को ऐसा करने का अधिकार ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि चुनाव आयोग किसी का नाम मतदाता सूची में शामिल करने के क्रम में उसकी नागरिकता की जांच कर सकता है। आखिर इससे ही तो तय होगा कि वह भारत का वैध नागरिक है या नहीं? चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग की नागरिकता संबंधी जांच अंतिम फैसला नहीं मानी जाएगी, इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि केंद्र सरकार लोगों की नागरिकता जांचने के लिए राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी एनआरसी तैयार करने की दिशा में आगे बढ़े।

अनदेखी पड़ेगी भारी

झारखंड में जलसंकट की तस्वीर फिर भयावह होने लगी है। कुएं सूख रहे हैं, हैंडपंप जवाब दे रहे हैं और छोटे जलाशयों का अस्तित्व मिटता जा रहा है। कई क्षेत्रों में लोगों को पानी के लिए घंटों कतार में खड़ा होना पड़ रहा है तो कहीं मीलों दूर से पानी लाना मजबूरी बन गया है। यह स्थिति अचानक नहीं बनी, बल्कि वर्षों से भूगर्भ जल के अनियंत्रित दोहन और जल संरक्षण की अनदेखी का परिणाम है। विडंबना यह है कि जल संरक्षण को लेकर योजनाएं और दावे तो खूब किए जाते हैं, लेकिन अधिकांश प्रयास कागजों तक सीमित रह जाते हैं। अनियंत्रित डीप बोरिंग ने जलस्तर को तेजी से नीचे धकेला है। जहां कभी 50 से 100 फीट पर पानी मिल जाता था, अब 500 से 1000 फीट तक खोदाई करनी पड़ रही है। यह केवल पर्यावरणीय नहीं, बल्कि सामाजिक संकट भी बनता जा रहा है। जरूरत इस बात की है कि भूगर्भ जल दोहन पर सख्त निगरानी हो और वर्षा जल संचयन को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। प्रशासन के साथ आम लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। यदि अभी नहीं चेते तो आने वाले वर्षों में जलसंकट और विकराल रूप ले सकता है। प्रकृति चेतावनी दे रही है, लेकिन अनदेखी की यह प्रवृत्ति भविष्य को और कठिन बना सकती है।

भूगर्भ जल का अंधाधुंध दोहन और जल संरक्षण के प्रति लापरवाही आने वाले समय में गंभीर संकट को जन्म दे सकती है

खुद को पहचानने की कोशिश में पाकिस्तान

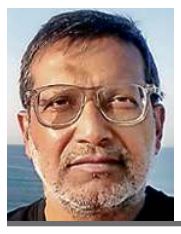

शंकर शरण

हर कहीं विचारशील मुस्लिम समझ चुके हैं कि 14 सौ साल पहले के पिछड़े, संकीर्ण अरब क्षेत्र में दिए गए कायदे, वर्जनाएं और लक्ष्य दरअसल जीवन और प्रकृति से दूर हैं

अवधेश राजपूत

लाहौर में असंख्य स्थानों के बदले गए कई नामों को फिर अपने मूल नामों में बदलने का फैसला कई अर्थों में एक बड़ी घटना है। इसमें ब्रिटिश नाम ही नहीं, हिंदू देवी-देवताओं से जुड़े नाम भी हैं। इनमें कृष्ण नगर, राम गली, धर्मपुरा, लक्ष्मी चौक, संतनगर आदि हैं, जिन्हें विभाजन के बाद इस्लामपुरा, रहमान गली, मुस्तफाबाद आदि कर दिया गया था। कट्टरपंथियों के दबाव में पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज की अध्यक्षता में कैबिनेट के ओर से लिए गए फैसले को रोक लिया गया है। देखना है आगे क्या होता है? वैसे मूल नाम बहाल करने का कारण यह बताया गया था कि लाहौर की सांस्कृतिक पहचान और ऐतिहासिक विरासत को पुनर्जीवित करना है। इससे पाकिस्तान के अस्तित्व की बुनियाद ही बदलती दिखती है। क्लासिक इस्लामी नजरिये से 'इस्लामपुरा' को 'कृष्ण नगर' कहना घोर कुफ्र यानी सबसे घृणित काम है। यह पाकिस्तान का ही नाम बदल कर 'पश्चिमी भारत' कर देने जैसा है। यदि पाकिस्तान अपने क्षेत्र की मूल सांस्कृतिक पहचान और ऐतिहासिक विरासत को महत्व दे रहा है, तो यह बात बहुत दूर तक जा सकती है। इसमें न केवल भारत-विभाजन को व्यर्थ, अनुपयुक्त और अलाभकारी मानने का संकेत है, अपितु स्वयं इस्लामी मान्यताओं को अनुपयुक्त मानना है।

मोरक्को, मिस्र, सऊदी अरब से लेकर ईरान तक में संस्कृति एवं इतिहास को लेकर यह उलझन स्थायी रही है। सबमें समान तत्व जीवन की वास्तविकता और इस्लामी निर्देशों के बीच विरोध ही है। पाकिस्तान में विभाजन के फौरन बाद ही विचारशील लोग असहज होने लगे थे। वहां संविधान बनने में नौ वर्ष लगे, जिसमें पाकिस्तान को 'इस्लामी रिपब्लिक' कहा गया। पर फिर छह वर्ष में ही संविधान बदल दिया गया। 1962 में बने दूसरे संविधान में देश के नाम से 'इस्लामी' हटा कर केवल 'रिपब्लिक आफ पाकिस्तान' कर दिया गया। फिर इस्लामी शब्द जोड़ा गया। 11 वर्ष बाद तीसरा संविधान आया, जिसमें इस्लाम को 'राजकीय मजहब' घोषित किया गया। जिया उल हक और फिर परवेज मुशर्रफ ने संविधान का और इस्लामीकरण किया। मुशर्रफ ने तो 'जिहाद' को पाकिस्तान की विदेश नीति भी बताया। इसके बाद अब फिर मूल सांस्कृतिक पहचान और ऐतिहासिक विरासत की ओर लौटने की कोशिश इसकी स्वीकृति है कि अधिक से अधिक इस्लामीकरण मनुष्य की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक प्यास को उपेक्षित करता है। पाकिस्तान की इस विडंबना का एक आकलन नोबेल पुरस्कृत लेखक वीएस नायपाल ने वहां रहकर किया था। अपनी पुस्तकों 'अमंग द बिलीवर्स' और 'बियांड बिलीफ' में उन्होंने पाकिस्तानी मानस की दुविधा को दिखाया। उन्होंने ईरान, इंडोनेशिया, मलेशिया को लेकर भी यह आकलन किया था कि हर कहीं इस्लामी प्रतिबद्धता, मानवीय स्वतंत्रता के बीच स्थायी तनाव है। इस्लामी बंधन को बलपूर्वक बनाए रखना होता है, वरना उसका टिकना असंभव है।

प्रख्यात लेखक नीरद सी. चौधरी ने भी लिखा था कि पाकिस्तान एक विनष्ट उद्देश्य के लिए लड़ते रहने को विवश है, अन्यथा वह खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब किसी मुस्लिम देश में सब कुछ शरीयत से नहीं चलता, जबकि यही इस्लाम की मूल टेक है। उनके अवलोकन के बाद 64 वर्षों में मुस्लिम जगत ने और विशाल अनुभव पा लिया है। पेट्रो-डालर, ईरान में खुमैनी क्रांति, तालिबान, अलकायदा, इस्लामिक स्टेट आदि का दशकों चला जिहाद और अब ईरान की दुर्दशा, सभी अनुभव संकेत करते हैं कि राजनीतिक इस्लाम का कोई भविष्य नहीं है। इसीलिए सऊदी में भी इस्लाम से पहले के स्थानों, प्रतीकों को ऐतिहासिक सांस्कृतिक विरासत के रूप में स्थापित किया गया है। वहां सिनेमा, संगीत, लड़कियों के लिए फुटबाल की अनुमति, शिक्षा में योगाभ्यास आदि को स्थान दिया जा चुका है। यह सब अनायास भी हो रहा है और सुविचारित भी। संख्यात्मक रूप से मुस्लिम बढ़ रहे हैं, पर अंदर इस्लाम से मोहभंग भी बढ़ रहा है। चाहे अभी संख्या में कम हों, पर हर कहीं विचारशील मुस्लिम समझ चुके हैं कि 14 सौ साल पहले के पिछड़े, संकीर्ण अरब क्षेत्र में दिए गए कायदे, वर्जनाएं और लक्ष्य दरअसल जीवन और प्रकृति से दूर हैं।

ऐतिहासिक रूप से भारतीय मनीषा से जुड़े होने के कारण अनेक पाकिस्तानी कभी नहीं तय कर पाए कि एक राष्ट्र के रूप में वे कौन है? कहां से जुड़े हैं? खुद पाकिस्तान में जिन्ना और इकबाल की इसे लेकर अलग-अलग समझ थी कि इस्लाम को जीवन में कैसे उतारा जाए? वहां हर फिरका दूसरे को 'काफिर' कहता है। केवल भारत-विरोध पाकिस्तानी लोगों को जोड़ने की चीज रही है, पर वह एक नकारात्मक भावना है। इससे पाकिस्तानी समाज की उन्नति असंभव है।

यह भविष्य ही बताएगा कि क्या पाकिस्तानी नेतृत्व सच स्वीकार करने की ओर बढ़ रहा है, किंतु यदि ऐसा हुआ तो भारत विभाजन का औचित्य कभी भी एक झटके में खत्म हो सकता है, जैसे कम्युनिज्म की सच्चाई स्वीकार करते ही पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी का भेद खत्म हो गया था। पाकिस्तान में जो हो रहा है, उसकी परिणति जर्मनी वाली होना संभव है, क्योंकि यदि पाकिस्तानी उच्च वर्ग इस्लाम से मुंह मोड़ ले तो, आम जन मूल भारतीय समाज के प्रति स्वतः खिंचा आएगा, जिसकी सभ्यता और संस्कृति का वह सहज अंग रही है। पंजाब, सिंध, और बलूचिस्तान में मुस्लिम लीग को 1946 तक कोई समर्थन नहीं था। उसकी मांग मुख्यतः अलीगढ़, कलकत्ता और बंबई के मुस्लिम नेताओं ने की थी। पंजाब और सिंध के मुसलमानों को तो विभाजन एक आकस्मिक नियामत के रूप में मिला। फिर उन्हें अपनी ही गौरवशाली संस्कृति, इतिहास, साहित्य और समाज से घृणा करना सिखाया गया। आखिर भारत-विरोधी नीतियों से पाकिस्तानी पंजाब के लोगों को अब तक क्या हासिल हुआ? अभी यह कहना कठिन है कि इस्लाम को अपना आधार बनाना असल में गले का तौक हो गया है, पर यह तय है कि इस्लाम की अपनी मूल पहचान हटाते ही पाकिस्तान का अस्वाभाविक विलगाव जाता रहेगा। फिर क्या होगा, यह अल्लाह जानता है।

(लेखक राजनीतिशास्त्र के प्रोफेसर एवं वरिष्ठ स्तंभकार हैं)

response@jagran.com

शिखर पर महिलाओं के होने का मतलब

क्षमा शर्मा

आखिर शिखर पर पहुंचते ही कई नेत्रियों को वही रास्ता क्यों सुविधाजनक लगता है, जिसे चुनौती देकर वे सत्ता में आती हैं?

चौतरफा आरोपों से घिरीं ममता बनर्जी। फाइल

बंगाल में पराजय के बाद ममता बनर्जी मुश्किल में हैं। उनके सहयोगी ही उनके खिलाफ खड़े हो रहे हैं। ममता यह दिखा रही हैं कि किस तरह हर वक्त संविधान बचाने और लोकतंत्र की दुहाई देने वाले नेता चुनाव परिणाम अपने अनुकूल न आने के बाद किसी भी तरह के झूठ से परहेज नहीं करते। पता नहीं क्यों नेता यह मानकर बैठ जाते हैं कि कोई राज्य उनकी निजी जागीर है और वे हमेशा ही वहां बने रहेंगे? ममता की हार पर दो तरह के विमर्श चालू हैं। एक पक्ष कह रहा है कि उनकी हार उनकी पार्टी की गुंडागर्दी, तानाशाहीपूर्ण नीतियों, अवैध वसूली, भ्रष्टाचार तथा हिंदुओं की नाराजगी के कारण हुई। दूसरा पक्ष उनकी हार पर कह रहा है-देश से लोकतंत्र खत्म हो गया, फासिज्म आ गया आदि। फासिज्म का राग अलापने वाले यह नहीं बताते कि आपातकाल के दिनों में या हिटलर, मुसोलिनी, माओ, स्टालिन, शी चिनफिंग, किम इल सुंग से किम इल जोंग आदि के शासनकाल में क्या वे इतना बोल सकते थे? डिजिटल मीडिया पर जो चाहे, लिख सकते थे। आपातकाल को इस लेखिका ने देखा है। जहां किसी को भी बिना किसी जांच के उठा लिया जाता था। फिर उसका पता न चलता था। आपातकाल को भी एक महिला नेता इंदिरा गांधी ने ही लगाया था। तब लोकतंत्र के बहुत से हिमायतियों को सांप सूंघ गया था। दूरदर्शन, रेडियो, अखबारों में बाकायदा सरकार के लोग बैठे रहते, जो हर खबर को देखते। तभी वह छप सकती थी या प्रसारित हो सकती थी।

मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रहीं, उन्होंने राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति को वाकई बहुत सुधारा, लेकिन उन पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे। हालांकि वे साबित नहीं हुए। कुछ साल पहले ममता बनर्जी की तरह ही उन्होंने भी अपने भतीजे को अपना उत्तराधिकारी बना दिया। तमिलनाडु में जब जयललिता आईं तो उनकी परम मित्र शशिकला का बोलबाला हो गया था। जयललिता पर भी भ्रष्टाचार के खूब आरोप लगे। वह पहली मुख्यमंत्री थीं, जिन्हें इस पद पर रहते हुए जेल जाना पड़ा। शीला दीक्षित जब दिल्ली की मुख्यमंत्री थीं, तो निश्चित रूप से उन्होंने दिल्ली के इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास में बहुत योगदान दिया, लेकिन उन्हें भी भ्रष्टाचार के आरोपों से दो-चार होना पड़ा। उन्होंने भी अपने बेटे को आगे बढ़ाने की कोशिश की। पत्नी राबड़ी देवी को लालू प्रसाद यादव ने बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया था। उन पर भी जमीन के बदले नौकरी और आइआरसीटीसी घोटाले में लिप्त होने के आरोप लगे हैं। सुनवाई हो रही है। उनके उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव और मीसा भारती बन गए हैं।

आखिर ऐसा क्यों है कि शिखर पर पहुंचते ही कई नेत्रियों को वही रास्ता सुविधाजनक लगता है, जिसे चुनौती देकर वे सत्ता में आती हैं। अपने रिश्तेदारों के अलावा, उत्तराधिकारी के लिए इन्हें कोई और योग्य क्यों नहीं लगता? उन विचारों का कितना महत्व है, जो कहते हैं कि स्त्रियां ही दुनिया को नष्ट होने से बचा सकती हैं। वे भी इसी पितृसत्तात्मक समाज का हिस्सा हैं, इसलिए जाने-अनजाने वे भी वही तौर-तरीके अपनाती हैं। तब फिर शिखर पर रहकर वे क्या बदलती हैं? कहावत है-एब्सोल्यूट पावर करप्टस एब्सोल्यूटली या हिंदी की कहावत है-काजर की कोठरी में कैसो ही सयानो जाय..। ये सच मालूम देती हैं। अक्सर कहा जाता है कि स्त्रियां यदि सत्ता के शिखर पर पहुंच जाएं, तो लोगों की तकदीर बदल सकती है, क्योंकि वे भ्रष्ट नहीं होतीं। वे पानी, सफाई, पोषण, स्कूल, सड़कों आदि को सुधारने की पहल करती हैं। बहुत सी ग्राम प्रधान स्त्रियों के बारे में छपता भी रहता है कि उन्होंने किस तरह अपने प्रयासों से गांवों की सूरत बदल दी। प्रायः हमारी तुलना दूसरे देशों से की जाती है कि वहां देखो, कितना अच्छा है, लेकिन अमेरिका में अपराधी न स्त्री होती है, न पुरुष, वह सिर्फ अपराधी होता है। वहां ऐसा कोई नियम नहीं कि स्त्री अपराधी को पुरुष पुलिस वाले नहीं पकड़ सकते। न ही भारत की तरह यह नियम है कि सूर्यास्त के बाद किसी स्त्री अपराधी को आमतौर पर नहीं पकड़ा जा सकता। वहां अपराध के मामले में न स्त्री होना काम आता है, न रंग, भाषा, प्रदेश, प्रांत का सवाल उठता है।

जब से बंगाल के चुनाव हुए हैं, न जाने कितने भयावह वीडियो और रील्स देखी हैं। वहां की स्त्रियां बताती हैं कि मामूली बातों पर उनके पति, बेटों को घर से खींचकर उनके सामने ही मार दिया गया। लड़कियों का दुष्कर्म, अपहरण, घरों, जमीन पर कब्जा, मवेशियों को खोल ले जाना आम बात थी। पुलिस ने भी उनकी कोई मदद नहीं की। कुछ स्त्रियों ने कहा कि चुनाव के दौरान उनके घर सफेद साड़ियां भिजवाई जातीं यानी कि यदि तुमने हमें वोट नहीं दिया, तो इन्हें पहनना। क्या यह देखकर हैरत नहीं होती कि आज भी बंगाल में विधवा होना कितना दुखद है। वृंदावन की विधवाओं में अधिकांश बंगाल से ही आती हैं। उनके घर वाले ही उन्हें वहां छोड़ जाते हैं। यह राजा राममोहन राय जैसे समाज सुधारक की वही धरती है, जहां उन्होंने सती प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ, विधवा विवाह तथा स्त्री शिक्षा के समर्थन में आंदोलन चलाया था।

(लेखिका साहित्यकार हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

पुरुषार्थ का प्रतिफल

अस्तित्व तो हम सभी का है, किंतु विराट व्यक्तित्व विरले ही बना पाते हैं। अस्तित्व सहज मिलता है, जबकि व्यक्तित्व निर्मित करना पड़ता है। व्यक्तित्व के निर्माण में सबसे मुख्य कारक है पुरुषार्थ। सफलता एकाएक नहीं मिलती। हर सफलता कुछ कीमत मांगती है और कीमत होती है-सही समय पर सही काम करना। अपनी पूरी लगन उसमें झोंक देना। एडिसन ने कहा बिजली का बल्ब बनाने में हर असफलता से मुझे अनुभव हुआ कि अब तक के अपनाए गए सभी तरीकों से बिजली के बल्ब नहीं बनाए जा सकते हैं।

निरंतर बहती हुई नदी अपनी ताकत से नही, बल्कि अपने द्वारा किए गए निरंतर प्रयास से पहाड़ तक को काट देती है। जीवन-वृक्ष भी सिर्फ श्रम करने वालों का ही पुष्पित-पल्लवित होता है। इच्छा मात्र से ही सफलता मिल जाती तो यह दुनिया इतनी रंग-बिरंगी नहीं होती। विचारों के तानेबाने से योजना का वस्त्र बुनने वाले आलसी मनुष्य के सौ वर्ष के जीवन की तुलना में दृढ़तापूर्वक परिश्रम करने वाले का एक दिन का जीवन भी श्रेष्ठ है।

हमारी सबसे अच्छी मित्र हमारे हाथों की दस अंगुलियां और उनके द्वारा किया पुरुषार्थ है। तभी प्रकृति ने हथेली पर खिंची भाग्य की रेखाओं से अंगुलियों को आगे रखा है। पुरुषार्थ का अर्थ केवल भौतिक इच्छाओं की पूर्ति नहीं है, बल्कि यह वह मानवीय कर्म और संकल्प है, जो जीवन को सार्थक बनाता है। शिखर पर चढ़ते समय अगर हम यही सोचते रहें कि चोटी कितनी दूर है, कब पहुंचेंगे, न जाने कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, तो हमारे ध्यान में रची-बसी यही बातें हमें भयभीत और हतोत्साहित करती रहेंगी। जबकि हम सिर्फ अपने अगले कदम पर ध्यान रखें, उस एक-एक कदम के बारे में सोचें, जो हम आगे बढ़ाएंगे, तब हम सही समय पर उचित शिखर पर होंगे।

डा. निर्मल जैन

मानसिक स्वास्थ्य का गहराता वैश्विक संकट

प्रदीप

मानसिक स्वास्थ्य सामाजिक, आर्थिक और सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ा वैश्विक संकट बन चुका है

दुनिया भर में मानसिक विकारों का बोझ जिस रफ्तार से बढ़ रहा है, उसकी गंभीरता अब नए वैज्ञानिक अध्ययनों में साफ नजर आने लगी हैं। जर्नल 'द लैंसेट' में प्रकाशित एक हालिया अध्ययन के मुताबिक चिंता (एंग्जायटी), अवसाद (डिप्रेशन) और अन्य मानसिक विकारों के मामले पिछले तीन दशकों में इतने तेजी से बढ़े हैं कि उसने हृदय रोग, कैंसर और मांसपेशीय-हड्डी से जुड़े रोगों को भी पीछे छोड़ दिया है।

अध्ययन के मुताबिक 2023 में दुनियाभर में लगभग 1.2 अरब लोग किसी न किसी मानसिक विकार के साथ जीवन जी रहे थे, जो 1990 की तुलना में लगभग दोगुना है। चिंता की बात यह है कि किशोरों और युवाओं, खासकर 15-19 वर्ष आयु वर्ग, में मानसिक विकार संबंधी मामले सबसे ज्यादा बढ़े हैं। आज के युवाओं पर शैक्षणिक प्रतिस्पर्धा, करियर का भारी दबाव, इंटरनेट मीडिया और सामाजिक तुलना का प्रभाव पहले की अपेक्षा कहीं ज्यादा है। लगातार डिजिटल दुनिया में सक्रिय रहने से अवसाद और चिंता की समस्या युवाओं में तेजी से बढ़ रही है। अध्ययन में महिलाओं में मानसिक विकारों की दर पुरुषों की तुलना में ज्यादा पाई गई। 2023 में लगभग 62 करोड़ महिलाएं मानसिक विकारों से प्रभावित थीं। घरेलू हिंसा, लैंगिक असमानता, सामाजिक दबाव और आर्थिक निर्भरता जैसी परिस्थितियां महिलाओं को मानसिक रूप से ज्यादा संवेदनशील बनाती हैं। एडीएचडी और आटिज्म जैसे न्यूरो-विकासात्मक विकार पुरुषों में ज्यादा पाए गए।

भारत से जुड़े आंकड़े भी चिंताजनक हैं। अध्ययन के मुताबिक देश में चिंता विकारों की व्यापकता 1990 से 2023 के बीच 123 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ी है। महिलाओं में यह बढ़ोतरी और भी ज्यादा रही। भारत में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, प्रशिक्षित चिकित्सकों का अभाव और सामाजिक कलंक (स्टिगमा) स्थिति को गंभीर बना रहे हैं। आज भी मानसिक बीमारियों को लेकर खुलकर बातचीत नहीं होती, जिसकी वजह से ज्यादातर लोग समय पर मदद नहीं ले पाते। इस अध्ययन से पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन की 2025 की एक रिपोर्ट में भी चेतावनी दी गई थी कि दुनिया भर में एक अरब से अधिक लोग मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं से जूझ रहे हैं। इनमें चिंता और अवसाद के मामले सबसे ज्यादा थे। बहरहाल, हालिया शोध यह स्पष्ट संकेत देता है कि मानसिक स्वास्थ्य अब सिर्फ व्यक्तिगत समस्या नहीं रह गया है, बल्कि यह सामाजिक, आर्थिक और सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ा वैश्विक संकट बन चुका है। अगर हमारी सरकारें और समाज समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाते, तो आने वाले वर्षों में इसका प्रभाव मानव जीवन, उत्पादकता और सामाजिक स्थिरता पर और ज्यादा गहरा हो सकता है।

(लेखक विज्ञान के जानकार हैं)

प्रश्नों के घेरे में परीक्षा प्रणाली

'एनटीए के बाद सीबीएसई' शीर्षक से प्रकाशित संपादकीय में शिक्षा एवं परीक्षा प्रणाली में विसंगतियों को रेखांकित किया गया है। देश की शिक्षा व्यवस्था में परीक्षाओं की विश्वसनीयता अत्यंत महत्वपूर्ण आधार होती है। हाल के दिनों में मेडिकल प्रवेश परीक्षा-नीट के प्रश्नपत्र लीक प्रकरण के बाद अब सीबीएसई की पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया में सामने आई विसंगतियों ने शिक्षा प्रणाली की पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर नई चिंता पैदा कर दी है। सीबीएसई देश का सबसे बड़ा शिक्षा बोर्ड माना जाता है। लाखों छात्र इसके माध्यम से भविष्य की दिशा तय करते हैं। ऐसे में यदि छात्र यह शिकायत करें कि उनकी उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कापी उनकी लिखावट से मेल नहीं खा रही, सही उत्तर होने के बावजूद अंक काटे गए हैं या मूल्यांकन में गंभीर त्रुटियां हुई हैं, तो यह अत्यंत चिंताजनक स्थिति है। परीक्षा परिणाम केवल अंक नहीं होते, बल्कि छात्रों के आत्मविश्वास, करियर और मानसिक स्थिति से भी जुड़े होते हैं। छोटी सी लापरवाही भी किसी छात्र के भविष्य पर गहरा असर डाल सकती है। आज शिक्षा व्यवस्था में तकनीक का प्रयोग तेजी से बढ़ा है। आनलाइन मूल्यांकन, ओएमआर स्कैनिंग और डिजिटल रिकार्ड जैसी व्यवस्थाएं पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से लागू की गई थीं, लेकिन यदि इनका संचालन दक्षता और निगरानी के बिना होगा, तो तकनीक सुविधा के बजाय समस्या का कारण बन सकती है। सीबीएसई और अन्य परीक्षा संस्थाएं मूल्यांकन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, त्रुटिरहित और छात्र हितैषी बनाएं। उत्तर पुस्तिकाओं की सुरक्षित स्कैनिंग, प्रशिक्षित मूल्यांकनकर्ता, समयबद्ध शिकायत निवारण और स्वतंत्र निगरानी तंत्र जैसे कदम उठाने होंगे। शिक्षा व्यवस्था में विश्वास बनाए रखना केवल संस्थाओं की जिम्मेदारी नहीं, देश के भविष्य को सुरक्षित रखने का प्रश्न है। शिक्षा संस्थाएं अपनी प्रक्रियाओं की गंभीर समीक्षा करें और पारदर्शिता को सर्वोच्च प्राथमिकता दें।

हिमांशु शेखर, केसपा-गयाजी

युवाओं का टूटता भरोसा

जब किसी परीक्षा का पेपर लीक हो जाता है, तो केवल परीक्षा रद नहीं होती, बल्कि लाखों छात्रों की मेहनत, समय और उम्मीदें भी टूट जाती हैं। बार-बार ऐसी घटनाएं होने से छात्र मानसिक तनाव, बेरोजगारी और निराशा का सामना कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतनी महत्वपूर्ण परीक्षाओं की गोपनीयता बार-बार कैसे भंग हो जाती है? और अब तक इस समस्या का स्थायी समाधान क्यों नहीं निकल पाया है? सरकार को चाहिए कि प्रश्नपत्र लीक करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह पारदर्शी और सुरक्षित बनाया जाए तथा दोषियों को ऐसी कठोर सजा दी जाए, जिससे भविष्य में कोई भी इस तरह की हरकत करने का साहस न कर सके। क्योंकि यदि युवाओं का विश्वास ही टूट गया, तो देश का भविष्य भी कमजोर हो जाएगा।

आदर्श गौतम, कल्याणपुर, कानपुर

मेलबाक्स

सार्वजनिक संसाधन पर कब्जा

अंग्रेजों के दौर में बना दिल्ली जिमखाना क्लब कभी शासक वर्ग का विशिष्ट सामाजिक अड्डा था। हजारों करोड़ रुपये मूल्य की सरकारी जमीन पर दशकों तक प्रतीकात्मक किराये में चलता यह क्लब आम नागरिक को चुभता रहा है। आखिर जिस जमीन पर जनता का अधिकार है, उसका लाभ मुट्ठीभर प्रभावशाली लोगों तक सीमित क्यों रहे? लोकतंत्र का अर्थ केवल चुनाव नहीं, बल्कि सार्वजनिक संसाधनों पर समान अधिकार भी है। जब आम आदमी अपने छोटे से भूखंड के लिए संघर्ष करता है, तब सत्ता के गलियारों से जुड़े विशिष्ट वर्गों को मिली ऐसी सुविधाएं स्वाभाविक रूप से असंतोष पैदा करती हैं। समर्थकों का तर्क है कि जिमखाना क्लब एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संस्था है। यह बात सही हो सकती है, लेकिन तब प्रश्न और बड़ा हो जाता है-यदि यह सचमुच सामाजिक संस्था है, तो इसके दरवाजे समाज के बड़े हिस्से के लिए खुले क्यों नहीं हैं? लोकतंत्र में विरासत बचाई जा सकती है, पर विशेषाधिकार नहीं।

प्रमोद कुमार गोयल, मेरठ

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :

दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,

डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा

ई-मेल : response@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. नॉन एजीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग,रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001 से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा-201309 से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

1100 से ज्यादा बीमारियों की उत्पति के कारण, सैकड़ों औषधीय पौधों के प्रयोग और शल्य चिकित्सा करने के निर्देशों का वर्णन है सुश्रुत संहिता में।

आजकल

विरासत से ही समृद्ध बनेगा भारत

पिछले दिनों एनसीईआरटी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के कार्यान्वयन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भारतीयता के मूल्यों के आधार पर शैक्षिक पाठ्यक्रम लागू किया। ये पाठ्यपुस्तकें विद्यार्थियों को भारतीय संस्कृति, इतिहास और मूल्यों से जोड़ती हैं। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों में रचनात्मक सोच को बढ़ावा देना, भारतीय ज्ञान परंपरा को नई पीढ़ी से जोड़ना और गणित को सिर्फ गणना नहीं, अपितु इतिहास, सोच और नवाचार के संगम के रूप में प्रस्तुत करना है

डा. सुशील पाण्डेय
प्राध्यापक, इतिहास, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय, लखनऊ

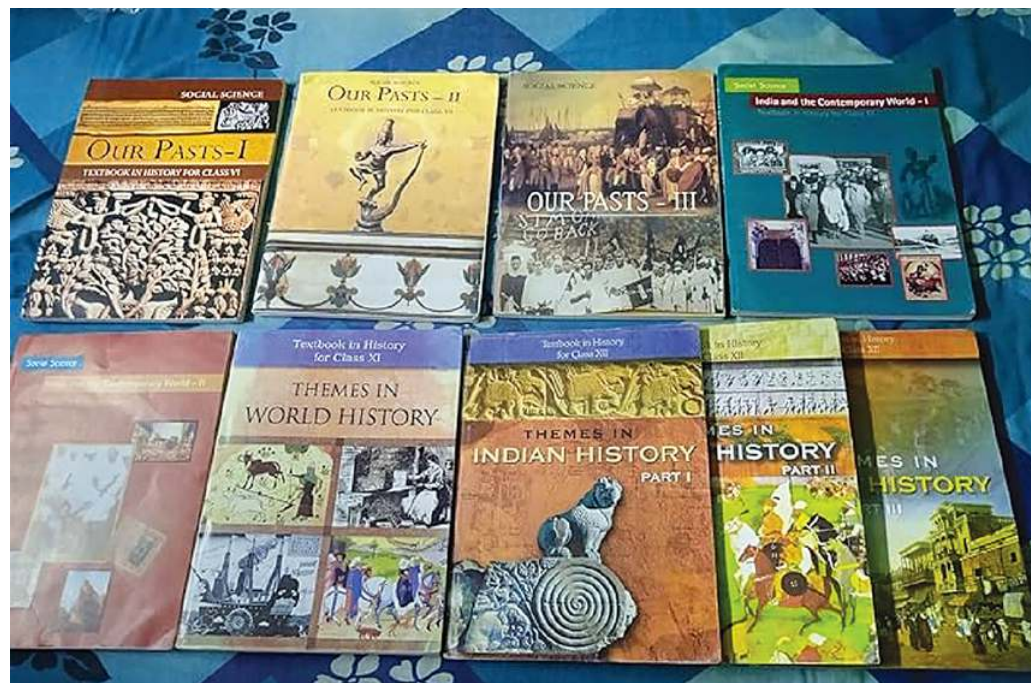

छात्रों को भारतीय ज्ञान-विज्ञान से परिचित कराती पाठ्यपुस्तकें। फाइल

एनसीईआरटी ने हाल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के कार्यान्वयन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भारतीयता के मूल्यों के आधार पर शैक्षिक पाठ्यक्रम लागू किया। इसके अंतर्गत विद्यार्थियों के लिए परशुराम-लक्ष्मण संवाद, रानी लक्ष्मीबाई की शौर्य गाथा और संत रविदास के पद, भारतीय जय-विजय जैसे पाठ शामिल किए गए हैं। ये कहानी और कविताएं राष्ट्रीय भावना, भक्ति और राष्ट्रवादी सामग्री से न सिर्फ परिपूर्ण हैं, अपितु विद्यार्थियों को भारतीय संस्कृति, इतिहास और मूल्यों से जोड़ती हैं। इसी प्रकार गणित की किताब 'गणित मंजरी' में पारंपरिक गणित ज्ञान को आधुनिक शिक्षा पद्धति के साथ जोड़ा गया है। इस पुस्तक में फार्मूलों के स्थान पर भारत की समृद्ध गणित विरासत को इतिहास, दर्शन और व्यवहार से जोड़कर प्रस्तुत किया गया है। इस पुस्तक में विद्यार्थियों के रचनात्मक सोच को बढ़ावा देना, भारतीय ज्ञान परंपरा को नई पीढ़ी से जोड़ना और गणित को सिर्फ गणना नहीं, अपितु इतिहास, सोच और नवाचार के संगम के रूप में प्रस्तुत करना है। गत दिनों दक्षिण एशियाई पांडुलिपियों का इतिहास और दस्तावेज संग्रह परियोजना के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन द्वारा आयोजित 'शून्य से अनंत तक गणित में भारतीय सभ्यता का योगदान' शीर्षक वाली प्रदर्शनी में विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने विचार दिया कि भारत की वैज्ञानिक प्रगति को लंबे समय से संकीर्ण दृष्टिकोण से देखा गया है, जबकि भारत की प्राचीन गणितीय विरासत आधुनिक विज्ञान और तकनीकी की नींव है। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में ऐसी पहली गणित प्रदर्शनी आयोजित हुई है, जिसका उद्देश्य ऐतिहासिक गलत धारणाओं को ठीक करने और भारत के योगदान को मान्यता देना है।

किसी भी राष्ट्र की शिक्षा व्यवस्था उसके सामाजिक, सांस्कृतिक जीवन का दर्शन और उसके नागरिकों की चेतना का आधार होती है। प्रत्येक राष्ट्र ने अपने सामाजिक तथा सांस्कृतिक उत्थान के लिए अपने अनुभव और परंपराओं पर आधारित शिक्षा व्यवस्था को स्वीकार किया है। प्रत्येक राष्ट्र की शिक्षा व्यवस्था पर उसके भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक चुनौतियों का प्रभाव होता है। अपनी विशिष्ट परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा प्रणाली स्वीकार करके ही राष्ट्र अपने अनुकूल विकास के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। भारत में औपनिवेशिक शासन स्थापित होने के बाद इसे निरंतर बनाए रखने के लिए भारत की शिक्षा व्यवस्था और चिंतन धारा को अवरुद्ध करने का प्रयास किया गया। मैकाले की शिक्षा पद्धति ने भारतीय ज्ञान, विज्ञान और शिक्षा व्यवस्था को नष्ट कर दिया और भारतीयों में स्वयं की सभ्यता संस्कृति के प्रति अविश्वास का भाव विकसित किया।

प्राचीन भारत की शिक्षा पद्धति सत्य के अन्वेषण और व्यक्ति के समग्र विकास पर आधारित थी। प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करके इस प्रकार का वैज्ञानिक चिंतन विकसित किया गया, जो प्रकृति के निर्देशों के आधार पर संचालित होता था। गुरुकुल में विद्यार्थियों को आध्यात्मिक, नैतिक और मानवीय गुणों की शिक्षा दी जाती थी। विद्यार्थियों की क्षमता और अभिरुचि के आधार पर उन्हें जीविकोपार्जन के लिए व्यावसायिक शिक्षा दी जाती थी। परिणामतः विद्यार्थी न तो तनाव में आते थे, नहीं कोई नकारात्मक विचार से प्रभावित होते थे। प्राचीन भारत की शिक्षा व्यवस्था में मौलिक चिंतन और व्यावहारिक ज्ञान का मिश्रण था। विदेशी आक्रमणों ने शिक्षा के केंद्रों और पुस्तकालयों को नष्ट कर दिया जिससे लिपिबद्ध ज्ञान नष्ट हो गया। संस्कृत का प्रयोग कम हो जाने से ज्ञान की परंपरा अगली पीढ़ी तक नहीं पहुंच पाई। प्राचीन भारत की ज्ञान परंपरा की दो महत्वपूर्ण विशेषताएं थीं। विभिन्न विषयों को सरल माध्यम और कहानियों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया, ताकि आमजन भी उस विज्ञान को अपने जीवन में अंगीकृत कर सके। दूसरा गणित और विज्ञान को धर्म से जोड़कर प्रस्तुत किया गया जिससे आम जनमानस में उसकी स्वीकार्यता हो सके। बाद में इस ज्ञान-विज्ञान को यूरोपीय औपनिवेशिक विचारक संस्कृत भाषा और पूर्वाग्रह के कारण अंधविश्वास के रूप में प्रस्तुत किए।

यूरोपीय दार्शनिक वाल्टेयर (15 दिसंबर, 1775) लिखते हैं, "मैं इस बात को लेकर पूर्णतः आश्वस्त हूं कि खगोल विज्ञान, ज्योतिष, आध्यात्म इत्यादि सब कुछ हमें गंगा के तट से प्राप्त हुआ है। पाइथागोरस गंगा के तट पर रेखा गणित सीखने गए थे। यदि यूरोप में भारतीयों की मेधा की अपार प्रतिष्ठा नहीं होती तो निश्चित ही पाइथागोरस ऐसी दुरूह यात्रा पर नहीं जाते!" हाल में इर्विंग मेडिकल सेंटर, कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने अपनी वेबसाइट पर लिखा कि प्लास्टिक सर्जरी की शुरुआत भारतीय महर्षि सुश्रुत ने ईसा पूर्व 600 ईस्वी में की थी। सुश्रुत संहिता में 1100 से ज्यादा बीमारियों की उत्पत्ति के कारण, सैकड़ों औषधीय पौधों के प्रयोग और शल्य चिकित्सा करने के निर्देशों का वर्णन है, जिसमें तीन प्रकार के त्वचा प्रत्यारोपण और नासिका के पुनर्निर्माण के तरीके भी शामिल हैं। जापानी विज्ञानी योशीनोरी ओहसुमी को 2016 में आटोफेगी का सिद्धांत देने के कारण चिकित्सा शास्त्र का नोबेल मिला। अथर्ववेद में 'लघनम परम औषधम' का सिद्धांत आटोफेगी ही है। प्राचीन भारतीय गणितज्ञ आचार्य पिंगल ने अपनी पुस्तक छंदशास्त्र में बाइनरी संख्या प्रणाली और फिबोनाची अनुक्रम को प्रस्तुत किया। उन्होंने संख्याओं के इस अनुक्रम को मात्रामेरू कहा है। पश्चिमी गणितज्ञों से 1600 साल पहले आचार्य पिंगल ने बाइनरी गणित की नींव रखी, जो आधुनिक कंप्यूटिंग के लिए अहम है। महर्षि गौतम ने न्याय दर्शन में आधुनिक नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का विचार प्रस्तुत किया, जो एआइ का आधार है।

प्राचीन भारत के दार्शनिक और विज्ञानी गणित, खगोल शास्त्र, चिकित्सा विज्ञान, रसायन शास्त्र, भौतिक विज्ञान में अत्यधिक पारंगत थे। भारतीय विज्ञान पश्चिमी विज्ञान से बिल्कुल अलग दृष्टिकोण से विकसित हुआ। भारतीय विज्ञान प्रकृति का अनुसरण करते हुए अथर्ववेद के दर्शन 'माता भूमिः पुत्रो अहम पृथिव्याः' के सिद्धांत पर विकसित हुआ। भारतीय विज्ञानी प्रकृति के साथ संघर्ष न करके साहचर्य के आधार पर और सभी प्राणियों के बीच सह अस्तित्व के आधार पर वैज्ञानिक चिंतन प्रस्तुत करते थे। महर्षि कणाद ने परमाणु का सिद्धांत प्रस्तुत किया, लेकिन उसका उपयोग विनाशकारी हथियार बनाने के लिए नहीं किया। भारतीय विज्ञानी प्रकृति के रहस्यों को जानते थे और उनके दुरुपयोग के दुष्परिणामों से पूर्णतः परिचित थे। भारत पर अरबों के आक्रमण से पश्चिमी जगत से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित हुआ और भारतीय ज्ञान-विज्ञान अरबों के माध्यम से यूरोप पहुंचा। यूरोपीय विज्ञानियों ने इसे नए संदर्भ में प्रस्तुत करके इसका श्रेय प्राप्त किया। विदेशी आक्रमणों के कारण भारतीय ज्ञान की परंपरा कमजोर हो गई और पांडुलिपियों में सीमित रह गई।

आज राजनीतिक आजादी के अमृत काल में भारतीय समाज में नया आत्मविश्वास और दृष्टिकोण सामने आ रहा है। भारतीय समाज सामाजिक, सांस्कृतिक और ज्ञान की विरासत के आधार पर नए भारत का निर्माण करने का विचार रखता है। आज भारतीय शिक्षाविदों को अपने प्राचीन ज्ञान पर आत्ममुग्ध न होकर उसे नए संदर्भ में वैज्ञानिक तथ्यों और प्रमाणों के साथ प्रस्तुत करना होगा। प्राचीन ज्ञान से सीख कर आधुनिक परिप्रेक्ष्य में विज्ञान को पुनः प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। आज भारतीय विज्ञानी दुनिया के श्रेष्ठ संस्थानों में अपनी मेधा प्रस्तुत कर रहे हैं। भारतीय इतिहास मूलतः ज्ञान, मानवता, तार्किकता का इतिहास है जिसने संपूर्ण विश्व को शांति और समृद्धि का मार्ग दिखाया है। ज्ञान भारतम् मिशन इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण पहल है, जहां परंपरागत भारतीय ज्ञान, जो पांडुलिपियों में संकलित है, को आधुनिक परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया जा रहा है।

गुलामी की मानसिकता से भी मिले मुक्ति

लंबे समय से गुलामी की मानसिकता और पराजयबोध ने भारतीय समाज को दिग्भ्रमित कर दिया। भारतीय इतिहास और ज्ञान की परंपरा को सही संदर्भ में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे भारतीय समाज गौरव बोध प्राप्त नहीं कर पाया। किसी भी समाज को अपने श्रेष्ठतम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्वदेशी मूल्यों का विकास अनिवार्य है। औपनिवेशिक राजनीतिक संरचना को चुनौती देने के लिए स्वदेशी आंदोलन और भारतीय मूल्य और नैतिकता ही मुख्य आधार बनें। आज वैश्विक चुनौतियों के संदर्भ में भारतीय ज्ञान परंपरा और भारतीय विचारधारा को महत्व देने की आवश्यकता है। आज भारत अपने मेधावी युवा वर्ग और मानव संसाधन के कारण एक ज्ञानवान समाज बनने की ओर आगे बढ़ रहा है। विद्यार्थियों को प्रारंभ से ही अपनी सभ्यता और संस्कृति के तत्वों से परिचित कराना पड़ेगा जिससे वे अपनी श्रेष्ठ सांस्कृतिक विरासत पर गर्व कर सकें और उसके आधार पर नए भारत का निर्माण कर सकें।

भारतीय ज्ञान परंपरा केवल अतीत की स्मृति नहीं, बल्कि भविष्य निर्माण की मजबूत आधारशिला है। आज दुनिया पर्यावरण संकट, मानसिक तनाव, नैतिक पतन जैसी समस्याओं से जूझ रही है। ऐसे समय में भारतीय चिंतन जीवन को संतुलन, सह-अस्तित्व और मानवता का मार्ग दिखाता है। शिक्षा नीति-2020 के माध्यम से भारतीय संस्कृति और परंपराओं को पाठ्यक्रम से जोड़ने का प्रयास स्वागतयोग्य है। इससे विद्यार्थियों में अपनी जड़ों के प्रति सम्मान और आत्मविश्वास विकसित होगा। आज जरूरत भारतीय ज्ञान को आधुनिक संदर्भों में प्रमाण और शोध के आधार पर प्रस्तुत करने की है। यदि हम अपनी विरासत को विज्ञान, तकनीक और नवाचार से जोड़ दें, तो भारत विश्व को दिशा देने में सक्षम होगा। सांस्कृतिक आत्मविश्वास और ज्ञान परंपरा का समन्वय ही विकसित और आत्मनिर्भर भारत का वास्तविक आधार बन सकता है।

खरी-खरी

इच्छाधारी इंसान

डा. यशोधरा भटनागर

सुना है और फिल्मों में देखा भी है कि पहले हमारे देश में इच्छाधारी सांप हुआ करते थे। अब विज्ञान और समाज दोनों ने प्रगति कर ली है। इच्छाधारी सांप तो विलुप्त हो गए हैं और उनकी जगह इच्छाधारी आदमी पैदा हो गए हैं। फर्क यह है कि सांप रूप बदलने से पहले केंचुली छोड़ता था, जबकि आदमी रूप बदलने से पहले जमीर छोड़ता है। पहले इच्छाधारी नाग फिल्मों में मिलते थे, अब इच्छाधारी आदमी हर गली, दफ्तर, संस्था, मंच और रिश्तेदारी में पाए जाते हैं। सांप फुफकारकर डराता था, जबकि यह आदमी मुस्कुराकर डसता है।

हमारे मोहल्ले के नेता जी को देखिए। चुनाव घोषित होते ही उनमें सेवा-भाव इस तरह फूट पड़ता है जैसे राष्ट्रप्रेम जाग गया हो। हर दरवाजे पर हाथ जोड़कर पहुंचते हैं- 'मैं आपका बेटा हूं'। जनता भी भावुक होती है। पांच साल गड्ढों में गिरकर भी उसे उम्मीद रहती है कि शायद नेता सच बोल रहा हो। लेकिन जैसे ही कुर्सी मिलती है, वही 'बेटा' अचानक 'माननीय' में बदल जाता है। फिर जनता उसे देखने के लिए तरसती है। फोन नेता जी की जगह पीए उठाता है और मिलने की जगह आश्वासन मिलता है।

अब आदमी नौकरी नहीं करता, अभिनय करता है। आफिस में बास के सामने झुककर चलता है, लेकिन बास के जाते ही कुर्सी पर फैलकर बैठ जाता है। मीटिंग में 'यस सर' बोलने वाला आदमी कैंटीन में बास को लोकतंत्र का खतरा घोषित करता है। इंटरनेट मीडिया ने इच्छाधारी इंसानों को राष्ट्रीय मंच दे दिया है। प्रोफाइल पर 'सादा जीवन, उच्च विचार' लिखने वाला आदमी पांच सितारा होटल में काफी पीते हुए फोटो डालता है।

आजकल लोग चरित्र नहीं, 'इमेज' बनाते हैं। पहले साधु बनने के लिए जंगल जाना पड़ता था, अब संत बनने के लिए रिंग लाइट और इंस्टाग्राम अकाउंट चाहिए। आदमी के पास इतने चेहरे हैं कि असली चेहरा आधार कार्ड में भी संदिग्ध लगता है। पुराने इच्छाधारी सांप प्रेम, प्रतिशोध या शाप में रूप बदलते थे, जबकि आधुनिक इच्छाधारी आदमी पेट्रोल के दाम, प्रमोशन और चुनाव टिकट के हिसाब से रंग बदलता है।

पोस्ट

कोलकाता में अपने इलाके में मुझे बदलाव दिखा। मुस्लिम बहुल बस्ती के एक क्लब में बकरीद से पहले चार-पांच गाय बंधी होती थीं और ईद के अगले दिन एक भी गाय नहीं दिखती थी। कारण तो पता था, पर मैं बेबस थी। इस बार एक हफ्ता बीत गया, कोई गाय नहीं दिखी। मैंने इसी 'परिवर्तन' को वोट दिया था। विनीता सिंह@biharigurl

सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि एसआइआर की प्रक्रिया पूरी तरह सही है और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए जरूरी है। इसमें कुछ भी अप्रत्याशित नहीं है। एसआइआर पहले से होता रहा है। अब शायद उन दलों, नेताओं को अक्ल ठिकाने आए, जो सिर्फ माहौल खराब करने के लिए विरोध कर रहे थे। महेश पोद्दार@maheshpoddarmp

सचिन पायलट बनाम गहलोत के बाद अब डीके शिवकुमार बनाम सिद्दरमैया। भाजपा नेतृत्व ने कई राज्यों में सीएम चुनने में अप्रत्याशित निर्णय लेकर एक तीर से कई निशाने साधे। मजबूत केंद्र का संकेत देने, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने और भविष्य की राजनीति के लिए नई पीढ़ी तैयार करने की रणनीति। वहीं कांग्रेस ने जीती हुई बाजी हारी हैं। राजेश शुक्ला@astroraj

जागरण जनमत कल का परिणाम

क्या कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन से कांग्रेस को राजनीतिक लाभ मिलेगा?

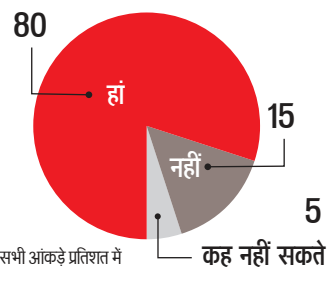

सभी आंकड़े प्रतिशत में

आज का सवाल

क्या एसआइआर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला विपक्षी दलों के लिए बड़ा झटका है?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है

जनपथ

बंग्लादेशी बार्डर पर लग रही कतार,
यही लोग हैं भाइयों टीएमसी के यार।
टीएमसी के यार गई है जबसे सत्ता,
तुरत हो गया बंद सभी का राशन-भत्ता।
बोरिया-बिस्तर बांध चल पड़े सब परदेसी,
अपने घर की राह ढूंढते बंग्लादेशी!
-ओम प्रकाश तिवारी

धनंजय प्रताप सिंह
डिप्टी पालिटिकल एडिटर (स्टेट), मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेश डायरी

अब सरस्वती लोक के निर्माण की तैयारी

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले के बाद भोजशाला में पूजा करने के लिए उमड़े श्रद्धालु। प्रेट्र

अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के बाद मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित भोजशाला दूसरा ऐसा मामला है, जिसमें हाई कोर्ट के निर्णय से मंदिर के पुनर्निर्माण का रास्ता साफ हुआ है। दोनों मामलों में एक समानता सैकड़ों साल की प्रतीक्षा की भी है। भोजशाला में वाग्देवी मंदिर के लिए करीब 700 साल से लंबा इंतजार है। अब मोहन सरकार ने यहां 200 करोड़ रुपये की लागत से सरस्वती लोक बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। साथ ही भोज शोध संस्थान भी स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव ने लंदन के ब्रिटिश संग्रहालय में रखी मां वाग्देवी की प्रतिमा को वापस लाने की घोषणा भी की है।

भोजशाला का इतिहास परमार राजवंश के सबसे बड़े शासक राजा भोज से जुड़ा है, जो शिक्षा एवं साहित्य के लिए विशेष रूप से समर्पित थे। उन्होंने धार में अद्वितीय विद्या केंद्र की स्थापना की थी, जिसे भोजशाला के रूप में पहचान मिली। पुरातात्विक प्रमाणों ने यहां सरस्वती मंदिर की उपस्थिति बताई है। साथ ही इतिहास में दर्ज है कि मुस्लिम शासक अलाउद्दीन खिलजी ने इसे ध्वस्त करते हुए मस्जिद में परिवर्तित कर दिया था। इसके अवशेष कमाल मौला मस्जिद में देखे जा सकते हैं। सैकड़ों वर्षों तक हिंदू वाग्देवी की नियमित पूजा के लिए प्रतीक्षा में थे, लेकिन वर्ष 2003 से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) ने सह-अस्तित्व की व्यवस्था लागू करते हुए मंगलवार को हिंदुओं को पूजा और शुक्रवार को मुस्लिम समुदाय को नमाज की अनुमति दी थी। शेष दिनों में भोजशाला पर्यटकों के लिए खुली रहती थी। अब बिना किसी रोक-टोक के नियमित पूजा-अर्चना करने का अधिकार हिंदू पक्ष को प्रदान किया गया है।

दरअसल सनातन संस्कृति के वैभवशाली इतिहास की पुनर्स्थापना के लिए केंद्र और एनडीए शासित राज्यों की सरकारों के प्रयासों से आस्था के सम्मान के साथ पर्यटन को भी नए सिरे से बढ़ावा मिल रहा है। पर्यटकों ने अब उन धार्मिक स्थलों का रुख करना शुरू कर दिया है, जहां नवाचार के प्रयास किए गए हैं। पर्यटन के मानचित्र पर उज्जैन तब और उभर कर आया, जब श्री महाकाल महालोक के निर्माण के बाद सबसे अधिक पर्यटक वहां पहुंचे। वर्ष 2024 में मध्य प्रदेश में लगभग 13.41 करोड़ पर्यटक आए थे, जो पिछले साल (2023) की तुलना में करीब 20 प्रतिशत अधिक थे। इनमें सबसे ज्यादा 7.32 करोड़ पर्यटक उज्जैन पहुंचे थे।

वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर में कारिडोर के निर्माण के बाद भी पर्यटकों की संख्या में काफी बड़ी वृद्धि देखी गई है। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने कई धार्मिक स्थलों पर ऐसे लोक के निर्माण की शुरुआत की थी, जिसे मोहन सरकार ने आगे बढ़ते हुए कई नए स्थलों को भी जोड़ा है। ओरछा में 332 करोड़ रुपये के विकास कार्यों के साथ श्रीराम राजा लोक का निर्माण, तो मैहर में 775 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से शारदा लोक, दमोह के बांदकपुर में 100 करोड़ रुपये की लागत से जागेश्वर लोक, सलकनपुर में देवी लोक और छिंदवाड़ा के जाम सांवली में 314 करोड़ रुपये की लागत से हनुमान लोक का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा इंदौर के पास भगवान परशुराम की जन्मस्थली जानापाव कुटी में 17.5 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से परशुराम-कृष्ण लोक भी बन रहा है।

मध्य प्रदेश में मोहन सरकार मंदिर परिसरों में निर्माण संबंधी नवाचार से आगे बढ़ते हुए श्रीकृष्ण पाथेय और श्रीराम वन गमन पथ के भी निर्माण का बीड़ा उठा चुकी है। यह अपनी तरह का अनूठा प्रयोग है, जो हिंदू पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। डा. मोहन यादव स्पष्ट कर चुके हैं कि भगवान श्रीकृष्ण की लीलाओं से संबंधित स्थलों को धाम के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसमें मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान भी जुड़ेगा, वहीं श्रीराम वन गमन पथ को लेकर जो तैयारी है, वह मध्य प्रदेश में पर्यटन के नए अध्याय की शुरुआत करेगी। निश्चित तौर पर इन प्रयासों से मध्य प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।

मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद डा. मोहन यादव ने साफ्ट हिंदुत्व की राह चुनी है। बड़ी बारीकी से वह किसी भी मामले को विवादित होने से बचाते हुए अपनी प्रशासनिक दक्षता और कौशल से सुलझाते रहे हैं। भोजशाला मामले में दो अपील सुप्रीम कोर्ट में हैं। इसके बावजूद उन्होंने इसे किसी पक्ष की जीत-हार या भविष्य में होने वाले टकराव की ओर न जाते हुए पूरे मामले को विकास के दृष्टिकोण से ही देखा और धार के विकास को भोजशाला से जोड़ते हुए धार्मिक पर्यटन की संभावनाओं के संकेत दिए हैं।

सनातन संस्कृति के गौरवशाली अध्यायों की पुनर्स्थापना में डा. मोहन यादव का यह अंदाज आने वाले समय में मिसाल के तौर पर भी याद रखा जाएगा।

हिमाचल प्रदेश डायरी

उठो एचआरटीसी, तुम्हें जीना है

नवनीत शर्मा
राज्य संपादक, हिमाचल प्रदेश

मंगलवार को नौ महीनों के बाद एशिया के सबसे ऊंचे सड़क मार्ग पर जब हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) की लेह-दिल्ली बस चली तो एक चित्र देखा। 1839 रुपये में 26 घंटे की यात्रा करवाने वाले चालक-परिचालक बहुत आत्म सम्मान और गर्व के साथ बस के आगे खड़े थे। बारालाचा के साथ और दर्रे भी लांघती है यह बस, लेकिन सबसे ऊंचा दर्रा संभवतः तांगलंग ला है, जिसकी ऊंचाई 5,328 मीटर है। जिस प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता, वह यह है कि जनजातीय, कठिन, शीत मरुस्थल और कहीं बर्फ से भरे क्षेत्रों में चालक परिचालक सुरक्षित रहते हैं, लेकिन कथित विकसित, शिक्षित, सभ्य क्षेत्र में उतरते ही उन पर हमले क्यों होने लगते हैं?

शिमला में हाल में 'हिमसुता' यानी पथ परिवहन निगम की वोल्वो बस के चालक को हरियाणा के चार लोगों ने इसलिए पीट दिया कि उसने इन्हें ओवरटेक क्यों किया। वारदात शिमला शहर में हुई। निगम के चालक-परिचालक पहले भी पिटते आए हैं, कभी नालागढ़, कभी पंजाब में, कभी चंडीगढ़ में। कभी गुंडों से, कभी निजी बस संचालकों के लोगों से। पिटना नई बात नहीं, लेकिन इस बार बात इसलिए बढ़ी, क्योंकि चालक को छह टांके लगवाने पड़े। शिमला शहर की बात थी, चालक पर आई आपदा वस्तुतः यात्रियों के पास लाइव घटना की रील बनाने का दुर्लभ अवसर था, इसलिए घटना वायरल हो गई। पुलिस कार्रवाई इसलिए भी हुई, क्योंकि कर्मचारी हड़ताल पर बैठ गए, चक्का जाम कर दिया। यह प्रश्न अनुत्तरित है कि हाल में नालागढ़ में भी निगम के स्टाफ के साथ ऐसी मारपीट हुई थी। वहां शायद इसलिए विरोध नहीं हुआ, क्योंकि चालक वोल्वो का नहीं, गांव के रूट की साधारण बस का था। कुल मिलाकर अक्टूबर 2025 से अब तक छह प्रमुख मामले मारपीट के हुए हैं। क्या यहां भी वर्ग विभेद है? 'सजग साधना सविनय सेवा' के लिए जानी जाती एचआरटीसी अपने इस सूत्रवाक्य पर खरी भी उतरी है, लेकिन अब इसका इकबाल लड़खड़ाता प्रतीत होता है। निगम इस प्रकार के मनोवैज्ञानिक झटकों से ही नहीं, आर्थिक झटकों से भी गुजर रहा है। सड़क पर किसी भी सिरफिरे से मार खाने वाला यह वर्ग वेतन के लिए जूझ रहा है, पेंशन के लिए जूझ रहा है, मेडिकल रिएंबर्समेंट तो भूल ही जाएं, 80 महीनों से रात्रि भत्ता या ओवरटाइम नहीं मिला।

जब हिमाचल प्रदेश क्लास सी स्टेट बना तो पंजाब, रेलवे और हिमाचल प्रदेश ने मिल कर कुल्लू-मंडी ट्रांसपोर्ट की स्थापना की, ताकि पंजाब और हिमाचल के बीच आवागमन की सार्वजनिक सुविधा हो। कुल्लू-मनाली मार्ग पर उस समय की, लंबे नाक वाली, भोंपू हार्न बजाने वाली बसें हिंदी फिल्मों में भी दिखी हैं। 1966 में जब पुनर्गठन हुआ तो हिमाचल पथ परिवहन निगम की स्थापना हुई। इन सरकारी बसों ने पूरे हिमाचल को जोड़ा...एचआरटीसी बस को जांबाज चालक कैसे कठिनतम मार्गों पर चलाते हैं, इंस्टाग्राम पर कुछ रील्स यह भी दिखाती हैं। हाल में निगम ने 50 वर्ष पूरे करने पर एक काफी टेबल बुक भी प्रकाशित की थी, जो 'अंग्रेजी' में थी। अब एचआरटीसी का हाल क्या है? पश्चिम एशिया का संघर्ष ताजा है, एचआरटीसी पहले से घाटे को जी रहा है। अब 2200 करोड़ के घाटे में डूबे निगम पर महंगे डीजल की मार पड़ रही है। एचआरटीसी प्रतिमाह 35 से 36 करोड़ रुपये डीजल पर खर्च करता है, जबकि इसकी 3200 बसें प्रतिदिन 5.60 लाख किलोमीटर का सफर तय करती हैं। निगम पर सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करने से घाटा साल दर साल बढ़ता जा रहा है।

दरअसल एचआरटीसी में दो संसार हैं। एक वह जो सड़कों पर निगम के लिए लड़ता है, मार खाता है। दूसरा वह जिसे सब हरा दिखता है। शासक हों या प्रशासक। किसी भी मुख्य स्टेशन पर निजी बस वालों को टाइम फालो करने के लिए कहते हुए जो लोग लड़ते हैं, वही मार खाते हैं। कहते भी हैं, 'सर हम तो झगड़ा करते हैं निगम का एक एक रुपया बचाने के लिए, पर अफसरों का क्या करें। आरटीओ साहब भी कोई चीज होते हैं। उन्हें कई कुछ देखना होता है।' बात में दम है। एक साहब तो इतने अच्छे आरटीओ थे कि हर दल की सरकार ने उन्हें आरटीओ ही रखा। गलती से एसडीएम या कुछ बने भी तो अंततः आरटीओ बन कर ही चैन पाया। अब ज्ञान का आलोक कर रहे हैं।

प्रदेश के हर कस्बे से दिल्ली के लिए निजी लग्जरी बसें भी चलती हैं। ये टैक्सी परमिट हैं। स्टेज कैरिज नहीं। निगम के हर डिपो को इनके संचालन से ही हर माह चार से पांच लाख रुपये की चपत लग रही है। मगर, अधिकारी और नीति नियंता क्या यह सब नहीं जानते होंगे? सरकारी बसें किसी भी मोड़ पर रुकती हुई निढाल दिखती हैं...उन स्त्रियों की तरह जिन्हें जमाने भर का काम होता है, वे हारना नहीं चाहतीं...पर एक सीमा होती है। ऊपर के संसार में वर्कशाप प्रबंधक, ट्रैफिक प्रबंधक, क्षेत्रीय प्रबंधक, मंडलीय प्रबंधक, सहायक महाप्रबंधक, महाप्रबंधक, मुख्य महाप्रबंधक....सब हैं। बस प्रबंधन गायब है। चार वर्षों से कोई बस नहीं खरीदी गई। जो हैं, उनके पुर्जे नहीं हैं, टायर, ल्यूब्रिकेंट सब का अभाव है और नीयत का भी। उठो एचआरटीसी, तुम्हें जीना है।

हिमाचल की राजधानी शिमला में रविवार को एचआरटीसी के चालक को पीटने के आरोप में चालकों ने लगाया जाम। जागरण

पुष्प ब्रांड ने सेबी के पास आइपीओ दस्तावेज जमा किए

नई दिल्ली: इंदौर की मसाला विनिर्माता कंपनी पुष्प ब्रांड (इंडिया) ने सेबी के पास आइपीओ के जरिये धन जुटाने के लिए शुरुआती दस्तावेज दाखिल किए हैं। प्रस्तावित आइपीओ का आकार 800 करोड़ रुपये से 1,000 करोड़ रुपये के बीच रहने की संभावना है। मंगलवार को दाखिल आइपीओ दस्तावेजों (डीआरएचपी) के अनुसार, यह निर्गम पूरी तरह 74.45 लाख इक्विटी शेयरों की बिक्री पेशकश के रूप में होगा। (प्रेट्र)

भारत अपने विशाल डेवलपर आधार और मजबूत डिजिटल ढांचे के बल पर वैश्विक एआइ क्षेत्र के अगले चरण के विस्तार का नेतृत्व करने के लिए सक्षम स्थिति में है।

– जय पारेख, माइक्रोसाफ्ट में कोरएआइ के कार्यकारी उपाध्यक्ष

संसेक्स	75,867.80	▼ 141.90
निफ्टी	23,907.15	▼ 6.55
सोना प्रति दस ग्राम	₹ 1,61,300	▼ ₹ 1,100
चांदी प्रति किलो ग्राम	₹ 2,69,700	▼ ₹ 3,300
डालर	₹ 95.58	▼ ₹ 0.12
क्रूड प्रति बैरल	$ 96.35	

एक नजर में

12,800 रुपये महंगे होंगे हुंडई के वाहन

नई दिल्ली: कार निर्माता कंपनी हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड अपने वाहनों की कीमतें माडल और वेरिएंट के आधार पर 12,800 रुपये तक बढ़ाएगी। कंपनी ने कहा कि कीमतों में यह बदलाव का फैसला कई तरह की लागतों में हुई वृद्धि के कारण लिया गया है। कमोडिटी की बढ़ती कीमतें और परिचालन खर्चों में वृद्धि, जैसे कारणों से कीमतों में यह बढ़ोतरी करना जरूरी था। कंपनी ने कहा, 'हालांकि कंपनी लागत को कम करने और ग्राहकों पर इसके असर को कम रखने की कोशिश करती है, लेकिन बढ़ी हुई लागत का कुछ हिस्सा उपभोक्ताओं पर डालना पड़ रहा है। (प्रेट्र)

ओएनजीसी का लाभ चौथी तिमाही में 6,650 करोड़

नई दिल्ली: ओएनजीसी का शुद्ध लाभ 2025-26 की चौथी तिमाही में तीन प्रतिशत बढ़कर 6,649.97 करोड़ रुपये रहा। इससे पिछले वर्ष 2024-25 की इसी तिमाही में यह 6,448.28 करोड़ रुपये। इस दौरान परिचालन राजस्व मामूली रूप से बढ़कर 35,928.18 करोड़ रुपये हो गया, जो वित्त वर्ष 2024-25 की चौथी तिमाही में 34,982.23 करोड़ रुपये था। कंपनी ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए प्रति शेयर एक रुपये के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है। (प्रेट्र)

आइटीआर-2 दाखिल करने की आनलाइन सुविधा शुरू

नई दिल्ली: आयकर विभाग ने आकलन वर्ष 2026-27 के लिए आयकर रिटर्न-2 को आनलाइन दाखिल करने की सुविधा शुरू कर दी है। अब करदाता ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर आइटीआर-2 आनलाइन भर सकते हैं। आइटीआर-2 उन व्यक्तिगत करदाताओं और हिंदू अविभाजित परिवारों द्वारा भरा जाता है, जिनकी आय व्यवसाय या पेशे से नहीं होती, लेकिन उन्हें पूंजीगत लाभ होता है। इससे पहले आइटीआर-1 ओर 4 को आनलाइन दाखिल करने की सुविधा शुरू की गई थी। (प्रेट्र)

अमेरिका से ट्रेड डील 24 जुलाई से पहले संभव

व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर के लिए दस्तावेज को अंतिम रूप देने एक जून को नई दिल्ली आ रही टीम

- अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के सभी देशों पर 10% शुल्क लगाने की अवधि 24 जुलाई को हो रही खत्म
- निर्णायक बैठक के दौरान बाजार पहुंच, टैरिफ, निवेश, मोबिलिटी जैसे कई मुद्दों पर होगी वार्ता

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: व्यापार समझौते को लेकर भारत और अमेरिका के बीच बन चुकी सहमति को वैधानिक स्वरूप प्रदान करने के लिए अमेरिकी टीम एक जून को भारत आ रही है। समझौते से जुड़े दोनों देशों के मुख्य वार्ताकार के नेतृत्व में चार जून तक नई दिल्ली में बैठक होगी। इस बैठक में बाजार पहुंच, टैरिफ, निवेश, मोबिलिटी जैसे कई मुद्दों पर वार्ता होगी ताकि व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर के लिए उसके दस्तावेज को अंतिम रूप दिया जा सके।

अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक अभी अमेरिका में सभी देशों की वस्तुओं पर 10 प्रतिशत का शुल्क लगता है। इस शुल्क की अवधि आगामी 24 जुलाई को समाप्त हो रही है। ऐसे में माना जा रहा है इससे पहले दोनों देशों के बीच व्यापार समझौता हो जाएगा। अमेरिका ने भारत समेत दुनिया के 50 से अधिक देशों पर पारस्परिक शुल्क लगाने का एलान किया था। इसके तहत भारत पर 25 प्रतिशत का पारस्परिक शुल्क लगाया गया था। रूस से तेल खरीदने को गलत मानते हुए अमेरिका ने भारत पर जुर्माने के रूप में पिछले साल अगस्त में और 25 प्रतिशत का शुल्क लगा दिया। इस दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को लेकर वार्ता होती रही और 18 प्रतिशत शुल्क पर समझौते के लिए सहमति बनी।

हालांकि, इसी बीच अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने पारस्परिक शुल्क को अवैध ठहराते हुए राष्ट्रपति ट्रंप के पारस्परिक शुल्क के आदेश को अवैध करार दे दिया और आगामी 24 जुलाई तक सभी देशों पर 10 प्रतिशत का शुल्क लगने का आदेश दिया। भारत अमेरिका के बीच इससे पहले ही सहमति बन सकती है।

भारत ने यूएसटीआर के आरोपों को किया खारिज : अमेरिकी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव (यूएसटीआर) ने मार्च में, 1974 के ट्रेड एक्ट की धारा 301 के तहत, भारत समेत कई देशों के खिलाफ दो एकतरफा जांच शुरू की थी। ये जांच ज्यादा उत्पादन क्षमता व ग्लोबल सप्लाई चेन में जबरदस्ती मजदूरी खत्म करने में नाकाम रहने के मामलों पर आधारित थीं। भारत ने यूएसटीआर द्वारा उन दोनों जांचों में लगाए गए आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है।

अमेरिका भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापार साझेदार : 2025-26 में अमेरिका भारत का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर था। पिछले वित्त वर्ष के दौरान, भारत से अमेरिका को होने वाला निर्यात थोड़ा बढ़कर (0.92%) 87.3 अरब डालर हो गया जबकि आयात 15.95 प्रतिशत बढ़कर 52.9 अरब डालर हो गया। इससे ट्रेड सरप्लस 2024-25 के 40.89 अरब डालर से घटकर 2025-26 में 34.4 अरब डालर हो गया। अभी चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार है।

प्रतिद्वंद्वी देशों से कम शुल्क पर ही भारत व्यापार समझौते पर करेगा हस्ताक्षर

वाणिज्य मंत्रालय का कहना है कि भारत व्यापार समझौते के लिए उसी दर पर अपनी सहमति देगा जब भारत को अमेरिका के बाजार में प्रतिद्वंद्वी देशों पर बढ़त दिखेगी। प्रतिद्वंद्वी देशों से कम शुल्क पर ही भारत व्यापार समझौता करना चाहेगा। पिछले साल 50 प्रतिशत शुल्क के बाद अमेरिका के बाजार में भारतीय निर्यात की बढ़ोतरी दर प्रभावित होने लगी थी। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा निर्यात बाजार है, इसलिए अमेरिका के साथ व्यापार समझौते को काफी अहम माना जा रहा है।

खाद ने बढ़ाई सरकार की चिंता, बढ़ सकता है राजकोषीय घाटा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: होर्मुज बंद होने से खाद की वैश्विक कीमत बढ़ती जा रही है। पिछले दो महीनों में खाद की कीमत 70-75 प्रतिशत तक बढ़ चुकी है और इससे सरकार पर वित्तीय दबाव बढ़ता जा रहा है। वित्त मंत्री ने भी दो दिन पहले एक कार्यक्रम में खाद पर नजर रखने की जरूरत बताई थी।

देश में 50 प्रतिशत खाद की जरूरत आयात से पूरी होती है। किसानों को सरकार खाद सब्सिडी के साथ देती है, इसलिए हर साल सरकार को खाद सब्सिडी के मद में खासी रकम का आवंटन करना पड़ता है। चालू वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में खाद सब्सिडी के लिए 1.7 लाख करोड़ का आवंटन किया गया था। पश्चिम एशिया संकट के कारण अब खाद सब्सिडी बढ़कर तीन लाख करोड़ को पार कर सकती है। अगर अक्टूबर तक पश्चिम एशिया संकट जारी रहा तो खाद सब्सिडी बिल 3.5 लाख करोड़ के पार जा सकती है।

इससे राजकोषीय घाटा बढ सकता है। चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा जीडीपी 4.3 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है जो 16.93 लाख करोड़ रुपये होता है।

दुनिया की एक तिहाई खाद होर्मुज के रास्ते से आती है। वैश्विक स्तर पर 42 प्रतिशत यूरिया की तो 21 प्रतिशत डीएपी की सप्लाई पश्चिम एशिया से होती है। फरवरी में यूरिया की कीमत 482 डालर प्रति टन थी जो 850 डालर प्रति टन को पार कर चुकी है। अगले महीने यह कीमत 900 डालर प्रति टन को पार कर जाएगी।

बिजनेस से जुड़ी खबरों और अपडेट के लिए स्कैन करें या विजिट करें jagran.com

एयरटेल ने अप्रैल में जोड़े 34.82 लाख नए ग्राहक

नई दिल्ली, प्रेट्र: भारती एयरटेल अप्रैल में शुद्ध रूप से 34.82 लाख नए ग्राहक जोड़कर सभी खंडों में ग्राहक वृद्धि के मामले में शीर्ष पर रही। इतना ही नहीं कंपनी ने वायरलाइन खंड में भी अपने प्रतिद्वंद्वी रिलायंस जियो को पीछे छोड़ते हुए अधिक संख्या में नए ग्राहक जोड़े। दूरसंचार नियामक ट्राई की मासिक ग्राहक रिपोर्ट के अनुसार, अप्रैल में कुल दूरसंचार ग्राहकों की संख्या 69.5 लाख बढ़कर अब तक के उच्चतम स्तर 133.75 करोड़ पर पहुंच गई।

एयरटेल के शुद्ध रूप से कुल नए ग्राहकों की संख्या अप्रैल, 2026 में 34.82 लाख रही। इसमें वायरलेस या मोबाइल खंड के 31.39 लाख और वायरलाइन खंड के 3.43 लाख ग्राहक शामिल हैं। जियो के शुद्ध रूप से कुल नए ग्राहकों की संख्या 30.84 लाख रही, जिसमें 29.42 लाख नए मोबाइल कनेक्शन और 1.42 लाख वायरलाइन कनेक्शन शामिल हैं।

एचडीएफसी बैंक के शेयर 3% गिरे, एमकैप 31,331 करोड़ घटा

नई दिल्ली, प्रेट्र: बुधवार को एचडीएफसी बैंक के शेयर लगभग तीन प्रतिशत गिर गए। बीएसई पर शेयर 2.63 प्रतिशत गिरकर 758.50 रुपये पर बंद हुआ। दिन के दौरान, यह 2.87 प्रतिशत गिरकर 756.60 रुपये पर आ गया। शेयर में गिरावट के बाद, बैंक का बाजार पूंजीकरण 31,331.59 करोड़ रुपये गिरकर 11,67,811.80 करोड़ रह गया।

दरअसल, शेयर में यह गिरावट मीडिया में आई उन रिपोर्टों के बाद दर्ज की गई, जिसमें कहा गया था कि 45 करोड़ रुपये का कथित भुगतान उसके मार्केटिंग विभाग के जरिये महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम को किया गया। इस भुगतान को कथित तौर पर मार्केटिंग खर्च के तौर पर दिखाया गया था। ये भुगतान बैंक के पूर्व चेयरमैन अतानु चक्रवर्ती के इस्तीफे से कुछ दिन पहले किए गए थे। चक्रवर्ती ने एक चौंकाने वाले कदम के तहत, नैतिक चिंताओं का हवाला देते हुए एचडीएफसी बैंक के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि, बैंक के प्रवक्ता ने इन आरोपों को खारिज किया है।

इन्फोसिस को अदाणी पावर ने पीछे छोड़ा

बुधवार को इन्फोसिस को पीछे छोड़कर अदाणी पावर बाजार पूंजीकरण के लिहाज से देश की 11वीं सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। बाजार बंद होने पर अदाणी पावर का बाजार मूल्यांकन 4,79,706.78 करोड़ रुपये था, जबकि इन्फोसिस का 4,70,111.69 करोड़ रुपये था। उधर, अदाणी समूह की कंपनियों का कुल मूल्यांकन 20 लाख करोड़ रुपये के करीब पहुंच गया है।

गेहूं का उत्पादन 12.06 करोड़ टन रहने का अनुमान

नई दिल्ली, प्रेट्र: बेमौसम बारिश एवं ओलावृष्टि के कारण हुए नुकसान के बावजूद गेहूं का उत्पादन फसल सत्र 2025-26 के दौरान 2.29 प्रतिशत बढ़कर 12.06 करोड़ टन रहने का अनुमान है। यह अनुमान कृषि मंत्रालय के 2025-26 के मानसून की शुरुआत में लगाए गए 12.02 करोड़ टन उत्पादन के अनुमान के अनुरूप है। यह फसल सत्र 2024-25 में दर्ज 11.79 करोड़ टन गेहूं उत्पादन से अधिक है।

कृषि मंत्रालय ने जुलाई 2025-जून 2026 सत्र के लिए प्रमुख कृषि फसलों का तीसरा अनुमान जारी करते हुए कहा, 'गेहूं का उत्पादन 12.06 करोड़ टन होने का अनुमान है, जो एक साल पहले की तुलना में 27.12 लाख टन अधिक है।' 2025-26 के लिए कुल खाद्यान्न उत्पादन बढ़कर 37.65 करोड़ टन रह सकता है जबकि एक साल पहले 35.77 करोड़ टन रहा था।

पश्चिम एशिया संकट से निपटने के लिए गैर जरूरी आयात पर लगे रोक

- थिंक चेंज फोरम ने कहा-गहरे तनाव से गुजर रहा वैश्विक आर्थिक परिदृश्य
- इस तरह के झटकों से निपटने के लिए अब सब्सिडी देना टिकाऊ तरीका नहीं रहा

नई दिल्ली, प्रेट्र: पश्चिम एशिया संकट के कारण उत्पन्न आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए भारत को करों में कमी और गैर जरूरी वस्तुओं के आयात पर रोक लगानी होगी। इसके अलावा, कारोबार से जुड़े सुधारों को समयसीमा के अंदर लागू करना होगा। थिंक चेंज फोरम की रिपोर्ट के मुताबिक, वैश्विक आर्थिक परिदृश्य एक गहरे तनाव से गुजर रहा है और पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक अस्थिरता जरूरी क्षेत्रों जैसे ऊर्जा, कृषि और मैन्यूफैक्चरिंग में लागत जनित महंगाई को बढ़ावा दे रही है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि इन झटकों से निपटने के लिए सब्सिडी पर निर्भर रहना अब टिकाऊ तरीका नहीं रह गया है। यह नीति वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए जरूरी ढांचागत दक्षता को हतोत्साहित करती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को खत्म करके और गैर-जरूरी सामानों के आयात को सीमित करके भारत राजकोषीय अनुशासन बनाए रखते हुए अपने घरेलू औद्योगिक आधार को सुरक्षित कर सकता है। रिपोर्ट में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के हवाले से कहा गया है कि गैर जरूरी सामानों का आयात कम करना अब केवल एक मितव्ययिता का उपाय नहीं है बल्कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेशी मुद्रा की मजबूती का आधार स्तंभ है।

अमेरिका-ईरान जंग से बीमा क्षेत्र भी होगा प्रभावित

एलआइसी के सीईओ और एमडी आर. दोराईस्वामी ने कहा कि अगर पश्चिम एशिया संकट लंबे समय तक बना रहता है तो बीमा क्षेत्र में कुछ नरमी देखने को मिल सकती है। उन्होंने कहा कि अगर पूरा समाज प्रभावित होता है और लोगों की आय तथा उनकी बचत करने की क्षमता पर असर पड़ता है, तो ज़ाहिर है कि इसका असर बीमा उद्योग पर भी पड़ सकता है। पश्चिम एशिया में युद्ध छिड़ने के बाद अर्थव्यवस्था के कई हिस्से, खासकर ऊर्जा क्षेत्र, प्रभावित हुए हैं, जिससे आर्थिक विकास में सुस्ती और बढ़ती महंगाई का डर पैदा हो गया है।

राष्ट्रीय फलक

उत्तराखंड में जंगल में लगी आग गोशाला तक पहुंची, बुझाने गई महिला की झुलसकर मौत

जागरण संवाददाता, चमोली

उत्तराखंड में जंगल की आग विकराल होती जा रही है। चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, बागेश्वर, पौड़ी के जंगलों में लगी आग आबादी के करीब पहुंच रही है। चमोली के बूंगा गांव में जंगल में लगी आग मंगलवार रात गोशाला के करीब पहुंच गई। आग बुझाने के लिए गई महिला सुरेशी देवी (51) उसकी चपेट में आ गई। झुलसी सुरेशी देवी की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। एक हफ्ते पहले चमोली में ही जंगल में लगी आग की चपेट में आकर वन विभाग के एक फायर वाचर की मौत हो गई थी। ज

मंगलवार रात आठ बजे के आसपास बूंगा गांव की सुरेशी देवी गोशाला में जा रही थीं। तभी उन्होंने देखा कि जंगल में लगी आग गोशाला की ओर बढ़ रही है। अन्य ग्रामीण भी गोशाला और गांव की सीमा के पास पहुंची आग को बुझाने में जुटे थे। सुरेशी देवी भी अपनी गोशाला के नीचे भड़की आग को बुझाने का प्रयास करने लगीं। इसी दौरान वह चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गईं। जिले में आदि बदरी, कर्णप्रयाग और गौचर की पहाड़ियों में आग लगने का सिलसिला जारी है। आग के कारण चारों ओर धुआं ही धुआं छा गया है।

चमोली के आदि बदरी क्षेत्र के जंगलों में लगी आग लगातार फैल रही है। इसे नियंत्रित करने की चुनौती बनी है। फोटो- पंकज सती, ग्रामीण

भारत को कैंसर जीन थेरेपी का वैश्विक उत्पादन केंद्र बनाएगी मेडथेरेपी बायोटेक

राज्य ब्यूरो, जागरण, मुंबई : कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के इलाज में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाली सीएआर-टी (काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर) सेल थेरेपी का उत्पादन केंद्र अब भारत बनने जा रहा है। प्रमुख बायोटेक कंपनी 'मेडथेरेपी बायोटेक' ने इस आधुनिक जीन थेरेपी को बड़े पैमाने पर तैयार करने की रणनीति बनाई है। कंपनी का लक्ष्य भारत को इस थेरेपी का वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है।

मेडथेरेपी बायोटेक के सीईओ डा. विकास वर्मा ने बताया कि इस प्रभावी मानी जाने वाली थेरेपी की शुरुआत अमेरिका में 2017 में हुई थी। हालांकि, जटिल प्रक्रिया और महंगा होने के कारण यह इलाज आम मरीजों की पहुंच से दूर है। उनकी कंपनी इसे किफायती बनाकर हर जरूरतमंद मरीज तक पहुंचाना चाहती है। भारत में इस थेरेपी के बड़े पैमाने पर उत्पादन से कैंसर चिकित्सा में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और चिकित्सा पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।

लेह में 11,400 फीट की ऊंचाई पर सिंधु नदी पर देश का पहला हिमालयी राक चेक डैम तैयार

राज्य ब्यूरो, जागरण • जम्मू

लद्दाख के लेह में पानी की कमी को दूर करने के लिए उपशी क्षेत्र में 11,400 फीट की ऊंचाई पर सिंधु नदी पर देश का पहला हिमालयी राक चेक डैम बनकर तैयार हो गया है। पूरी तरह स्थानीय स्तर पर उपलब्ध विशाल चट्टानों से इसका निर्माण सात दिन में पूरा किया गया है। राक चेक डैम में गर्मियों में चार करोड़ लीटर पानी को स्टोर करना संभव होगा। लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने इस राक चेक डैम का उद्घाटन किया।

उपशी में राक चेक डैम बनाने का कार्य 12 मई को शुरू हुआ और इसे 18 मई तक पूरा कर लिया गया था। इस दौरान उपराज्यपाल ने कई बार स्थल का दौरा कर स्वयं इसकी निगरानी की। यह परियोजना लेह में हर वर्ष उत्पन्न होने वाले जल संकट से निपटने के लिए पर्यावरण अनुकूल व कम लागत वाला समाधान मानी जा रही है। चेक डैम की लंबाई करीब 200 फुट है। इसके बनने से सिंधु नदी के उथले हिस्सों में जल स्तर बढ़ाने में मदद मिली है। इस राक डैम के बनने से किसानों को फसल लगाने के मौसम में सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिल सकेगा। यह परियोजना लद्दाख के संवेदनशील नदी तटीय पारिस्थितिकी तंत्र को सुरक्षित रखने में भी सहायक होगी।

यह योजना लद्दाख जैसे हिमालयी क्षेत्र में जल संरक्षण के साथ कृषि में एक महत्वपूर्ण व टिकाऊ पहल साबित हो सकती है। लद्दाख में गर्मियों के महीने में सिंचाई के लिए पानी की कमी किसानों को प्रभावित करती है।

लद्दाख के लेह में पानी की कमी को दूर करने के लिए उपशी में बना राक चैक डैम। सूचना विभाग

एमेजोन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अमेरिकी ई-कामर्स कंपनी एमेजोन को राहत देते हुए राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) के जून, 2022 के उस आदेश को रद कर दिया, जिसमें कंपनी के फ्यूचर समूह के साथ सौदे को निलंबित करने के भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआइ) के फैसले के खिलाफ अपील की गई थी। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने 17 दिसंबर, 2021 के सीसीआई के एमेजोन पर 202 करोड़ का जुर्माना लगाने और फ्यूचर ग्रुप के साथ उसके सौदे को निलंबित करने के आदेश को भी रद कर दिया। पीठ ने कहा कि यदि इन आदेशों के तहत एमेजोन से कोई राशि जमा कराई गई है या वसूली गई है, तो उसे आठ सप्ताह में वापस किया जाए। कोर्ट ने में कहा,'अपील स्वीकार की जाती है। एनसीएलएटी का 13 जून, 2022 का फैसला और सीसीआइ का 17 दिसंबर, 2021 का आदेश रद्द किया जाता है।'

कश्मीर में रेल सेवा से खिले बागवानों के चेहरे, 43 टन चेरी देशभर में भेजी

जागरण संवाददाता, जम्मू

जम्मू-कश्मीर के चेरी उत्पादकों के लिए रेलवे भरोसेमंद परिवहन का बड़ा माध्यम बनकर उभरा है। चेरी सीजन के दौरान अब तक 43 टन ताजा चेरी रेल मार्ग से देश के विभिन्न हिस्सों में भेजी जा चुकी है। इससे बागवानों और व्यापारियों के चेहरे खिल उठे हैं। इस पहल से किसानों का मुनाफा तो बढ़ा ही है, चेरी की ताजगी भी बरकरार है

रेलवे अधिकारियों के अनुसार, ट्रेन संख्या 12472, 12474, 12476, 12920 और 19028 में एसएलआर तथा पार्सल यान के माध्यम से चेरी की खेप सूरत, बांद्रा, भोपाल और छायापुरी वडोदरा सहित कई शहरों तक पहुंचाई गई। रेल से कम समय में चेरी सुरक्षित तरीके से बाजारों तक पहुंच रही है, जिससे उसकी गुणवत्ता बनी हुई है। किसानों को बेहतर दाम मिल रहे हैं। छोटे और बड़े व्यापारी पार्सल बुकिंग करा पा रहे हैं।

चेरी को प्रदेश से बाहरी राज्य में भेजने के लिए उसे ट्रक से ट्रेन में लोड करते हुए। फोटो :रेलवे

बागवान सीधे बड़े बाजारों तक अपनी उपज भेज पा रहे हैं। यात्री ट्रेनों में पार्सल स्थान के उपयोग से रेलवे को अतिरिक्त आय भी प्राप्त हो रही है। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक जम्मू उचित सिंघल ने बताया कि रेलवे किसानों और व्यापारियों को परिवहन सुविधा देने के लिए प्रतिबद्ध है। 43 टन चेरी का रेल मार्ग से भेजा जाना इसका प्रमाण है कि फल उत्पादकों का रेलवे पर भरोसा लगातार बढ़ रहा है।

केदारनाथ में खच्चरों के चारे में छिपा ले जाई जा रही थी 494 बोतल अंग्रेजी शराब

जागरण संवाददाता, रुद्रप्रयाग : केदारनाथ यात्रा को नशामुक्त बनाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। फाटा चौकी पुलिस और एसओजी रुद्रप्रयाग की संयुक्त टीम ने खच्चरों के चारे में छिपाकर ले जाई जा रही अंग्रेजी शराब की 494 बोतलें बरामद की हैं। पुलिस ने एक आरोपित को गिरफ्तार कर हुए तस्करी में प्रयुक्त पिकअप वाहन को भी सीज कर दिया है।

पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर यात्रा मार्गों में शराब की अवैध बिक्री और तस्करी रोकने के लिए सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी दौरान चौकी फाटा और एसओजी टीम ने फाटा के पास एक संदिग्ध पिकअप वाहन को रोका और तलाशी ली। शुरुआती जांच में वाहन में खच्चरों का चारा लदा दिखाई दिया, लेकिन तलाशी लेने पर चारे के नीचे छिपाकर रखी गई अंग्रेजी शराब की 494 बोतल बरामद हुई।

प्रयागराज के आइटेक जोन केंद्र की 29-30 मई की भी परीक्षा स्थगित

राज्य ब्यूरो, जागरण • प्रयागराज

- कांस्टेबल जीडी-2026 परीक्षा में 25 व 26 मई को छात्रों ने की थी तोड़फोड़

कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) की कांस्टेबल जीडी-2026 परीक्षा में प्रयागराज के झूंसी स्थित सुनीता सिंह सीता सिंह महिला महाविद्यालय का आइटेक जोन केंद्र अव्यवस्था के कारण विवादों के घेरे में है। इस केंद्र पर 29 और 30 मई को होने वाली परीक्षा भी स्थगित कर दी गई है। प्रभावित छात्रों की परीक्षा अब 29, 30 और 31 मई को अलग-अलग केंद्रों पर कराई जाएगी।

एसएससी मध्य क्षेत्र प्रयागराज की ओर से परीक्षा स्थगन से संबंधित सूचना बुधवार को जारी की गई है। प्रभावित अभ्यर्थियों के नए प्रवेश पत्र एसएससी मुख्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध कराए जाएंगे। मालूम हो कि 25 मई को क्षमता से लगभग दोगुना अभ्यर्थियों के पहुंचने के कारण द्वितीय और तृतीय पाली की परीक्षा निरस्त करनी पड़ी थी। नाराज अभ्यर्थियों ने हंगामा कर तोड़फोड़ की थी। इसके बाद 26 मई को भी स्थिति सामान्य नहीं हो सकी। तकनीकी कारणों से परीक्षा करीब 20 मिनट देरी से शुरू हुई, लेकिन परीक्षा समाप्त होने से लगभग 25 मिनट पहले ही सिस्टम बंद हो गए। इससे नाराज अभ्यर्थियों ने तोड़फोड़, चक्काजाम किया। ऐसे में एसएससी ने 26 मई की सभी पालियों की परीक्षा रद कर 27 मई की परीक्षा भी स्थगित कर दी थी। एसएससी मध्य क्षेत्र ने इस केंद्र की 29 और 30 मई की परीक्षा भी स्थगित कर दी। उप्र और बिहार के 41 केंद्रों पर यह परीक्षा कराई जा रही है, जिनमें अधिकांश केंद्रों पर परीक्षा सामान्य रही। ऐसे में प्रयागराज के इसी केंद्र पर बार-बार गड़बड़ी होना संकेत देता है कि समस्या केवल तकनीकी खराबी से हटकर केंद्र स्तर की व्यवस्थागत कमजोरी भी हो सकती है।

रक्षा सौदों में भ्रष्टाचार मामले में कई वित्तीय सलाहकार भी सीबीआइ के रडार पर

जागरण संवाददाता, कानपुर : रक्षा सौदों में कथित रिश्वतखोरी, हवाला कारोबार और फर्जी तरीके से ठेके हासिल करने के मामले में सीबीआइ की जांच अब कारोबारियों के साथ ही वित्तीय सलाहकारों तक पहुंच गई है। जांच एजेंसी को शक है कि हवाला के जरिये आए करोड़ों रुपये को वैध दिखाने, कंपनियों के वित्तीय दस्तावेज तैयार करने व कई संदिग्ध सौदों को कानूनी संरक्षण देने में कुछ पेशेवर फर्मों की भूमिका रही है। इसी आधार पर कई वित्तीय सलाहकारों की फर्मों को एजेंसी ने रडार पर रखा है।

सीबीआइ ने कर्नल हिमांशु बाली समेत पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। चार दिनों से कानपुर समेत आसपास के जिलों में डेरा डाले सीबीआइ अधिकारी लगातार कारोबारी नेटवर्क की परतें खोलने में जुटे हैं। 50 से अधिक लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया जा चुका है।

एसआईआर पर मुहर

सर्वोच्च न्यायालय ने फिर विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को सही ठहराते हुए, इसे पूर्णतः वैध करार दिया है। शीर्ष न्यायालय ने बिहार में मतदाता सूची के पुनरीक्षण को चुनौती देने वाली कुछ याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) को विशेष गहन पुनरीक्षण का अधिकार है और आयोग ने किसी भी वैधानिक या सांविधानिक प्रावधान का उल्लंघन नहीं किया है। लगे हाथ, न्यायालय ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि चुनाव आयोग को पुनरीक्षण करते हुए नागरिकता जांचने का भी अधिकार है। याचिकाओं में यह आशंका जताई गई थी कि चुनाव आयोग द्वारा किसी मतदाता के नाम को सूची में शामिल न करने का मतलब नागरिकता छीनना होगा। न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है, सूची में नाम न होने से नागरिकता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जिन लोगों के नाम नागरिकता न होने की वजह से कट गए हैं, उनकी सुनवाई चुनाव आयोग को करनी पड़ेगी। सुनवाई करते हुए संबंधित अधिकारियों को यह देखना होगा कि कहीं किसी योग्य व्यक्ति का नाम सूची से न कट जाए।

कोई दोराय नहीं कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए समय-समय पर मतदाता पुनरीक्षण जरूरी है। सांविधानिक योजना और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत चुनाव आयोग को मतदाता सूची में संशोधन करने का पूरा अधिकार है। पुनरीक्षण का राजनीतिक स्तर पर विरोध करने वालों ने चुनाव आयोग के अधिकार को ही चुनौती दी थी। बिहार की बात करें, तो खासकर विपक्षी पार्टियों की यह कोशिश थी कि चुनाव आयोग किसी भी मतदाता का नाम न काट सके। वोट चोरी को एक बड़ा मुद्दा बनाकर पेश किया गया। पश्चिम बंगाल के चुनाव में भी वोट चोरी और मतदाता पुनरीक्षण से जुड़े सवाल बार-बार पूछे गए। पश्चिम बंगाल की तत्कालीन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी स्वयं ही सर्वोच्च न्यायालय में पुनरीक्षण को चुनौती देने के लिए पहुंच गई थीं। ऐसे में, पश्चिम बंगाल में न्यायिक अधिकारियों के मातहत पुनरीक्षण की सुनवाई करनी पड़ी। एक जगह न्यायिक अधिकारियों को बंधक भी बनाया गया। हर प्रकार से विरोध के बावजूद पुनरीक्षण का काम रुका नहीं और अब विधानसभा चुनाव भी संपन्न हो गए हैं। फिर भी, पश्चिम बंगाल पर सुनवाई हो सकती है, पर बिहार की याचिकाओं को सर्वोच्च न्यायालय ने अंतिम रूप से निपटा दिया है। जिनके नाम कट गए हैं, उन्हें निराशा नहीं होना चाहिए, उनके पास पर्याप्त समय है कि वे अपना नाम सूची में जुड़वाएं। एक बार नाम कट जाने का अर्थ यह नहीं कि वह फिर सूची में नहीं आएगा।

तमिलनाडु से शिकायत नहीं है और अगर बिहार से शिकायतें हैं, तो इसका मतलब, पुनरीक्षण की प्रक्रिया गलत नहीं है, पुनरीक्षणकर्ताओं ने लापरवाही की है।

ध्यान रहे, पुनरीक्षण का कार्य अनेक राज्यों में हुआ है, पर शिकायतें दो राज्यों से ज्यादा आई हैं। ऐसा क्यों हुआ, यह समझने की जरूरत है। चुनाव आयोग को इसकी समीक्षा ईमानदारी से करनी चाहिए। आयोग के पास अपने स्वतंत्र कर्मचारी नहीं होते हैं। वह सरकारी कर्मचारियों (बीएलओ) और राजनीतिक पार्टियों के एजेंट (बीएलए) की ताकत से ही काम करता है। जहां बीएलए और बीएलओ सतर्क रहते हैं, वहां पुनरीक्षण कार्य आसानी से हो जाता है, पर जहां ये गड़बड़ी या कोताही करते हैं, वहां शिकायतें आती हैं। तमिलनाडु से शिकायत नहीं है और अगर बिहार से शिकायतें हैं, तो इसका मतलब, पुनरीक्षण की प्रक्रिया गलत नहीं है, पुनरीक्षणकर्ता लापरवाही कर रहे हैं। चुनाव आयोग को अपने स्तर पर पुख्ता दिशा-निर्देश बनाने चाहिए और उनके तहत ही पूरा समय लेकर पुनरीक्षण के काम को अंजाम देना चाहिए।

अमेरिका-ईरान समझौते के बनते आसार

यहां स्कैन करें

फ्रैंक एफ इस्लाम | अमेरिकी उद्यमी व समाजसेवी

अमेरिका-ईरान युद्ध के तीन महीने हो गए। इसे खत्म करने को लेकर यदि कोई सहमति बनती है, तो इससे खुद अमेरिका के लिए एक कठिन दौर खत्म होगा।

कई हफ्तों की बातचीत के बाद अमेरिका और ईरान एक ऐसे समझौते के करीब पहुंच रहे हैं, जो मध्य-पूर्व के मौजूदा संघर्ष को समाप्त कर सकता है। हालांकि, अभी यह साफ नहीं है कि ऐसा कोई समझौता क्षेत्रीय तनाव का स्थायी समाधान साबित होगा या फिर उसे महज अस्थायी विराम देगा।

बीते शनिवार, यानी 23 मई को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह घोषणा की कि अमेरिका और ईरान के बीच समझौते को लेकर 'काफी हद तक बातचीत' हो चुकी है और उसे बस अंतिम रूप देना बाकी है। ईरानी विदेश मंत्रालय ने भी यही संकेत दिया कि व्यापक बातचीत शुरू होने से पहले, एक शुरुआती समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर हो सकता है। बेशक, राष्ट्रपति ट्रंप ने बाद में कहा कि वह समझौते को लेकर जल्दबाजी नहीं करेंगे, लेकिन सप्ताहांत के घटनाक्रम बता रहे हैं कि दोनों पक्ष औपचारिक समझौते के बेहद करीब पहुंच गए हैं। हालांकि, ऐसी किसी सहमति के करीब पहुंचना भी एक बड़ी प्रगति है। यह उस सैन्य-नीति में बदलाव का साफ संकेत है, जो बीते तीन महीनों से वाशिंगटन और तेहरान के रिश्तों पर हावी है।

इस युद्ध की शुरुआत 28 फरवरी को हुई थी और इसने पश्चिम एशिया की राजनीतिक व आर्थिक तस्वीर को पूरी तरह से बदलकर रख दिया है। इंसानी जान-माल के नुकसान के अलावा, इसने वैश्विक ऊर्जा बाजार को बाधित किया, वित्तीय प्रणालियों को हिला दिया और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में गहरी अनिश्चितता पैदा कर दी। होर्मुज जलमार्ग को लेकर बढ़ती चिंताओं के कारण तेल की कीमतों में बार-बार उछाल आया और बाजार व सरकारों को एक बार फिर यह एहसास हुआ कि फारस की खाड़ी की अस्थिरता अपने क्षेत्र तक सीमित नहीं रह सकती।

भारत और यूरोप इस संघर्ष के बेमतलब में शिकार बन गए हैं। युद्ध-क्षेत्र से दूर रहने और संघर्ष में सीधी भागीदारी न होने के बावजूद इन दोनों को आर्थिक झटके झेलने पड़े। मध्य-पूर्व की जंग शायद ही कभी क्षेत्रीय घटना बनकर रह जाती है। उसका असर ऊर्जा बाजार, व्यापार मार्ग और वित्तीय प्रणालियों पर पड़ता है, जिससे हजारों मील दूर की अर्थव्यवस्थाएं भी गहरे प्रभावित होती हैं। भारत पर दबाव इस रूप में भी अधिक है कि यहां ईंधन, रसोई गैस व उर्वरकों की कीमतों में उछाल जारी है, क्योंकि यह अपनी जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा आयात करता है। ऊर्जा की बढ़ती कीमतें अंततः परिवहन लागत और विनिर्माण खर्च बढ़ाएंगी, जिससे महंगाई बढ़ जाएगी और इससे घरेलू ही नहीं, कारोबारी बजट भी प्रभावित होगा।

यह संघर्ष सिर्फ ऊर्जा बाजार को प्रभावित नहीं कर रहा। भारत सहित ज्यादातर दक्षिण एशियाई देशों के लाखों नागरिक खाड़ी के मुल्कों में रहते हैं। वे वहां से हर साल अरबों डॉलर की रकम बतौर 'रेमिटेंस' अपने-अपने मुल्क में भेजते हैं। इसका सीधा अर्थ है कि खाड़ी देशों की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाला कोई भी संघर्ष इन परिवारों पर भी सीधा प्रभाव डालता है।

यूरोप भी इसी तरह की गंभीर चुनौतियों से जूझ रहा है। ऊर्जा सुरक्षा संबंधी चिंताओं के साथ-साथ वह पूर्व से मौजूद अस्थिर आर्थिक विकास को दूर करने की कोशिशों में जुटा था। ऐसे में, इस संघर्ष ने उसके ईंधन बाजार, आपूर्ति श्रृंखलाओं और मुद्रास्फीति पर नए सिरे से दबाव पैदा कर दिया है।

अगर कोई समझौता आकार लेता है, तो अमेरिका से पूछा जाएगा कि यदि कूटनीति से ही पश्चिम एशिया का तनाव खत्म हो सकता था, तो उसने सैन्य-संघर्ष का रास्ता क्यों चुना? महीनों के इस युद्ध से आखिर क्या हासिल हुआ? सैन्य कार्रवाई के समर्थकों का तर्क था कि संघर्ष का मकसद ईरान की परमाणु क्षमताओं को कमजोर करना और उसकी महत्वाकांक्षाओं को खत्म करना था। उन्हें यह उम्मीद थी कि सैन्य कार्रवाई से तेहरान में सत्ता-परिवर्तन हो जाएगा। जाहिर है, ऐसा कुछ नहीं हुआ, अलबत्ता उन ताकतों को मजबूती ही मिली, जिनको कमजोर करने के लिए अमेरिका और इजरायल ने इस युद्ध की शुरुआत की थी।

इतिहास सावधानी बरतने के कारण देता है। इराक युद्ध ने भी क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को इस कदर बदल दिया था, जिसकी किसी ने भविष्यवाणी नहीं की थी। इसी तरह, अफगानिस्तान और लीबिया में भी सैन्य कार्रवाइयों का नतीजा लक्ष्य से काफी अलग निकला। वास्तव में, मध्य-पूर्व ने बार-बार बताया है कि सैन्य कार्रवाइयों के नतीजे युद्धक्षेत्र की आंकड़ेबाजी से कहीं अधिक व्यापक हो सकते हैं। कल्पना कीजिए, यदि संभावित समझौते से ईरान को प्रतिबंधों में ढील मिल जाती है और उसके व्यापार-मार्ग फिर से खुल जाते हैं, तो तेहरान को नए सिरे से आर्थिक लाभ मिलेगा ही, उसका क्षेत्रीय प्रभाव भी बढ़ जाएगा।

सऊदी अरब, कतर, संयुक्त अरब अमीरात जैसे खाड़ी के देशों ने तनाव कम करने के संभावित प्रयासों का समर्थन किया है, क्योंकि उनकी ओर से यही कहा जा रहा है कि लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष आर्थिक विकास और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा पैदा करते हैं। उनके समर्थन ने राष्ट्रपति ट्रंप को अपनी कूटनीति को आगे बढ़ाने के मौके दिए हैं।

अमेरिका में भी इसका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। युद्ध शायद ही लंबे समय तक विदेश नीति का मुद्दा बना रहता है। वह अंततः आर्थिक और राजनीतिक मुद्दा ही बनता है। ऊर्जा की बढ़ती कीमतें घरेलू बजट को प्रभावित करती हैं, जबकि आर्थिक मुश्किलों से मतदाताओं की सोच आकार लेती है। लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष से जनता को मिलने वाली थकान राजनीतिक गठबंधनों को भी बदल सकती है।

ट्रंप के राजनीतिक आधार में मतभेद स्पष्ट नजर आने भी लगे हैं। पारंपरिक विदेश नीति के समर्थक तेहरान के प्रति उदार माने जाने वाले किसी भी समझौते का विरोध कर रहे हैं, जबकि किसी दूसरे देश में दखल देने के विरोधी लंबे समय से सैन्य हस्तक्षेप पर सवाल उठा रहे हैं। इन सबसे ट्रंप का समर्थक-आधार लंबे समय तक प्रभावित हो सकता है।

हालांकि, इन सब बातों का यह कतई मतलब नहीं है कि समझौता होना तय है। ट्रंप ने खुद बार-बार अपना रुख बदला है। प्रतिबंध, परमाणु गतिविधियां, क्षेत्रीय सुरक्षा आदि से जुड़े कई सवाल अब तक अनुत्तरित हैं। हालांकि, यदि जंग खत्म करने को लेकर वार्ता सफल रहती है, तो निस्संदेह अमेरिका के लिए एक कठिन अध्याय का अंत होने जैसा होगा। एक ऐसा अध्याय, जिससे मध्य-पूर्व में संबंधों को नया रूप मिलेगा।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

हम कुर्बानी के असली पैगाम को कितना समझ पाए

यहां स्कैन करें

एम अफशार आलम | कुलपति, जामिया हमदर्द

ईद-उल-अजहा हजरत इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) की उस महान इबादत और समर्पण की याद दिलाती है, जब वह अल्लाह के हुक्म पर अपने बेटे हजरत इस्माइल (अलैहिस्सलाम) को कुर्बान करने को तैयार हो गए। ईमान, आज्ञाकारिता और अटूट भरोसे की वह महान भावना हर वर्ष कुर्बानी की रस्म के जरिये मुसलमानों द्वारा ताजा की जाती है।

इस्लाम यह शिक्षा देता है कि कुर्बानी का वास्तविक उद्देश्य केवल किसी जानवर की बलि देना नहीं, बल्कि दिल की नीयत, तकवा (आत्म-संयम) और अल्लाह के प्रति निष्ठा है। पवित्र *कुरान* में यह फरमाया गया है: 'अल्लाह तक न उनका मांस पहुंचता है और न ही उनका खून, बल्कि उस तक तुम्हारी पाकीजगी और परहेजगारी पहुंचती है।' इस संदेश को हमें अपने दिल में बसाना चाहिए कि हर इबादत के साथ सद्भावना, इंसानियत के प्रति करुणा तथा सामाजिक व राष्ट्रीय जिम्मेदारी की भावना भी जुड़ी होनी चाहिए। इस त्योहार को जिम्मेदारी से मनाने के लिए देश के हरेक मुसलमान को सरकार द्वारा कुर्बानी के बारे में जारी किए गए नियमों और दिशा-निर्देशों का पूर्ण पालन करना चाहिए। यह हमारे इस्लामी मूल्यों की भी अभिव्यक्ति है। ये दिशा-निर्देश हमसे अपेक्षा करते हैं कि प्रतिबंधित या संरक्षित पशुओं की कुर्बानी न करें। भारत सरकार तथा विभिन्न राज्यों की सरकारों ने पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960, वन्य-जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 व विभिन्न राज्य स्तरीय गो-संरक्षण कानूनों के अंतर्गत कुछ पशुओं को संरक्षित अथवा वध हेतु प्रतिबंधित घोषित किया है। गाय, बछड़े, बैल और सांड़ अधिकांश भारतीय राज्यों में प्रतिबंधित हैं। ऐसे किसी भी पशु की कुर्बानी, जिसे राज्य सरकार या स्थानीय प्रशासन द्वारा संरक्षित घोषित किया गया हो, कानून का उल्लंघन है और इससे आपराधिक कार्रवाई हो सकती है। इस्लाम उस देश के कानूनों के पालन की सीख देता है, जहां आप निवास करते हैं, बशर्ते वे धर्म की मूल शिक्षाओं के विरुद्ध न हों। सभी मुसलमानों को इसका ख्याल रखना चाहिए।

इसी तरह कुर्बानी केवल सरकार द्वारा अनुमोदित बूचड़खानों, निर्धारित स्थलों या स्थानीय निकायों/पंचायतों द्वारा अधिकृत जगहों पर ही की जानी चाहिए। सार्वजनिक सड़कों, गलियों या खुले स्थान पर कुर्बानी करना पूर्णतः प्रतिबंधित है। पशुओं के अवशेष सहित सभी अपशिष्ट का निपटान भी दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाना चाहिए। गंदगी फैलाना या अनुचित ढंग से अवशेष फेंकना जन-स्वास्थ्य के लिए खतरा उत्पन्न करता है और सामाजिक तनाव को बढ़ावा दे सकता है।

भारत विविध धर्मों और परंपराओं का देश है। ऐसे में, हमारा दायित्व है कि हम एक अच्छे पड़ोसी और संवेदनशील नागरिक बनें। अपने पर्व-त्योहारों को इस प्रकार मनाएं कि अन्य धर्म के नागरिकों या मतावलंबियों को कष्ट या असुविधा न हो। एक नागरिक के तौर पर हम इस तथ्य की उपेक्षा नहीं कर सकते कि भारत की महानता उसकी विविधता और बहुलता में निहित है, जहां सदियों से विभिन्न धर्मों, भाषाओं और संस्कृतियों के लोग आपसी सौहार्द के साथ रहते हैं। पवित्र *कुरान* में कहा गया है, 'और धरती में सुधार के बाद उसमें फसाद पैदा मत करो।' (सूरह अल-आराफ, 7:56)

ईद-उल-अजहा को मनाते हुए हम एक ऐसा नागरिक आचरण प्रस्तुत करें, जिससे प्रत्येक भारतीय गौरवान्वित हो।

ईद के हमारे जश्न में इसी ईश्वरीय निर्देश की झलक दिखनी चाहिए- जो व्यवस्थित, सामंजस्यपूर्ण व साथी नागरिक का सम्मान करने वाला हो। एक ऐसी संस्था की नुमाइंदगी करते हुए, जो मानवता की सेवा, शिक्षा और स्वास्थ्य के आदर्शों को समर्पित संस्था है, हम मुस्लिम नागरिकों से यही अपेक्षा करेंगे कि ईद-उल-अजहा मनाते हुए एक ऐसा नागरिक आचरण प्रस्तुत करें, जिससे प्रत्येक भारतीय गौरवान्वित हो।

कुर्बानी की भावना को उदारता में अपनाएं- गरीबों, शैक्षणिक संस्थानों और राष्ट्रीय कल्याण के कार्यों में बढ़-चढ़कर योगदान दें। यह बहुत अच्छी बात है कि इस बार कई मुस्लिम रहनुमाओं ने यह अपील की है कि हमें बहुसंख्यक समुदाय की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। जब ईद-उल-अजहा को हम गरिमा और अनुशासन के साथ मनाते हैं, तब संसार के समक्ष अपने धर्म की सुंदरता का सर्वोत्तम उदाहरण प्रस्तुत करते हैं।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा

आशा को सहेजिए

छह हजार साल पुरानी किताब है चीन में। उसकी भूमिका अगर पढ़ें, तो ऐसा लगता है कि आज सुबह के अखबार का 'एडिटोरियल' है। उसमें लिखा है कि लोग बहुत बिगड़ गए हैं, उनका नैतिक ह्रास हो गया है। लोग भौतिकवादी हो गए हैं, भ्रष्टाचार फैल गया है, कोई किसी की सुनता नहीं, ऐसा लगता है कि महाप्रलय निकट है। वह छह हजार साल पहले की किताब है और उसमें भी लिखा है कि पहले के लोग अच्छे थे।

पहले के लोग अच्छे थे, यह मिथ और कल्पना से ज्यादा नहीं है। असल में, पहले के लोगों को हम भूल चुके हैं और जो थोड़े से लोग हमें याद रह गए हैं, उनके कारण ही सब गड़बड़ होती है। महावीर याद हैं, महावीर के समय का आम आदमी हमें याद नहीं है, तो लगता है कि महावीर के जमाने में सभी लोग अच्छे रहे होंगे। महावीर के जमाने में अगर सब लोग अच्छे होते, तो उनकी हमें याद भी न आती अब तक। महावीर अब तक दिखाई इसीलिए पड़ रहे हैं। स्कूल में काले तख्ते पर सफेद खड़िया से मास्टर लिखते हैं। सफेद दीवार पर लिखें, तो लिख भी सकते हैं, लेकिन दिखाई नहीं पड़ेगा, काले बोर्ड पर दिखाई पड़ता है। महावीर ढाई हजार साल तक दिखाई पड़ते हैं कि एक महापुरुष थे। जब तक समाज का तख्ता ब्लैक-बोर्ड न रहा हो, तब तक ढाई हजार साल तक दिखाई नहीं पड़ सकता कि वह महापुरुष थे। दस-पांच महापुरुष मनुष्य जाति में दिखाई पड़ते हैं। बाकी सारी मनुष्यता एक काले तख्ते की तरह है, जिसके ऊपर लकीरें उभरी हुई दिखाई पड़ती हैं, लेकिन कोई मनुष्यता कभी अच्छी नहीं थी। जितनी अच्छी आज है, उतनी अच्छी भी नहीं थी। हम रोज अच्छाई की तरफ विकास कर रहे हैं।

बस एक धारणा हमारे मन में है कि पतन हो रहा है। पहले सतयुग हो चुका, अब कलियुग है। अब तो पतन ही पतन है। जिस कौम के मन में यह भाव बैठा कि आगे पतन है, उसका पतन निश्चित है, क्योंकि भाव ही गतिमान करते हैं। हम अपने स्वर्ण-युग को पीछे रखे बैठे हैं कि सब अच्छा हो चुका। अब तो सब बुरा होना है। यह हमारा संस्कार बन गया है कि आगे तो और बुरा होना है। जब कोई किसी को छुरा भोंकता है, तो तपाक से कहते हैं, आ गया कलियुग। जब कोई किसी की स्त्री को लेकर भाग जाता है, तो हम कहते हैं, आ गया कलियुग और ऋषि-मुनि लेकर भागते रहे, तब सतयुग था और अब कलियुग आ गया, क्योंकि बगल का कोई आदमी ले गया है।

आदमी रोज अच्छा हो रहा है। अगर भविष्य में अच्छा बनना है, तो स्वर्ण-युग आगे है। भविष्य का निर्माण करना है, तो आशा चाहिए। आशा न हो, तो भविष्य निर्मित नहीं हो सकता।

अजीब बातें हैं। सीता का अपहरण हो गया, तब अच्छी दुनिया थी और अभी किसी रामचंद्र की औरत चोरी चली जाए, तो कलियुग आ गया। नहीं, आदमी रोज अच्छा हो रहा है। अगर भविष्य में अच्छा बनना है, तो स्वर्ण-युग आगे है। भविष्य का निर्माण करना है, तो आशा चाहिए। आशा न हो, तो भविष्य निर्मित नहीं हो सकता।

ओशो

ओम बिरला | अध्यक्ष, लोकसभा

विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाते हुए हम आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकृति को सुरक्षित रखें। जैव विविधता केवल पर्यावरण का विषय नहीं, बल्कि मानव जीवन, खाद्य सुरक्षा, जलवायु संतुलन और सतत भविष्य का आधार भी है।

हिन्दुस्तान Hindustan | 75 साल पहले 28 मई, 1951

बम्बई का मद्य निषेध कानून

बम्बई का मद्य निषेध कानून न्यायालयों की चौखट से सकुशल पार हो गया। उसका भाग्य अभी तक अधर में झूल रहा था। बम्बई की हाईकोर्ट ने सारे कानून को तो अवैध करार नहीं दिया था, किन्तु उसकी कुछ धाराओं को अनियमित ठहराया था। बम्बई हाईकोर्ट के इस निर्णय के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय के सामने दो विरोधी अपील दाखिल की गयी थीं। एक अपील बम्बई सरकार की ओर से पेश की गयी थी, जिसमें बम्बई हाईकोर्ट द्वारा अमान्य ठहरायी गयी धाराओं को नियमित करार देने का अनुरोध किया गया था। दूसरी अपील बम्बई के एक पत्रकार की थी, जिसका कहना था कि बम्बई हाईकोर्ट द्वारा कुछ धाराओं को अनियमित ठहरा देने के बाद सारा ही कानून अनियमित करार दिया जाना चाहिए। इस कानूनी कुश्ती में जीत बम्बई सरकार की ही हुई है और बम्बई के मद्य निषेध कानून को अनियमित ठहराने का प्रयत्न अन्तिम रूप में निष्फल हो गया है।

बम्बई का मद्य निषेध कानून सन् 1949 में स्वीकार किया गया था। उस समय भारत का नया संविधान बनकर तैयार नहीं हुआ था। किन्तु कानून का आधार वही है, जो संविधान की 47वीं धारा में स्वीकार किया गया है। उसमें कहा गया है कि राज्य ऐसे मादक द्रव्यों के सेवन पर रोक लगाने की कोशिश करेगा, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकर है। चिकित्सा कार्यों में ऐसे द्रव्यों के उपयोग की छूट रखी गयी थी। बम्बई की विधानसभा ने यह कानून बना कर संविधान की मूलभूत मंशा को पूरा किया था। मादक पदार्थों का निषेध कांग्रेस कार्यक्रम का भी एक आवश्यक अंग रहा है। महात्मा गांधी ने अंग्रेजी राज को शैतानी राज्य कहा था और उसका एक कारण यह था कि वह मादक द्रव्यों की बिक्री से आमदनी करता था और लोगों के स्वास्थ्य का नाश करने के अलावा उनके नैतिक पतन में भी सहायक होता था।

बम्बई और मद्रास की सरकारों ने मादक पदार्थों के सेवन को वर्जित करने में पूरी दृढ़ता का परिचय दिया है और करोड़ों रुपये की हानि उठाकर मद्य-निवारण संबंधी कांग्रेस कार्यक्रम को कार्यान्वित किया है। कुछ लोगों का कहना है कि रुपये की कमी के कारण राज्य सरकारों को अपनी अनेक लोक हितकारी योजनाओं को स्थगित करना पड़ा है।

पेट्रो पदार्थों के दाम बढ़ाने की मजबूरी

एक बार फिर सीएनजी के दाम बढ़ा दिए गए हैं। सीएनजी ही नहीं, पेट्रोल-डीजल की कीमतें भी लगातार ऊपर उठ रही हैं। यह मूल्य-वृद्धि बताती है कि तेल कंपनियों के लिए इनके दाम स्थिर रख पाना संभव नहीं रह गया है। पेट्रो उत्पादों के दाम इसलिए बढ़ रहे हैं, क्योंकि अमेरिका-ईरान के बीच टकराव के चलते होर्मुज जलमार्ग बाधित है और आपूर्ति श्रृंखलाएं छिन्न-भिन्न हो गई हैं। चूंकि भारत अपनी आवश्यकता का 75 प्रतिशत से अधिक ईंधन आयात करता है, इसलिए उसके सामने पेट्रोल-डीजल-गैस के दाम बढ़ाने के अतिरिक्त और कोई दूसरा उपाय नहीं है। हालांकि, जिस तरह भारत ऐसा करने के लिए मजबूर है, उसी तरह दुनिया के अन्य देशों के सामने भी मजबूरी है। इसकी अनदेखी नहीं होनी चाहिए कि भारत ने दूसरे देशों की तुलना में काफी समय बाद पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़ाए। पेट्रोल-डीजल और गैस के बढ़ते दामों के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जिस तरह यह कहा कि तेल, उर्वरकों और विदेशी मुद्रा पर कड़ी निगाह रखने की जरूरत है, उसके अनुरूप सरकार को काम करना ही होगा। हां, आम जनता इतना अवश्य कर सकती है और उसे यह करना भी चाहिए कि वह संयम बरते और उन उपायों पर ध्यान दे, जो सरकार और विशेष रूप से प्रधानमंत्री की ओर से सुझाए गए हैं।

विभूति बुपक्या, टिप्पणीकार

वर्तमान में पेट्रोलियम पदार्थों में की गई मूल्य-वृद्धि कोई आंतरिक या नीतिगत विफलता नहीं है, बल्कि यह एक वैश्विक संकट का अनिवार्य परिणाम है। इस कठिन समय में देश को आर्थिक रूप से स्थिर बनाए रखने के लिए सरकार की प्रशासनिक दृढ़ता, विपक्ष के परिपक्व रवैये और आम जनता के संयम की बेहद जरूरत है। तेल कंपनियों द्वारा कीमतों को स्थिर रख पाना अब व्यावहारिक नहीं रह गया है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में होने वाली मामूली हलचल भी भारतीय अर्थव्यवस्था को सीधे तौर पर प्रभावित करती है। जब वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बाधित होती है, तो घरेलू बाजार में दाम बढ़ाना सरकार और तेल कंपनियों के लिए एक अपरिहार्य मजबूरी बन जाती है। साफ है, यह समय घबराहट का नहीं, बल्कि संतुलित नीति, जिम्मेदार उपभोग और दीर्घकालिक ऊर्जा-आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ने का है। केवल नागरिकों से किफायत की अपेक्षा पर्याप्त नहीं होगी। सरकारों की भी समान जिम्मेदारी बनती है। वे मूल्य नियंत्रण के साथ-साथ वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के विस्तार, सार्वजनिक परिवहन की मजबूती और आयात पर निर्भरता घटाने के भी उपाय करें।

युगल किशोर राही, टिप्पणीकार

अनुलोम-विलोम

पेट्रो पदार्थों की कीमतें

नीतिगत विफलता की भी चर्चा करिए

तेल कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल और गैस के दामों में चार बार बढ़ोतरी करके सामान्य जन की कमर तोड़ दी है। पेट्रो पदार्थों की मूल्य-वृद्धि का सीधा असर यातायात के साधनों, बाजार और आम आदमी के घरेलू बजट पर पड़ता है, वह भी विशेषकर निम्न और मध्यमवर्गीय परिवारों पर। अगर आय के साधनों और खर्च के बीच समन्वय हो, तो महंगाई का यदा-कदा बढ़ना नहीं अखरता, लेकिन अभी गैस के दामों में बेतहाशा वृद्धि के साथ-साथ डीजल व पेट्रोल के दाम भी बार-बार बढ़ाए गए हैं, जिससे आम आदमी के सम्मुख अपने अस्तित्व को बचाए रखने का संकट खड़ा हो गया है। कहना गलत न होगा कि पेट्रोलियम पदार्थों की बिक्री केंद्र और राज्य सरकारों की कमाई का बड़ा जरिया हैं। यदि ऐसा न होता, तो केंद्र व राज्य सरकारें जनहित में टैक्स को कम करके जनसाधारण को महंगाई से कुछ हद तक निजात दिला सकती थीं। किंतु, ऐसा नहीं हो रहा। विडंबना यह भी है कि सड़कों पर महंगाई का विरोध करने वाले विपक्षी दलों के नेतृत्व में चल रही राज्य सरकारों ने भी दूसरे राज्यों की तरह टैक्स वसूलना जारी रखा है। कहीं-कहीं तो यह ज्यादा ही है, जिस कारण उन राज्यों में पेट्रोलियम पदार्थों के दाम तुलनात्मक रूप से अधिक हैं। किसी भी कल्याणकारी राज्य में जनता सर्वोपरि मानी जाती है, लेकिन आम आदमी अपनी जीवनचर्या को तभी बिना किसी अतिरिक्त व्यवधान के गतिशील बनाए रख सकता है, जब सरकारें लोगों की सहूलियत पर ध्यान दें। जरूरी वस्तुओं के दामों और महंगाई को नियंत्रित करना आवश्यक है, तभी आम आदमी को महंगाई से राहत मिल सकती है। इसके लिए सरकारों को प्रयास करना ही चाहिए।

सुधाकर आशावादी, टिप्पणीकार

भारत जैसे देश में सरकारें अपनी कमियों पर शायद ही ध्यान देती हैं। वे तो इसी ताक में रहती हैं कि आरोप किसी दूसरे पर मढ़ दिया जाए, जिस तरह अभी पेट्रोलियम पदार्थों में की जा रही मूल्य-वृद्धि का ठीकरा विदेशी घटनाक्रमों पर फोड़ा जा रहा है। जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम कम थे, तब आम जनता को राहत नहीं दी गई, लेकिन अब जब दाम बढ़ गए हैं, तो यह कहकर अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ा जा रहा है कि यह तो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के बाधित होने का दुष्परिणाम है। जब अच्छे वक्त में कंपनियों ने फायदा कूटा, तो बुरे वक्त में आम लोगों को क्यों परेशान किया जा रहा है? इस वक्त कंपनियों से ही घाटे की भरपायी होनी चाहिए थी। ऐसा हो तो नहीं रहा है, अलबत्ता आम जनता पर महंगाई का बोझ डाला जा रहा है।

पूनम कुमारी, टिप्पणीकार

कॉलेज में दाखिले की कितनी तैयारी

केंद्रीय विश्वविद्यालयों समेत कई राज्य, डीम्ड और निजी विश्वविद्यालयों में स्नातक दाखिले का आधार बन चुकी सीयूईटी (यूजी) परीक्षा अब अंतिम चरण में है। इसके साथ ही लाखों अभ्यर्थियों के सामने अगली चुनौती काउंसिलिंग व चॉइस फिलिंग की होगी। अब अच्छा स्कोर ही नहीं, सीट आवंटन प्रक्रिया, पात्रता नियम एवं अपग्रेड विकल्पों की समझ भी उनके लिए बेहद अहम होगी। जरूरी जानकारी दे रही हैं अनामिका चौहान

सीयूईटी -यूजी, (कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट- अंडरग्रेजुएट) 2026 परीक्षा का आयोजन 31 मई तक किया जा रहा है। बीए, बीकॉम, बीएससी समेत विभिन्न पारंपरिक स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए आयोजित इस परीक्षा में इस बार अभ्यर्थियों को अधिकतम पांच विषय चुनने का अवसर दिया गया है। इस कारण कुल 67.56 लाख से अधिक टेस्ट आयोजित किए जा रहे हैं और औसतन प्रत्येक विद्यार्थी चार से अधिक विषयों की परीक्षा दे रहा है। ऐसे में स्पष्ट है कि इस बार दाखिले को लेकर प्रतिस्पर्धा काफी तीव्र रहने वाली है।

काउंसलिंग प्रक्रिया समझें

सीयूईटी के परिणामों के आने के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सटी, जेएनयू आदि कई विश्वविद्यालय अपनी-अपनी काउंसलिंग और सीट अलॉटमेंट प्रक्रिया चलाते हैं। काउंसलिंग छात्रों को विश्वविद्यालयों की समय-सीमा, रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया और विभिन्न चरणों, जैसे कि स्पॉट राउंड को समझने में मदद करती है। काउंसलिंग प्रक्रिया में काउंसलर से छात्रों को अपनी योग्यता और दीर्घकालिक लक्ष्यों के अनुसार सही कोर्स चुनने में मार्गदर्शन मिलता है। इस दौरान दस्तावेज सत्यापन, फीस भुगतान और एडमिशन प्रक्रिया में होने वाली गलतियों से बचाव पर सलाह भी मिलती है।

सोच-समझकर तय करें कोर्स : दिल्ली विश्वविद्यालय में डीन एडमिशन प्रो. हनीत गांधी के अनुसार विद्यार्थियों को पहले कोर्स की प्राथमिकता तय करनी चाहिए और इसके बाद स्कोर के अनुरूप कॉलेजों का चयन करें। वहीं, चॉइस फिलिंग के मामले में दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय के उपकुलसचिव व एकेडमिक कुमार कौशल बताते हैं, 'विश्वविद्यालय में उपलब्ध 24 स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले सीयूईटी-यूजी 2026 के आधार पर किए जाएंगे।'

उनके अनुसार काउंसलिंग के दौरान विद्यार्थी संबंधित विश्वविद्यालयों की पात्रता शर्तों और प्रवेश नियमों को पहले अच्छी तरह समझ लें, क्योंकि अलग-अलग संस्थानों में इनमें भिन्नता हो सकती है।

छात्रों के सवाल और समाधान

1. सभी कॉलेजों में स्नातक दाखिले के लिए सीयूईटी-यूजी जरूरी है?
नहीं। देश की सभी 48 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन कोर्स में दाखिले के लिए सीयूईटी-यूजी की शुरुआत की गयी थी, जिसके बाद अनेक विश्वविद्यालय,डीम्ड यूनिवर्सिटी एवं अन्य शिक्षण संस्थानों ने इसके स्कोर पर दाखिला लेना प्रारंभ किया। कई विश्वविद्यालय अब भी अपनी अलग प्रवेश प्रक्रिया अपनाते हैं।

2. बारहवीं में ड्रॉप इयर के बाद भी सीयूईटी-यूजी दे सकते हैं?
हां। सीयूईटी-यूजी में अधिकतम आयु सीमा नहीं है, इसलिए बारहवीं के बाद ड्रॉप इयर लेने पर भी आप परीक्षा दे सकते हैं।

3. क्या हिंदी में परीक्षा दी जा सकती है?
हिंदी व अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं में यह परीक्षा दे सकते हैं।

4. क्या परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी होती है?
हां। आपके प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक मिलेंगे और गलत उत्तर के 1 अंक कटेंगे।

5. इसके माध्यम से प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों में दाखिला मिलता है?
कई कॉलेज सीयूईटी-यूजी के आधार पर बीसीए, बीबीए, बीजेएमसी और बीफार्मा में दाखिला देते हैं।

7. यदि किसी छात्र ने 10+2 में इम्प्रूवमेंट या री-अपियारिंग के लिए फॉर्म भरा है, तो क्या वह सीयूईटी-यूजी में बैठ सकता है?
यदि पुराने रिजल्ट में वह 'पास' है, तो उस आधार पर बैठ सकता है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि उसके अंक कितने थे।

– **आशीष आदर्श**, करियर सलाहकार

जरूरी सावधानी

सीएसएएस और काउंसलिंग प्रक्रिया
सीयूईटी के बाद एडमिशन सीएसएएस (कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम) के जरिए होता है, जहां छात्र यूनिवर्सिटी और कोर्स की प्रेफरेंस भरते हैं। सीट अलॉटमेंट कई राउंड्स में होता है, जैसे फ्रीज (सीट पक्की करना) और फ्लोट (बेहतर विकल्प के लिए अपग्रेड का मौका लेना)। काउंसलिंग के समय बारहवीं की मार्कशीट, कैटेगरी, आईडी प्रूफ आदि दस्तावेज पहले से तैयार रखना जरूरी है।

स्ट्रीम स्विच
साइंस या कॉमर्स से 12वीं करने के बाद अब आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज लेना चाहते हैं, तो कुछ यूनिवर्सिटी में इसकी अनुमति है। हालांकि, टॉप यूनिवर्सिटी जैसे डीयू में बारहवीं के विषयों के आधार पर सीयूईटी के विषय होना जरूरी होता है। स्ट्रीम बदलने से कोर्स विकल्प बढ़ते हैं, लेकिन सही विषय चयन न होने पर मौके सीमित हो सकते हैं।

अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी है लक्ष्य : दिल्ली विश्वविद्यालय यानी डीयू में दाखिले के लिए केवल सीयूईटी (यूजी) 2026 का स्कोर ही पर्याप्त नहीं है। आवेदक का बारहवीं में उस विषय का अध्ययन करना भी जरूरी है। सीयूईटी आवेदन के अलावा कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम (सीएसएएस-यूजी) के तहत अलग से आवेदन करना होगा। इसी आवेदन के आधार पर दाखिले का अवसर प्रदान किया जाएगा। दाखिले से जुड़ी सभी जानकारी डीयू की एडमिशन वेबसाइट **admission.uod.ac.in** पर दी गई है।

अपने विषय और करियर को लेकर स्पष्टता होना भी जरूरी है। जैसे मुजफ्फरपुर के हिमांशु बताते हैं कि उनकी रुचि शुरू से मीडिया, कानून और हिंदी पत्रकारिता में थी, इसलिए उन्होंने 12वीं में ह्यूमैनिटीज चुनी। ओपन स्कूल से मास कॉम और इंट्रोडक्शन टु लॉ में डिप्लोमा भी किया। सीयूईटी की तैयारी में सामान्य ज्ञान, करेंट अफेयर्स और बेसिक गणित पर ध्यान दिया। अच्छे अंकों के साथ परीक्षा पास करने के बाद डीयू की प्रेफरेंस लिस्ट में डॉ. भीमराव अंबेडकर कॉलेज को पहली पसंद रखा और पहले ही राउंड में चयन हो गया। बाद में बीएचयू में बीए एलएलबी में भी चयन हुआ।

संस्थान चयन में सावधानी : सीयूईटी-यूजी में छात्रों को अपने स्कोर के आधार पर संस्थान चुनने का अवसर मिलता है, इसलिए सावधानी जरूरी है। विशेषज्ञों के अनुसार पिछले साल के कट-ऑफ पर निर्भर रहना सही नहीं है, क्योंकि यह हर साल बदलता रहता है। छात्र अपनी रुचि के अनुसार कोर्स और संस्थान का चयन रैंकिंग, पढ़ाई व सुविधाओं को ध्यान में रखकर करें।

किन संस्थानों में दाखिला

सीयूईटी (यूजी) के माध्यम से कई केंद्रीय, राज्य स्तरीय, डीम्ड विश्वविद्यालय स्नातक में दाखिले लेते हैं। इनमें प्रमुखतः डीयू, जेएनयू, बीएचयू, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय और टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान आदि शामिल हैं।

एस्ट्रोफिजिक्स के लिए 12वीं में पीसीएम जरूरी

एक्सपर्ट टिप्स

डॉ. संजीब कुमार आचार्य
सीनियर करियर काउंसलर

■ **मैं दसवीं का छात्र हूं। एस्ट्रोफिजिक्स में करियर बनाना चाहता हूं। कृपया इस क्षेत्र की विस्तृत जानकारी दें। मुझे कौन-कौन से विषय चुनने चाहिए और कौन से कॉलेज यह कोर्स कराते हैं? –अथर्व उपाध्याय**

एस्ट्रोफिजिक्स में अंतरिक्ष, तारे, ब्लैक होल, ग्रह, आकाशगंगाएं और ब्रह्मांड की उत्पत्ति का अध्ययन किया जाता है। इसमें फिजिक्स, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस और एस्ट्रोनॉमी की मजबूत समझ जरूरी होती है। आपके लिए 11वीं और 12वीं में सबसे उपयुक्त स्ट्रीम नॉन-मेडिकल साइंस है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथेमेटिक्स (पीसीएम) शामिल होते हैं। एस्ट्रोफिजिक्स में गणित और रिसर्च का बहुत अधिक उपयोग होता है, इसलिए फिजिक्स और मैथेमेटिक्स महत्वपूर्ण विषय हैं। साथ ही कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, खासकर पाइथन सीखना, भविष्य में रिसर्च, डाटा एनालिसिस और सिमुलेशन्स के लिए काफी उपयोगी साबित होता है।

12वीं के बाद आप बीएससी फिजिक्स, इंटीग्रेटेड एमएससी फिजिक्स या एस्ट्रोनॉमी जैसे कोर्स कर सकते हैं। दूसरा रास्ता इंजीनियरिंग फिजिक्स, एयरोस्पेस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस में बीटेक करने का भी है, जिसमें स्पेस रिसर्च से जुड़ी पढ़ाई की जा सकती है। भारत में एस्ट्रोफिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी की पढ़ाई के लिए प्रमुख संस्थानों में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, इंटर-यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च शामिल हैं। इन संस्थानों में प्रवेश के लिए जेईई एडवांस्ड, आईआईएसईआर एप्टीट्यूड टेस्ट, एनईएसटी और सीयूईटी जैसी परीक्षाओं की गंभीर तैयारी करनी होती है।

■ **मेरा बेटा बीटेक करना चाहता है, लेकिन उसने 12वीं में बायोलॉजी ली थी, मैथ्स नहीं। क्या वह बाद में सिर्फ मैथ्स की परीक्षा देकर इंजीनियरिंग में दाखिला ले सकता है? – सुमन मिश्रा**

हां, यह संभव है, लेकिन अधिकांश बीटेक कोर्स में 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथेमेटिक्स (पीसीएम) जरूरी होते हैं। इसलिए आपके बेटे को मैथेमेटिक्स की योग्यता पूरी करनी होगी। इसके लिए वह 12वीं के बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग (एनआईओएस) या किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से अतिरिक्त विषय के रूप में मैथेमेटिक्स ले सकता है। ऐसा करने के बाद वह जेईई मेन जैसी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाएं दे सकता है और बीटेक में प्रवेश के लिए आवेदन कर सकता है। कुछ विश्वविद्यालय और निजी संस्थान पीसीबी छात्रों को भी बायोटेक्नोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस जैसे चुनिंदा बीटेक कोर्स में प्रवेश देते हैं। हालांकि, हर कॉलेज के प्रवेश नियम अलग-अलग होते हैं। यदि आपके बेटे की इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में वाकई रुचि है, तो मैथेमेटिक्स जोड़ना फायदेमंद रहेगा। इससे इंजीनियरिंग की अधिक शाखाओं और करियर निर्माण के रास्ते खुलेंगे। साथ ही उसे मैथेमेटिक्स और प्रोग्रामिंग की तैयारी भी धीरे-धीरे मजबूत करनी चाहिए।

www.sanjibacharya.com

हिन्दुस्तान क्विज-7

हिन्दुस्तान अर्थात भारत की विकास यात्रा बहुआयामी रही है। इसी महायात्रा से हम पाठकों के लिए कुछ प्रश्न लेकर आए हैं, जो सामान्य ज्ञान के लिए उपयोगी हैं। पेश हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी पार्थ सारथी सेन शर्मा के दस सवाल और उनके जवाब...

1. महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग कांड के विरोध में किस उपाधि/सम्मान को अंग्रेजी सरकार को वापस किया था?
2. हिंदुस्तान की पहली महिला अधिवक्ता कौन थीं?
3. 'हिंदू महासभा' के अधिवेशन की अध्यक्षता केवल एक बार किसी मुस्लिम महानुभाव द्वारा हुई थी। वह कौन थे?
4. हिंदुस्तान में एक तैरता हुआ डाकघर कहां स्थित है?
5. किस हिंदुस्तानी ने कालाजार बीमारी, जिससे हर साल हजारों लोगों की जान जाती थी, की रोकथाम के लिए दवाई का आविष्कार किया था?
6. आज तक कलकत्ता यूनिवर्सिटी के सब से कम उम्र (33 साल) में कुलपति होने का श्रेय किस हिंदुस्तानी को जाता है?
7. हिंदुस्तान में स्थित कौन-सी जगह व्हाइट टाइगर के लिए विश्व प्रसिद्ध है?
8. हिंदुस्तान की प्रसिद्ध कार 'एम्बेसडर' किस विदेशी कार के मॉडल पर बनाई गई थी?

9. हिंदुस्तान के कौन से शहर को 'मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट' के नाम से भी जाना जाता था?
10. हिंदुस्तान के किस शहर को 'पूरब का शिराज' ईरान के प्रसिद्ध शहर शिराज के नाम पर कहा जाता था?

उत्तर : 1. कैसर ए हिन्द मेडल 2. कार्नेलिया सोराबजी 3. हकीम अजमल खान 4. डल झील, श्रीनगर 5. सर उपेन्द्रनाथ ब्रह्मचारी 6. डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने बहुत साल बाद भारतीय जन संघ की स्थापना की थी 7. रीवा, मध्य प्रदेश 8. मॉरिस ऑक्सफोर्ड 9. कानपुर 10. जौनपुर, उत्तर प्रदेश

जॉब/करिअर

■ संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित कंबाइन्ड डिफेंस सर्विसेज इग्जामिनेशन (II), 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन किए जा रहे हैं।
कुल पद : 451
अंतिम तिथि : 09 जून 2026
आवेदन प्रक्रिया : ऑनलाइन वेबसाइट **-upsc.gov.in** पर आवेदन करें।

■ रेलवे भर्ती बोर्ड (रेल मंत्रालय), में असिस्टेंट लोको पायलट के पदों पर आवेदन मांगे गए हैं।
कुल पद : 11,127
अंतिम तिथि : 14 जून 2026
आवेदन प्रक्रिया : बोर्ड की वेबसाइट है- **rrbapply.gov.in**

■ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने कंबाइन्ड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन, 2026 के लिए अधिसूचना जारी की है। इसके तहत ऑडिटर समेत विभिन्न पद भरे जाएंगे।
कुल पद : 12,256
अंतिम तिथि : 22 जून 2026
आवेदन प्रक्रिया : ऑनलाइन करना होगा। इस वेबसाइट **ssc.gov.in** पर जाएं।

■ भारतीय स्टेट बैंक में ट्रेड फाइनेंस ऑफिसर की नियुक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन का मौका है।
कुल पद : 100
अंतिम तिथि : 02 जून 2026
आवेदन प्रक्रिया : बैंक की वेबसाइट है- **sbi.bank.in**

■ एडसिल (इंडिया) लिमिटेड में ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, स्पेशल एजुकेटर समेत अन्य पद रिक्त हैं।
कुल पद : 879
अंतिम तिथि : 04 जून 2026
आवेदन प्रक्रिया : ऑनलाइन। वेबसाइट है- **edcilindia.co.in**

■ हाथरस जिला, उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकत्री के पद भरे जाएंगे। महिला अभ्यर्थी ही आवेदन की पात्र होंगी।
कुल पद : 229
अंतिम तिथि : 04 जून 2026
आवेदन प्रक्रिया : संबंधित वेबसाइट है- **upanganwadibharti.in**

■ पंजाब एंड सिंध बैंक में अप्रेंटिस की रिक्तियां भरी जाएंगी। प्रशिक्षण अवधि 12 माह होगी।
कुल पद : 635
अंतिम तिथि : 06 जून 2026
आवेदन प्रक्रिया : बैंक की वेबसाइट है- **punjabandsind.bank.in**

■ कोल इंडिया लिमिटेड में मैनेजमेंट ट्रेनी के पद रिक्त हैं। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
कुल पद : 660
अंतिम तिथि : 11 जून 2026
आवेदन प्रक्रिया : वेबसाइट है – **coalindia.in**

(नोट : आवेदन करने से पहले आधिकारिक वेबसाइट से अपने स्तर पर जांच कर लें)

भेजें अपना सवाल

करियर या शैक्षिक कोर्स संबंधी आपके मन में कोई उलझन है या कोई जानकारी चाहते हैं, तो आप हमें अपने सवाल नीचे दी गई ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे विशेषज्ञ उसके जवाब देंगे। इस ईमेल आईडी का उपयोग करें **nayiraheincareer@gmail.com**

रोजनामचा

पं. राघवेन्द्र शर्मा
ज्योतिषाचार्य

मेष : आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। मन प्रसन्न रहेगा। माता की सेहत में सुधार होगा। कारोबार में भागदौड़ अधिक बढ़ेगी। लाभ के अवसर मिलेंगे। सेहत का ध्यान रखें।

वृष : मन परेशान रहेगा। आत्मविश्वास में कमी रहेगी। जीवनसाथी की सेहत का ध्यान रखें। माता का सान्निध्य मिलेगा। नौकरी में कार्यक्षेत्र में बदलाव हो सकता है।

मिथुन : आत्मविश्वास में कमी रहेगी। मन में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं। धैर्यशीलता बनाए रखने का प्रयास करें। नौकरी में कार्यक्षेत्र में वृद्धि के साथ स्थान परिवर्तन हो सकता है।

कर्क : आत्मविश्वास तो भरपूर रहेगा, परंतु मन अशांत रह सकता है। घर-परिवार में धार्मिक कार्य हो सकते हैं। भवन की साज-सज्जा एवं वस्त्रों पर खर्च बढ़ेंगे।

सिंह : आत्मविश्वास से लबरेज रहेंगे। कारोबार में वृद्धि होगी। भागदौड़ भी अधिक रहेगी। लाभ के अवसर मिलेंगे। भवन सुख में वृद्धि हो सकती है। माता-पिता का साथ मिलेगा।

कन्या : आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। वाणी में मधुरता रहेगी, परंतु मन परेशान हो सकता है। आत्मसंयत रहें। परिवार का साथ मिलेगा। कारोबार में वृद्धि होगी।

तुला : मन परेशान रहेगा। आत्मसंयत रहें। व्यर्थ के क्रोध एवं विवाद से बचें। धार्मिक कार्यों में व्यस्तता बढ़ सकती है। मीठे खान-पान में भी रुचि बढ़ सकती है।

वृश्चिक : मन परेशान रहेगा। परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थान पर जा सकते हैं। भागदौड़ अधिक रहेगी। वाहन के रखरखाव और वस्त्रों पर खर्च बढ़ सकते हैं।

धनु : आत्मविश्वास से परिपूर्ण रहेंगे। संतान सुख में वृद्धि होगी। परिवार में धार्मिक कार्य हो सकते हैं। भागदौड़ भी अधिक रहेगी। सेहत के प्रति सचेत रहें।

मकर : आत्मसंयत रहें। धैर्यशीलता बनाए रखने का प्रयास करें। कारोबार में वृद्धि होगी। किसी मित्र का सहयोग मिल सकता है। लाभ के अवसर भी मिलेंगे।

कुंभ : शैक्षिक कार्यों में सफल रहेंगे। बौद्धिक कार्यों से आय में वृद्धि हो सकती है। कला और संगीत के प्रति रुझान बढ़ सकता है। नौकरी में कार्यक्षेत्र में वृद्धि हो सकती है।

मीन : आत्मसंयत रहें। व्यर्थ के क्रोध एवं वाद-विवाद से बचें। संतान की सेहत का ध्यान रखें। किसी मित्र के सहयोग से कारोबार में वृद्धि हो सकती है।

स्कैन करें
भविष्यफल और व्रत-त्योहार जानने के लिए

व्रत और त्योहार । पंचांग | पं. ऋषिकांत गोस्वामी

28 मई, गुरुवार, **शक संवत्:** 07, ज्येष्ठ (सौर) 1948 **पंजाब पंचांग:** 14, ज्येष्ठ मास प्रविष्टे 2083 **इस्लाम:** 10, जिल्हिजा, 1447, **विक्रमी संवत:** प्रथम (अधिक) ज्येष्ठ शुक्ल द्वादशी तिथि प्रातः 07.58 मिनट तक पश्चात त्रयोदशी तिथि, चित्रा नक्षत्र प्रातः 08.09 मिनट तक पश्चात स्वाती नक्षत्र, वरीयान योग रात्रि 03.55 मिनट तक पश्चात परिघ योग, चन्द्रमा तुला राशि में (दिन रात)
सूर्य उत्तरायण। सूर्य उत्तर गोल। ग्रीष्म ऋतु। दोपहर 01.30 मिनट से अपराह्न 03 बजे तक राहुकालम्। प्रदोष व्रत।

वास्तु सलाह । आचार्य मुकुल रस्तोगी

कृपया यह बताएं कि दक्षिण पश्चिम दिशा में अंडरग्राउंड वाटर टैंक, स्विमिंग पूल तथा बोरिंग करवाने के क्या परिणाम होते हैं। – निधि सुमन, मेरठ

■ दक्षिण-पश्चिम दिशा में बोरिंग हो, तो घर के मुखिया पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, आर्थिक स्थिति और निर्णय लेने की क्षमता भी बहुत कमजोर हो सकती है।
■ इस दिशा में स्विमिंग पूल हो, तो बाहरी रिश्तों पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मानसिक बेचैनी रहती है। इनको उत्तर, उत्तर पूर्व दिशा में बनाना चाहिए। यदि इनको न हटा पाएं, तो इस दिशा को भारी एवं ऊंचा करें।
■ यहां पर लाइटिंग का समुचित प्रबंध करें और भूमि से संबंधित रंग की वस्तुएं रखें।

वर्ग पहेली : 8342

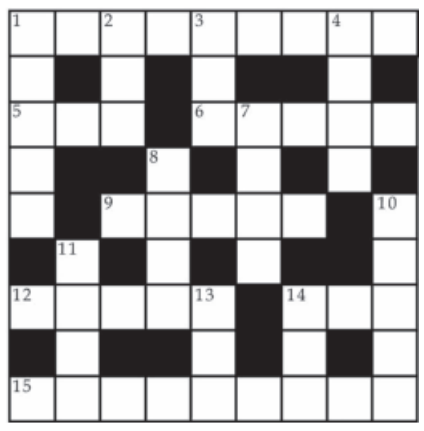

बाएं से दाएं
1. बहुत अधिक दावेदार होने की स्थिति; वस्तु एक चाहने वाले अनेक (2,3,1,3)
5. उमंग; हिलोर; तरंग; मौज; रह रहकर उठने वाला दर्द (3)
6. पूरे जोर के साथ कुछ करने के लिए कहना; वास्ता देना; सौगंध देना (3,2)
9. चमकीला; भड़कीला (5)
12. अचेत; बेहोश; संज्ञाहीन; सुधहीन; स्मृतिहीन (5)
14. आघात; धक्का; चोट (3)
15. दोनों पक्षों का बराबर होना (3,4,2)

ऊपर से नीचे
1. एड़ देना; वेगपूर्वक भगाने के लिए घोड़े के पेट पर एड़ी से आघात करना (2,3)
2. जिसके पास बहुत संपत्ति हो; उदार; दौलतमंद; संपन्न; कार्याधिकार रखने वाला; सरदार (3)
3. आनंद लेने वाला; काव्य मर्मज्ञ; रसिया; प्रेमी (3)
4. किसी काम के लिए स्वेच्छापूर्वक दिया गया पारिश्रमिक; किसी सेवा के लिए सादर दिया जाने वाला धन; सम्मानपूर्वक दी गई राशि (4)
7. नायक; अमीर; नेता (4)
8. संगी; साथ चलने वाले; सहयात्री (4)
10. इच्छा रोकना; उदास होना (2,3)
11. व्याकरण में क्रिया का एक काल; बीता हुआ काल; बीता हुआ समय (4)
13. चोचला; दिखावटी इनकार; नाज; रूप अभिमान; हाव-भाव (3)
14. झोंका; बयार; बहती हवा; वायु; पवन (3)

हरीश चन्द्र सन्सी, विविधा विधा, दिल्ली
(उत्तर अगले अंक में)

वर्ग पहेली : 8341

सुडोकू : 8324 *आसान

4			2			8		
	5		6					
	1	2			8	4		7
				6			7	4
		1		5		9		
3	8			4				
2		3	4			7	9	
					5		3	
		5			6			1

खेलने का तरीका : दिमागी खेल और नंबरों की पहेली है यह। ऊपर नौ-नौ खानों के नौ खाने दिए गए हैं। आपको 1 से 9 की संख्याएं इस तरह लिखनी हैं कि खड़ी और पड़ी लाइनों के हरेक खाने में 1 से 9 की सभी संख्याएं आएं। साथ ही 3×3 के हरेक बक्से में भी 1 से 9 तक की संख्याएं हों। पहेली का हल हम कल देंगे।

सुडोकू : 8323

9	7	8	3	2	1	5	6	4
3	2	6	9	4	5	1	7	8
5	1	4	6	8	7	3	2	9
7	9	2	4	1	3	8	5	6
1	6	5	2	9	8	7	4	3
8	4	3	7	5	6	2	9	1
4	8	7	1	6	2	9	3	5
2	5	9	8	3	4	6	1	7
6	3	1	5	7	9	4	8	2

Last Day To Join Private Channel.
Closing entry for new members Now.

♦ **Indian Newspaper**

1) Times of India
2) The Hindu
3) Business line
4) The Indian Express
5) Economic Times
And more Newspapers

♦ **InternationalNewspapers channel**

[Europian, American, Gulf & Asia]

♦ **Magazine Channel**

National & International

[Genaral & Exam related]

♦ **English Editorials**

[National + InternationalEditorials]

Click here to join

♦ Lifetime validity at just 19 Rupees 📍

Trust me... this will be your best purchase of 2026